R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 । अंक : 07
01 से 15 जनवरी 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

रघुपति राघव राजा राम
सज गया अयोध्या धाम

कहीं के पत्थर, कहीं की लकड़ी, कहीं के कारीगरों ने तैयार किया भव्य मंदिर

22 जनवरी को 84 सेकेंड में खत्म होगा भारतीयों के सालों का इंतजार

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_0/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

प्रशासनिक

8 | अब होगी प्रशासनिक जमावट...

मप्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद अब प्रशासनिक जमावट की कवायद तेज होगी। माना जा रहा है कि इसी महीने सरकार मंत्रालय-पीएचक्यू से लेकर मैदानी स्तर तक तबादले कर सकती है। सूत्रों का कहना है...

राजपथ

10-11 | अबकी बार सभी 29...

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी मात देने के बाद अब भाजपा का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर है। भाजपा की नई रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी तैयारी...

तहकीकात

18 | कहीं जीएम फल तो नहीं खा रहे...

अगर आप भी विदेशी यानी आयातित फल और सब्जियों के प्रति आकर्षित हैं और उसका उपभोग करते हैं तो सावधान होने की जरूरत है। भारत में सिर्फ आयातित प्रोसेस्ड फूड ही नहीं बल्कि आयात होने वाले ताजा फलों और सब्जियों में भी...

घपला

20 | किसानों की मौत पर...

कर्जदार किसानों की मौत हो गई, लेकिन बैंक अफसरों ने उन पर रहम नहीं किया। अफसरों ने उनके खातों की लोन लिमिट बढ़ाई और खुद पैसा निकाल लिया। ऐसा एक या दो नहीं, बल्कि 17 मृत किसानों के साथ हुआ है। ये कहानी बैतूल के घोड़ाडोंगरी की है। यहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अफसरों...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

प्रभु श्रीराम का मंदिर करोड़ों हिंदुओं का सपना है, जो अब साकार होने जा रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान श्रीराम की प्राण-प्रतिष्ठा होते ही ये सपना पूरा हो जाएगा। लोगों के दिलों में बसने वाले भगवान श्रीराम का अयोध्या में भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, जिसकी केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया में धूम है। अयोध्या में बने इस मंदिर की अपनी ही एक भव्यता है, जिसे केवल एक शहर नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष ने अपना योगदान दिया है।

राजनीति

30-31 | चौबीस का चेहरा

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पांचों चुनावी राज्यों के बहाने लोकसभा की राह तैयार कर रही थी लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपना चेहरा सामने रखकर बड़ा दांव चल दिया, अब सवाल है कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस और उसकी छतरी के नीचे बिखरता इंडिया गठबंधन...

महाराष्ट्र

37 | इलेक्शन मोड में सरकार

यह साल भी हर साल की तरह गुजरने वाला है। 2024 चुनावों के नजरिये से बड़ी हलचल वाला होने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद अक्टूबर के आसपास महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट, भाजपा और राष्ट्रीय...

बिहार

40 | राजनीति को नई दिशा देने बेताब

अब से ठीक तीन साल पहले बिहार में बदलाव को लेकर जिन चार चेहरों में होड़ लगी हुई थी, उनमें दो चेहरे तो अब भी दमखम के साथ मैदान में डटे हैं। तीसरा जनता को जागरूक करने के अभियान में जुटा है। पर, चौथा चेहरा सियासत के दांव-पेंच...

6 -7 अंदर की बात
40 बिहार
41 पड़ोस
43 अध्यात्म
44 कहानी
45 खेल
46 व्यंग्य

अपनी बात

उम्मीदों का नया वर्ष...

कवि हरिवंशराय बच्चन की एक कविता है...

हुई बहुत दिन खेल मिचौनी, बात यही थी निश्चित होनी,
आओ, सदा दुखी रहने का जीवन में आदर्श बना लें!

नए संकल्पों और नई उम्मीदों के साथ हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। जहां 2023 का साल कभी गम, कभी खुशी में बीता तो इस साल भी बहुत कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। 2024 में कई ऐसी घटनाएं होने वाली हैं, जिन पर हर भारतवासी की नजर रहेगी। जहां लोकसभा चुनाव में जनता अपने पांच वर्षों का भविष्य तय करेगी तो वहीं साल की शुरुआत में ही राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इसके अलावा खेल, सिनेमा और विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत कुछ होने वाला है। राम मंदिर का उद्घाटन इस साल की ऐसी घटना होगी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। जिस राम मंदिर के लिए दशकों तक लंबी कानूनी लड़ी गई, वो मंदिर अब आकार ले रहा है। अयोध्या में बन रहे विराट मंदिर के पहले चरण का कार्य पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इससे पहले 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, जिसमें भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। इस साल के सबसे बड़े घटनाक्रमों में आम चुनाव जरूर गिना जाएगा। मार्च के शुरुआत या मध्य में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। जहां देश में नौ साल से अधिक वर्षों से सत्ता में काबिज भाजपा तीसरी पारी खेलनी की उम्मीद करेगी, तो वहीं दूसरी ओर संभावित इंडिया गठबंधन भी अपना दम दिखाने की कोशिश करेगा। लोकसभा के साथ ही चार राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी यह वर्ष खास रहने वाला है। क्रिकेट का फटाफट प्रारूप कहे जाने वाले टी20 विश्वकप 4 से 30 जून 2024 तक आयोजित किया जाएगा। 2024 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से वेस्टइंडीज और अमेरिका करेंगे। यह पहली बार होगा, जब अमेरिका आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस में इन खेलों का आयोजन होगा। भारत भी पेरिस ओलंपिक में भाग लेगा। लिहाजा कुश्ती, मुक्केबाजी, भाला फेंक, हॉकी जैसी कई स्पर्धाओं में पदक आने की उम्मीदें होंगी। इससे पहले कई खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई भी कर लिया है। भारत के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में यह साल काफी अहम रहने वाला है। एक जनवरी 2024 को ही इसरो एक्सपोसैट मिशन प्रक्षेपित करेगा। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट का उद्देश्य अंतरिक्ष में तीव्र एक्स-रे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना है। गगनयान-1 मिशन 2024 के अंत में लॉन्च हो सकता है। तीन चालक दल के सदस्यों को अंतरिक्ष ले जाने वाली यह परीक्षण उड़ान, भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मिशन का उद्देश्य भविष्य में मानवयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए तैयारी करना है। वीनस ऑर्बिटर मिशन के तहत इसरो ने शुक्रयान-1 लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह पांच साल के लिए शुक्र की कक्षा में जाने वाला एक अंतरिक्ष यान है। दिसंबर 2024 या 2025 के लिए निर्धारित इस मिशन का लक्ष्य शुक्र के वातावरण का अध्ययन करना है।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 1, पृष्ठ-48, 1 से 15 जनवरी, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

भाजपा को मिलेगी मदद

आम चुनाव में भी दिल्ली की गद्दी मोदी के खाते में गई, तो सोचिए क्या होगा। मोदी ने हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत लिए। जाहिर सी बात है ये तीनों ही राज्य महत्वपूर्ण थे और इससे लोकसभा चुनाव में भाजपा को मदद मिलेगी।

● **रूपकुमार राय,** भोपाल (म.प्र.)

कांग्रेस खेल से बाहर

इस बार विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के आगे कांग्रेस के तीनों दिग्गज अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल ने कांग्रेस को बुरी तरह खेल से बाहर कर दिया है। हालांकि अभी कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश है लेकिन इन तीन राज्यों को हिंदी पट्टी का ताज कहा जाता है।

● **विक्रम सिंह,** जयपुर

हिंदी भाषी क्षेत्र पर पकड़

भाजपा तथा उसके सहयोगी दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सर्वमान्य है। वैसे तो मोदी पहले हिमाचल और कर्नाटक चुनाव हारे हैं लेकिन उनकी पकड़ हिंदी भाषी क्षेत्र पर बनी हुई है। 2024 के लोकसभा में ये राज्य पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा करेंगे।

● **अनवर खान,** उज्जैन (म.प्र.)

भाजपा की दूरगामी रणनीति

भाजपा को तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली सफलता के बाद उसने सभी जगहों पर नए चेहरों को मौका दिया है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने इसके जरिए दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे लाने का सियासी प्रयोग किया है। इसके साथ भाजपा ने एक मजबूत प्रतीकात्मक आधार भी तैयार किया है और नई सोशल इंजीनियरिंग गढ़कर नया संदेश देने की कोशिश की है। सियासी जानकारों की मानें तो मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के तौर पर आदिवासी, दलित, ब्राह्मण और राजपूत चेहरों को उतारकर भाजपा ने एक संदेश दिया। पार्टी ने इसके साथ ही तीनों राज्यों में नए नेतृत्व को लेकर भी नई पॉलिटिकल पिच तैयार कर सबको चौंका दिया।

● **रमाकांत साहू,** रायपुर (छग)

गठबंधन को भी लगा है बड़ा झटका

उत्तर भारत के तीन प्रमुख राज्यों मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के कस-बल थोड़े ढीले हुए हैं। पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी भाजपा को आईएनडीआईए (इंडिया) गठजोड़ के जरिए चुनौती देने के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसे लेकर भी असमंजस बढ़ता जा रहा है। गठबंधन में शामिल दलों के दबाव में 6 दिसंबर 2023 को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कई क्षेत्रीय दलों की बेरुखी को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी को इस बैठक को टालना पड़ा। हालांकि इंडिया गठबंधन के मजबूत पैरोकार शरद पवार ने पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद कहा है कि गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यह सभी जानते हैं कि कांग्रेस की हार बड़ा झटका है।

● **प्रेम प्रताप तोमर,** मुंबई (महाराष्ट्र)

चिंताजनक स्थिति

एक तरफा प्रेम प्रसंग के मामलों में लड़कियों के भी अपहरण होते हैं और ऐसे ही जबरन विवाह किए जाते हैं पर समाज के तौर पर यह देखने की जरूरत है कि जबरदस्ती की ऐसी शादियों का हश्र क्या होता होगा या क्या हो सकता है? अभी हफ्ते भर पहले ही पटना न्यायालय ने एक ऐसे ही विवाह की मान्यता 7 साल बाद रद्द कर दी है। ऐसे ही आंकड़ें बताते हैं कि प्रेम प्रसंग में की गई हत्याएं भारत में हत्या के कारणों में तीसरे नंबर पर आती हैं।

● **सुरभी नागर,** जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

अगले चुनाव में नहीं दिखेंगे कई दिग्गज!

आम चुनाव 2024 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे देश की सियासत गरमाने लगी है। कई राजनीतिक दलों ने इसके लिए अभी से अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन भी शुरू कर दिया है। चर्चा है कि कई दिग्गज राजनेता ऐसे हैं जो अगले चुनाव में नहीं दिखेंगे। कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव या मायावती अभी तुरंत रिटायर नहीं हो रहे हैं लेकिन कई नेता हैं जो सक्रिय राजनीति से रिटायर होने वाले हैं और वे आम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कम से कम चार दिग्गज नेताओं के बारे में बताया जा रहा है कि वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये नाम हैं कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, जेडीएस के एचडी देवगौड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन। इनमें से दो नेता एचडी देवगौड़ा और शिबू सोरेन पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे और हार गए थे, जिसके बाद वे राज्यसभा में चले गए थे। इन दोनों का कार्यकाल 2026 में खत्म होना है। ऊपर से दोनों की सेहत भी बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए दोनों लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहीं कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के बारे में बताया जा रहा है कि वे कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य बन सकती हैं।

कर्नाटक कांग्रेस में टूट के आसार

कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर राजनीतिक नाटक देखने को मिल सकता है। इस बात को बल मिला जनता दल (सेक्युलर) के नेता एचडी कुमारस्वामी के एक बयान से। कुमारस्वामी ने दावा किया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक प्रभावशाली मंत्री केंद्र द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों से बचना चाहते हैं, जिसके कारण वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यही नहीं उन्होंने दावा किया कि यह मंत्री 50 से 60 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं और वह वर्तमान में भाजपा नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। कुमारस्वामी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस सरकार में सबकुछ ठीक नहीं है और सरकार कभी भी गिर सकती है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से जिस तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियां विपक्षी दलों के नेताओं की जांच में जुटी है जिनसे बच निकलने की कोई संभावना नहीं है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कर्नाटक के मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखें तो कुछ भी हो सकता है।

जल्द होगा मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार!

हाल ही में संपन्न हुए पांच राज्यों के चुनावों के बाद अब आम चुनाव 2024 में कुछ ही महीने शेष हैं। ऐसे में चर्चा जोरों पर है कि मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुनर्वास के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का छोटा विस्तार हो सकता है। वहीं मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया है तो माना जा रहा है कि शिवराज को कृषि मंत्रालय का प्रभार दिया जा सकता है। चौहान के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी केंद्रीय मंत्री बनाए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव में शर्मा के कुशल प्रबंधन से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व खुश है। उल्लेखनीय है कि मोदी कैबिनेट से जिन मंत्रियों को अलग-अलग राज्यों में चुनाव लड़ाया गया था, उनमें से मप्र के दोनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल इस्तीफा दे चुके हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार शिवराज सिंह चौहान के पुनर्वास को लेकर केंद्रीय नेतृत्व गंभीर है। कई वर्षों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि चौहान को मोदी कैबिनेट में लिया जा सकता है, लेकिन जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को पराजय मिली तो पार्टी ने यू-टर्न ले लिया था। पार्टी नेताओं का कहना है कि कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को हटाए जाने के कारण भाजपा को पराजय मिली।

सबक लेगी कांग्रेस ?

भाजपा ने तीन राज्यों में बिल्कुल नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना दिया। मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नए मुख्यमंत्रियों की उम्र 60 साल से कम है। इस तरह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सिर्फ पुराने नेताओं को किनारे करके किसी के चुनौती के तौर पर उभरने की संभावना को खत्म कर दिया तो नई लीडरशिप भी तैयार कर दी। इससे पार्टी का कार्यकर्ताओं और दूसरी, तीसरी कतार के नेताओं को यह संदेश गया है कि किसी समय उनकी भी लॉटरी खुल सकती है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस इससे कोई सबक लेगी ? क्या कांग्रेस पार्टी के पुराने नेताओं को हटाकर उनकी जगह नया नेता नियुक्त करेगी ? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस की मुश्किल यह है कि उसके पास नए नेता बहुत कम बचे हैं। राहुल गांधी ने एक प्रयोग के तौर पर 2009 में जो नए चेहरे आगे किए थे उनमें से ज्यादातर भाजपा के साथ चले गए हैं। जो बचे हैं उनमें से कुछ ही लोग कांग्रेस के साथ सक्रिय हैं। कांग्रेस उनको आगे कर सकती है लेकिन पुराने नेताओं से नेतृत्व छीनना बहुत आसान नहीं होगा।

राज्यसभा जाएंगी शर्मिला!

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के बहन वाईएस शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। तेलंगाना में उन्होंने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी बनाकर बड़ी मेहनत की थी। लेकिन ऐन चुनाव से पहले उन्होंने चुनाव लड़ने की बजाय कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान किया था। शर्मिला और उनकी पार्टी ने कांग्रेस की मदद की थी, जिसका फायदा पार्टी को हुआ। चुनाव से पहले वे सोनिया गांधी से मिली थीं और तब चर्चा थी कि वे अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देंगी। लेकिन उस समय उन्होंने पार्टी का विलय नहीं किया। अब कांग्रेस के जीत जाने के बाद उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में होगा। बताया जा रहा है कि शर्मिला की पार्टी का कांग्रेस में विलय होने के बाद उनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि उनको तेलंगाना से राज्यसभा भेजा जाएगा। कांग्रेस उनका कद बढ़ाएगी ताकि वे आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती दिला सकें।

नए साल से पहले अफसरों ने मनाया जश्न

जब भी साल बदलता है लोग नए साल के जश्न में डूब जाते हैं। लेकिन गत दिनों प्रदेश के कुछ युवा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने एक पार्टी आयोजित कर जमकर जश्न मनाया। नए साल के आगमन से पहले मनाई गई यह पार्टी प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग जानने को उत्सुक हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स की यंग ब्रिगेड ने जमकर जश्न मनाया। जब इसकी पड़ताल की गई तो जश्न के पीछे की वजह भी चौंकाने वाली निकली। सूत्रों का कहना है कि इन अफसरों ने 2 लोगों की विदाई पर यह जश्न मनाया है। इनमें से एक हैं पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया रहे एक माननीय और दूसरे पूर्व प्रशासनिक मुखिया। जानकारों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रशासनिक मुखिया की सरकार में प्रदेश के युवा नौकरशाहों को खूब प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ना का आलम यह था कि कई अफसरों की सीआर भी खराब कर दी गई है। सूत्र बताते हैं कि पूर्व प्रशासनिक मुखिया तो जूनियर अफसरों के साथ तानाशाह की तरह व्यवहार करते थे। लेकिन सरकार की छत्रछाया इन पर इस कदर थी कि शिकायतों के बाद भी उनका बाल बांका नहीं हो पा रहा था। अब जब शासन और प्रशासन के केंद्र बिंदु रहे ये दोनों विदा हो गए हैं तो इसकी खुशी में अफसरों ने एक पार्टी आयोजित की और जमकर जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने अपने-अपने तरीके से दोनों की आलोचना कर भड़ास निकाली।

बड़ी मैडम का जलवा

किसी व्यक्ति का कद उसके पद से तय होता है। यह बात 100 फीसदी सत्य है। इस पर अभी हाल ही में उस समय मुहर लग गई जब 1988 बैच की एक महिला आईएएस को प्रशासनिक मुखिया की कुर्सी का प्रभार मिला। मैडम रायसेन और भोपाल की सीमा पर स्थित एक कॉलोनी में रहती हैं। इस कॉलोनी में करोड़ों के बंगले हैं, लेकिन वहां की सड़कें खस्ताहाल हैं। जबकि इस क्षेत्र में कई नौकरशाह और धनाढ्य लोग रहते हैं। लेकिन जिस दिन मैडम को प्रशासनिक मुखिया का प्रभार मिला, उसके बाद क्षेत्र की दिशा और दशा बदलने लगी है। मैडम के बंगले के पीछे बीडीए की एक सड़क है। यह सड़क सालों से खस्ताहाल थी। इसी सड़क से होकर मैडम मंत्रालय आया-जाया करती थीं। लेकिन जैसे ही मैडम को बड़ी कुर्सी मिली, तत्काल उस सड़क के कायाकल्प का कार्य शुरू हो गया है। अब वह सड़क शहर की सबसे अच्छी सड़कों में से एक बन जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मैडम का जलवा अब दिखने लगा है। बड़ी कुर्सी का रसूख क्या होता है, यह समझ में आ गया है। सूत्र बताते हैं कि पूर्व में जब मैडम के पास बड़ी कुर्सी का प्रभार नहीं था, तब उन्होंने इस सड़क को सुधारने के लिए हाथ-पांव मारे थे, लेकिन तब उनकी नहीं सुनी गई थी।

40 फीसदी वाले साहब से निजात

शीर्षक पढ़कर आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। बात भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल, प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी इस साल के आखिरी दिन रिटायर हो गए हैं। साहब के रिटायरमेंट की खबर सुनते ही व्यवसायी खुशी से झूम उठे हैं। उनका कहना है कि अब हम सुकून से रह पाएंगे, क्योंकि 40 फीसदी वाले साहब से उन्हें निजात मिल गई है। जिस आईपीएस अधिकारी की यहां बात हो रही है, वह 1993 बैच के अधिकारी हैं। साहब ने कायदे-कानून की आड़ में व्यवसायियों को खूब प्रताड़ित किया है। इसलिए उनके रिटायरमेंट की बात सुनते ही सभी खुश हो उठे हैं। जब इस संदर्भ में पड़ताल की गई तो यह बात सामने आई कि साहब ने रोड सेफ्टी के नाम पर व्यापारियों से जमकर वसूली की है। उन्होंने व्यापारियों से रोड सेफ्टी के नाम पर 40 प्रतिशत तक की वसूली की है। साहब ने इसके लिए व्यापारियों पर तरह-तरह के दबाव भी बनाए। बेचारे व्यापारी करते भी तो क्या करते, उन्होंने साहब की मांग को जैसे-तैसे पूरा भी किया। यहां बता दें कि जिस साहब की यहां चर्चा हो रही है, वे दक्षिण भारत के मूल निवासी हैं। साहब का जलवा इस कदर था कि वे मनमाने नियम बनाकर आम लोगों को परेशान करते रहे। लेकिन अब साहब रिटायर हो गए हैं और उनके कारण जो लोग परेशान हुए हैं, वे अब खुश हैं कि चलो जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन आखिरकार उन्हें 40 फीसदी के भार से मुक्ति तो मिल ही गई।

पूर्व मंत्री की जमावट खत्म

प्रदेश के सबसे बड़े विभागों में से एक विभाग में इन दिनों पूर्व मंत्री द्वारा की गई जमावट को पूरी तरह खत्म करने का अभियान चल रहा है। दरअसल, पिछली सरकार में ग्वालियर-चंबल अंचल के एक माननीय को इस बड़े विभाग का मंत्री बनाया गया था। बड़ा विभाग मिलते ही तत्कालीन मंत्रीजी ने दूसरे विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को डेपुटेशन पर लाकर अपने विभाग में पदस्थ कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि विभाग में अपना हित साधने के लिए मंत्री जी ने यह जमावट की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में मंत्री जी को हार का सामना करना पड़ा। मंत्री जी की हार के बाद अब विभाग में पदस्थ 2010 बैच की महिला अधिकारी ने डेपुटेशन पर आए अधिकारियों-कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में वापस भेजना शुरू कर दिया है। मैडम ने तो कुछ को आरोप पत्र पकड़ा दिया है। दरअसल, हुआ यह है कि एक सड़क के लिए डामर की खरीदी की गई है और उस बिल को कई सड़कों में दिखा दिया है। अब देखना यह है कि पूर्व मंत्री की क्षत्रछाया में रहने वाले कौन-कौन इसकी चपेट में आता है।

चर्चा में सरकार के सलाहकार

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में एक आईएएस अधिकारी रातों-रात चर्चा का केंद्र बन गए हैं। दरअसल, 2008 बैच के आईएएस अधिकार इन दिनों नई सरकार के सबसे चहेते अफसरों में से एक बन गए हैं। आलम यह है कि साहब सरकार के अघोषित सलाहकार बन गए हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब अक्सर दबे पांव सरकार के मुखिया के निवास पर पहुंच जाते हैं और अपने सुझाव साझा करते हैं। उधर प्रशासनिक वीथिका के वरिष्ठ अधिकारी यह देख और सुन आश्चर्यचकित हैं। इसकी वजह है कि सरकार द्वारा एक सचिव स्तर के अधिकारी से सलाह ली जा रही है। गौरतलब है की परंपरा यह रही है कि सरकार के मुखिया अक्सर वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों से शासन और प्रशासन से संबंधित मामलों में सलाह लेती है। लेकिन जो साहब इन दिनों सरकार के तथाकथित सलाहकार बने हुए हैं उनको कोई बड़ा प्रशासनिक अनुभव भी नहीं है और न ही उन्होंने कोई महत्वपूर्ण पद संभाला है। ऐसे में हर कोई इस खोज में जुट गया है कि आखिर उनमें ऐसी क्या खासियत है कि उनसे सलाह ली जा रही है।

अब होगी प्रशासनिक जमावट

मप्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद अब प्रशासनिक जमावट की कवायद तेज होगी। माना जा रहा है कि इसी महीने सरकार मंत्रालय-पीएचक्यू से लेकर मैदानी स्तर तक तबादले कर सकती है। सूत्रों का कहना है नई सरकार पर आईएएस और आईपीएस का यह बड़ा तबादला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिशा निर्देश के अनुसार होगा। ऐसे में जहां दो दर्जन से अधिक आईएएस अफसरों के तबादले होने की संभावना है। जिसमें प्रमुख सचिव से लेकर नगर निगम कमिश्नर तक शामिल हैं। वहीं कई रेंज के डीआईजी-आईजी और कई जिलों के एसपी के तबादले भी होंगे।

गौरतलब है कि डॉ. मोहन यादव द्वारा मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के पद पर राघवेंद्र कुमार सिंह की पदस्थापना की गई है। इसी कड़ी में जनसंपर्क आयुक्त और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी मनीष सिंह को हटा दिया है। उनको अपर सचिव बनाया गया। वहीं, जनसंपर्क आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार जनसंपर्क सचिव विवेक पोरवाल और एमडी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का अतिरिक्त प्रभार नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को सौंपा गया। कुछ दिन बाद विवेक पोरवाल को जनसंपर्क आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) से हटा दिया गया। वहीं, 2000 बैच के आईएएस अधिकारी संदीप यादव को सचिव मप्र शासन, विमानन विभाग तथा सचिव, मप्र शासन, जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क मप्र शासन भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मप्र माध्यम (अतिरिक्त प्रभार) सौंपा गया है।

वहीं, नर्मदापुरम के कलेक्टर नीरज कुमार को उज्जैन का कलेक्टर बनाया गया है। उनकी जगह नर्मदापुरम कलेक्टर, संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मप्र भोपाल तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जनजाति, वित्त एवं विकास निगम भोपाल तथा प्रबंध संचालक मप्र रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद अतिरिक्त प्रभार 2013 बैच की आईएएस अधिकारी सोनिया मीना को बनाया गया है। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव, राज्य बीच एवं फार्म विकास निगम के प्रबंध संचालक नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को बैतूल कलेक्टर बनाया गया है। वहीं, बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस को गुना कलेक्टर बनाया गया है। गौरतलब है कि अमनबीर सिंह के पिता इकबाल सिंह बैंस भी गुना कलेक्टर रह चुके हैं। माना जा रहा है कि प्रभारी मुख्य सचिव ने कहीं न कहीं अमनबीर सिंह की पदस्थापना उनके पिता से प्रभावित होकर की है।

इसके अलावा उज्जैन नगर पालिक निगम आयुक्त रौशन कुमार सिंह को भोपाल स्मार्ट सिटी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। नगर पालिक निगम जबलपुर के आयुक्त स्पन्निल वानखेड़े को विशेष कर्तव्यस्त अधिकारी सह आयुक्त सह संचालक संस्थागत वित्त बनाया गया है। वहीं, उज्जैन जिले की अपर कलेक्टर प्रीति यादव को जबलपुर नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, आईएएस अधिकारी दीपाली रस्तोगी को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ ही प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

● **सुनील सिंह**

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति

मप्र सरकार ने गत दिनों भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति दी। दो आईजी को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। 1999 बैच के राकेश गुप्ता और दीपिका सूरी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाए गए। वहीं 2006 बैच के 13 आईपीएस आईजी, तो 2009 और 2010 बैच के आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी बनाया गया है। गृह विभाग ने 2006 बैच के 13 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नत कर आईजी बनाए जाने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ अंशुमान सिंह, रुचिवर्धन मिश्रा समेत कई अधिकारी पदोन्नत हुए हैं। इन अधिकारियों को पदोन्नति के बाद अभी यथावत पदस्थ रखा गया है। इनकी नवीन पदस्थापना के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। भारतीय पुलिस सेवा के उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपर परिवहन आयुक्त और उप पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। इनमें रुचिवर्धन मिश्रा, चंद्रशेखर सोलंकी, चैत्रा एन, अनिल सिंह कुशवाह, आरआरएस परिहार, आरके हिंगणकर, अंशुमन सिंह, मनीष कपूरिया, अरविंद कुमार सक्सेना, विनीत खन्ना, हिमानी खन्ना, मिथिलेश शुक्ला और अनुराग शर्मा का नाम है। रुचिवर्धन मिश्रा को पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन पुलिस मुख्यालय बनाया गया है। वहीं सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के ही 18 अधिकारियों को उप पुलिस महानिरीक्षक पद पर पदोन्नत किया है। इसमें सेनानी, पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संचालक जनसंपर्क, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपायुक्त शामिल हैं। इनमें 2009 बैच के साकेत प्रकाश पांडे, अमित सांघी, तुषारकांत विद्यार्थी, सत्येंद्र कुमार शुक्ला, बीरेंद्र कुमार सिंह, प्रशांत खरे, अतुल सिंह, मनीष कुमार अग्रवाल। वहीं 2010 बैच के आबिद खान, आशुतोष प्रताप सिंह, मोहम्मद युसूफ कुरैशी, निमिष अग्रवाल, सिद्धार्थ बहुगुणा, पंकज श्रीवास्तव, राजेश कुमार सिंह, विनीत कपूर, धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और हेमंत चौहान शामिल हैं।

पीएम के साथ बैठक में शामिल नहीं हुईं सीएस... हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक हुई। लेकिन इसमें मप्र की सीएस वीरा राणा शामिल नहीं हुईं। उन्होंने अपनी जगह एसीएस राजेश राजौरा को भेजा। इसके पीछे सीएस ने खराब तबीयत का हवाला दिया था। लेकिन सूत्रों का कहना है कि सीएस इसलिए नहीं गईं, क्योंकि उनको इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस बैठक में प्रदेश से संबंधित व्यवस्था का प्रेजेंटेशन देना था। इसलिए उन्होंने तेज तर्रार अफसर राजौरा को भेजा। लेकिन इस बैठक में सीएस की गणना होती है, इसलिए मप्र की भागीदारी तकरीबन अनुपस्थित मानी गई। इससे कहीं न कहीं प्रदेश की साख गिरी है और इसका प्रभाव भविष्य में दिख सकता है।

बीआरटीएस मुक्त होगा भोपाल

वाहनों के लिए जगह नहीं, कॉरिडोर खाली

भोपाल में 24 किमी का कॉरिडोर बना है। इसमें भी रोशनपुरा से बोर्ड ऑफिस तक 4 किमी डेडिकेटेड लेन नहीं है। दो फ्लाईओवर बनने के बाद 5.3 किमी की डेडिकेटेड लेन का हटना पहले से तय है। यानी 14.7 किमी में डेडिकेटेड कॉरिडोर रह गया है, जिसे हटाने पर करीब 5 करोड़ खर्च होंगे। यह डेडिकेटेड कॉरिडोर होशंगाबाद रोड के साथ पॉलिटेक्निक चौराहा, किलोल पार्क से कमला पार्क और लालघाटी चौराहे पर परेशानी का सबब है। बीआरटीएस की लो फ्लोर बसों में शहर के करीब 1 लाख लोग सफर कर रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में ये आंकड़ा करीब 5 प्रतिशत है। बीआरटीएस के 24 रूट हैं और उन पर अभी 368 बसें चल रहीं हैं। इनमें से ज्यादातर डेडिकेटेड लेन के बाहर ही चलती हैं। शहर में 18.50 लाख निजी टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर वाहन हैं, जो कॉरिडोर के बाहर मिक्स लेन में चलते हैं। होशंगाबाद रोड, बोर्ड ऑफिस चौराहा, एमपी नगर क्षेत्र और पॉलिटेक्निक चौराहा से कमला पार्क तक रोजाना ट्रैफिक जाम के हालात बनते हैं।

भोपाल में 360 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए बीआरटीएस को हटाने पर आखिरकार सहमति बन गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में इसे हटाने का निर्णय लिया गया। अब भी हवाला वही दिया गया, जो करीब 10 साल से दिया जा रहा है कि बीआरटीएस के कारण ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी नहीं बल्कि बिगड़ रही है। बीआरटीएस को कई चरणों में हटाया जाएगा। इसमें 52 बस स्टॉप भी हैं, जो पीपीपी मोड पर हैं। सड़क समतलीकरण करने और सड़क के बीच में सेंट्रल रोड डिवाइडर बनाया जाएगा। बैठक में पीडब्ल्यूडी ने लेक कॉरिडोर के प्रस्ताव पर भी प्रेजेंटेशन दिया। इससे पहले तत्कालीन नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह, भूपेंद्र सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि इसे हटाने की बात कह चुके हैं, लेकिन हटा नहीं पाए। भूपेंद्र सिंह ने तो 27 अप्रैल 2022 को अजीब ऐलान भी कर दिया था। उन्होंने कहा था कि होशंगाबाद रोड पर ट्रैफिक जाम की आए दिन होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए शाम 4-9 बजे तक बीआरटीएस कॉरिडोर आम लोगों के लिए भी पूरी तरह खोल दिया जाएगा। इन पांच घंटे में सभी वाहन कॉरिडोर और आसपास की सड़कों से आवागमन कर सकेंगे। खुद विभाग के मंत्री होने के बाद भी वह न बीआरटीएस हटा पाए और न ही अपने ऐलान को ही पूरा कर पाए।

मार्च 2022 में भोपाल में हुई टाउन प्लानर्स की कॉन्फ्रेंस में भी बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की बात उठी थी। इसके कुछ दिन बाद भोपाल नगर निगम ने कॉरिडोर के रोड वर्क (मेंटेनेंस) के लिए 26 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर काम पूरा कर दिया। ये रोड वर्क मिसरोद से बैरागढ़ के बीच 24 किमी के कॉरिडोर में किया गया। इससे पहले भी बीआरटीएस कॉरिडोर के लिए दो बार मेंटेनेंस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 13 साल पहले इसे बनाने में 360 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि मेंटेनेंस पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते रहे। फिर भी कॉरिडोर पर हादसे कम नहीं हुए। यही वजह है कि कई मौकों पर मंत्री से लेकर विधायक तक इसे हटाने को लेकर पैरवी करते रहे। कॉरिडोर हटाए जाने के निर्णय से वे सभी ज्यादा खुश हैं, जो हर रोज बैरागढ़ और होशंगाबाद रोड पर जाम में फंसते रहे हैं। साल 2009-10 में मिसरोद से बैरागढ़ तक लगभग 24 किमी लंबा बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया गया था। तब इस पर 360 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बीसीएलएल (भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड) और नगर निगम ने 13 साल में कॉरिडोर के रखरखाव पर लाखों रुपए खर्च किए। इसके बावजूद कॉरिडोर से गुजरने वाले लाखों लोगों के लिए यह मुसीबत बना रहा। इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स ऑफ इंडिया (आईटीपीआई) के जनरल सेक्रेटरी वीपी कुलश्रेष्ठ का कहना है कि भोपाल में बीआरटीएस बना ही गलत। शहर की सबसे मुख्य सड़क पर बीआरटीएस बना दिया गया, लेकिन इसे आसपास की कॉलोनियों से नहीं जोड़ा गया। यानी लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं दी गई। शहर की सबसे प्रमुख सड़क होने के कारण स्वाभाविक रूप से फ्लाईओवर भी वहीं आए और डेडिकेटेड कॉरिडोर को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अब मेट्रो भी आ रही है, ऐसे में बीआरटीएस को हटा देना ही ठीक है।

बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के लिए कमलनाथ और शिवराज सरकार के मंत्री और विधायकों ने सवाल उठाए थे। वर्ष 2019 में भी यह मामला सुर्खियों में रहा था। तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने बीआरटीएस कॉरिडोर के प्रेजेंटेशन को भी देखा था। रिव्यू भी किया था। बाद में सरकार चली गई और कॉरिडोर को लेकर कोई बात नहीं हुई। पिछले साल हबीबगंज अंडरब्रिज के लोकार्पण के दौरान तत्कालीन प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस कॉन्सेप्ट को ही गलत बताया था। वहीं, मंत्री विश्वास सारंग ने इसे उखाड़ फेंकने की बात कही थी। विधायक रामेश्वर शर्मा, कृष्णा गौर ने भी कॉरिडोर को लेकर आपत्ति जताई थी। बीआरटीएस कॉरिडोर के कारण कई परेशानियां हो रही हैं। लालघाटी चौराहे पर अधूरा ग्रेड सेपरेटर बनने के बाद यहां लो फ्लोर बसों को टर्न होने में दिक्कत आ रही है। कमला पार्क से किलोल पार्क तक ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह डेडिकेटेड कॉरिडोर भी है, आर्च ब्रिज के निर्माण के बाद ये परेशानी और बढ़ गई। पॉलिटेक्निक चौराहे पर बस को मुड़ने में दिक्कत होती नजर आती है। डेडिकेटेड लेन में लगाए गए ज्यादातर ट्रैफिक सिग्नल बंद ही रहते हैं, जो चालू हैं वो प्रभावी नहीं। कॉरिडोर की रेलिंग में 125 से ज्यादा कट पॉइंट हैं और 20 से ज्यादा स्थानों पर रेलिंग टूटी है।

कॉरिडोर से सिर्फ सिटी बसें ही गुजरती हैं। दूसरी गाड़ियां नहीं निकल पातीं। इस कारण दोनों ओर वाहनों के जाम की स्थिति बन रही है। यदि मिनी बसें या अन्य गाड़ियां कनेक्ट होती तो जाम की स्थिति नहीं बनती। इन्हीं कारणों की वजह से दिल्ली से भी कॉरिडोर हट चुका है। कॉरिडोर हटाने से दोनों ओर एक-एक लेन मिल जाएगी। इससे ट्रैफिक का मूवमेंट ठीक होगा, लेकिन इसे हटाने के बाद बसों के लिए भी सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए भी सुविधा देना पड़ेगा। रोड सेफ्टी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बस स्टॉप भी बनाने होंगे, ताकि बसों के ठहराव के साथ दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए व्यवस्था जुटाई जा सके। इसे हटाने के बाद बेहतर नॉन बीआरटीएस सिस्टम देना होगा।

● **कुमार विनोद**

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी मात देने के बाद अब भाजपा का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर है। भाजपा की नई रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी तैयारी के साथ प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतकर कांग्रेस का सूपड़ा साफ करेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही मोहन यादव इस काम में जुट गए हैं।

अबकी बार सभी 29 सीटों पर दांव

म प्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत से भाजपा खेमे में भारी उत्साह है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अब प्रदेश की लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतने का संकल्प लिया है। इस अभियान में मुख्यमंत्री लग गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में 29 में से 28 सीटें मिली थीं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत पाया लेकिन छिंदवाड़ा जिले की सातों सीटें नहीं जीत पाई। कमलनाथ का गढ़ पूरी तरह से अभेद है। खास बात ये है कि छिंदवाड़ा जिले में सेंध लगाने के लिए भाजपा ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ ही कई केंद्रीय मंत्री उतारे लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन पुराने रिकार्ड को भुलाकर अब भाजपा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में मिशन 2024 में क्लीन स्वीप की तैयारी में जुट गई है। गौरतलब है कि हमेशा मिशन मोड में रहने वाली भाजपा ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मप्र विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब भाजपा राज्य में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप की तैयारी में जुट गई है। भाजपा का लक्ष्य है कि प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीता जाए। इसके लिए पार्टी में रणनीति बनने लगी है। गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों पर भाजपा का और 1 लोकसभा सीट छिंदवाड़ा पर कांग्रेस का कब्जा है।

आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कब्जे वाली छिंदवाड़ा सीट समेत सभी 29 सीटों को जीतने के लिए भाजपा विधानसभा चुनाव की रणनीति पर ही काम करेगी। जानकारों की मानें तो विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की घेराबंदी की जाएगी। ऐसे में पार्टी ने यहां पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दिया है। तभी जाकर भाजपा के लिए लोकसभा की राह आसान हो पाएगी। 2003 के बाद भारतीय लोकतंत्र में यह देखा गया है कि विधानसभा और लोकसभा में एक जैसे पैटर्न पर चुनाव नहीं होते हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अलावा कर्नाटक में भी अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। भाजपा पार्षद से लेकर लोकसभा चुनाव में पूरी मेहनत करती है। वह किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। खास बात यह है कि छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का साथ मिलता है। जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का भी हौसला बुलंद हो जाता है। पार्टी के आलाकमान की कोशिश है कि वे इस जीत को लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रखें। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पार्टी एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रही है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भाजपा मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का किला भेदने में सफल हो पाई है। भाजपा की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में भी वह इसे बरकरार रखे।

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अंचलवार रणनीति बनाई थी। विशेषकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को घेरने के लिए पार्टी ने अपने ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी थी, जो चुनावी प्रबंधन में माहिर थे। इसी तरह आरक्षित सीटों के लिए भी अलग से

इस बार 65 फीसदी का लक्ष्य

भाजपा सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी भाजपा लक्ष्य निर्धारित कर काम में जुटेगी। 2019 में लोकसभा की 29 सीटों में से 28 पर ऐतिहासिक विजय हासिल करने वाली भाजपा ने 58 फीसदी वोट हासिल कर एक कीर्तिमान दर्ज किया था। वहीं, करारी शिकस्त का सामना करने वाली कांग्रेस को 34.50 प्रतिशत मतदाताओं ने ही समर्थन दिया था। अब मिशन 2024 के लिए भाजपा ने 65 फीसदी वोट का लक्ष्य निर्धारित किया है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से छह माह पहले 2018 में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच मतों का अंतर काफी कम था। भाजपा को 41 प्रतिशत के साथ 1 करोड़ 56 लाख वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 40.90 प्रतिशत के साथ 1 करोड़ 55 लाख से कुछ अधिक वोट हासिल हुए थे। भाजपा को अधिक मत मिलने के बावजूद 230 विधानसभा में से 109 सीटें मिलीं और कांग्रेस को 114 सीटें। इस तरह कांग्रेस बहुमत के करीब थी और उसने बसपा, सपा और चार निर्दलीय समेत कुल सात विधायकों के समर्थन से सरकार बना ली। लेकिन इस बार भाजपा को 48.55 प्रतिशत वोट मिले हैं।

रणनीति बनाई गई थी। परिणाम यह रहा कि कांग्रेस बदलाव की बात करती रही और मतदाताओं ने भाजपा को दो तिहाई बहुमत देकर एक बार फिर से सूबे को सत्ता सौंप दी। प्रदेश को आरक्षित सीटों पर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डाली जाए तो एससी वर्ग की 38 सीटों में से भाजपा ने इस बार 30 पर जीत दर्ज की है। इसी तरह एसटी की 47 सीटों में से भाजपा को 24 और कांग्रेस ने 22 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। जबकि वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 47 एसटी सीटों में से 37 पर विजय हासिल कर सरकार बनाने में सफलता पाई थी। तब भाजपा को मात्र 15 एसटी आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई थी। यानि दोनों आरक्षित वर्ग की 82 सीटों में से भाजपा के पाले में 50 सीटें गईं, जो पिछले चुनाव की तुलना में 17 सीटें ज्यादा थीं।

भाजपा लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की तरह अपना प्रदर्शन दोहराना चाहती है, इसलिए प्रदेश संगठन ने मिशन 29 अपने हाथों में लिया है। यानी कि सूबे की सभी 29 सीटों को जीतकर लोकसभा में मप्र से कांग्रेस मुक्त कराया जा सके। जानकारों की मानें तो भाजपा अगले लोकसभा चुनाव के लिए कई आरक्षित सीटों पर इस बार नए चेहरे उतार सकती है। इनमें भिंड, देवास और उज्जैन में भाजपा नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। इसी तरह छिंदवाड़ा, बालाघाट में भी किसी नए नेता को संसदीय चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसी तरह सीधी, सतना, जबलपुर, मुरैना, ग्वालियर, सागर में भी लोकसभा चुनाव के लिए किसी नए नेता को मैदान में उतारा जा सकता है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हारे थे। केवल कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपने पुत्र नकुलनाथ को जिताकर कांग्रेस की लुटिया पूरी तरह से डूबने से बचाई थी। इस बार भाजपा छिंदवाड़ा संसदीय सीट को भी कांग्रेस से छीनना चाहती है, साथ ही वह विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की हार को भी ध्यान में रखकर आदिवासी और अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए रणनीति बनाएगी। जानकारों का कहना है कि पार्टी इन सभी सीटों में बूथ स्तर पर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारेगी। कहा जाता है कि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसकी हर चाल चुनावी होती है। पांच राज्यों के चुनाव में भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों समेत लोकसभा के 21 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था जिनमें से 9 सांसद हार गए हैं। अब चुनाव हारने वाले सांसद 2024 में टिकट की रेस से ऐसे ही बाहर माने जा रहे हैं। जो जीतकर आए हैं उन्होंने भी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यानी भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीतने वाले सांसदों को दिल्ली से सूबे की सियासत में भेज दिया है। इसे एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए भाजपा की टिकट काटने वाली रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मतदाताओं को साधने का फॉर्मूला बना लिया है। दो दिनों तक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में चले मंथन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पदाधिकारियों को मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने चार जातियों को ध्यान में रखकर काम करने को कहा है ये चार जातियां हैं- युवा, गरीब, महिला और किसान। इस बैठक में गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस करने के साथ ही उन्हें पार्टी से जोड़ने और उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताने का निर्देश दिया गया। वहीं भाजपा पदाधिकारियों को संदेश दिया गया कि अब मिशन मोड में काम करना होगा। आने वाला साल 2024 चुनावों का साल है। अगले छह महीने के भीतर मोदी सरकार के पांच साल पूरे होने के साथ लोकसभा चुनाव भी हो जाएंगे। ऐसे में भाजपा अभी से चुनावी मोड में है। पांच राज्यों में आए चुनावी परिणामों से पार्टी का उत्साह भी बढ़ा हुआ है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने इसे संभालते हुए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव के लिए नए सिरे से जुट जाने के लिए निर्देशित किया है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा जिस रणनीति पर चुनाव लड़ी है उसे लोकसभा में भी कायम रखा जाएगा। यानी लोकसभा चुनाव में भी गरीब, युवा, महिला और किसान पर सबसे अधिक फोकस रहेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से राजनीतिक दलों ने खूब वादे किए। अब किसान, महिला, युवा व गरीब जैसे वर्ग को आर्थिक फायदा देना लगभग हर दल की मजबूरी होगी। कोरोनाकाल में केंद्र की तरफ से गरीब महिलाओं के खाते में 500-500 रुपए दिए गए। मप्र में लाड़ली बहना ने भी असर दिखाया। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने कई अहम वादे किए। राजनीतिक पंडितों का मानना है महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ दिए जाने से वह आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और उन्हें सत्ता में भागीदार बनने का अहसास हो रहा है जो जाति व धर्म से अलग हटकर वोट करती हैं।

● **कुमार राजेन्द्र**

छिंदवाड़ा पर अधिक फोकस

मप्र विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चेहरा रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस ने एक बार फिर क्लीन स्वीप किया। यहां फिर से भाजपा का खाता नहीं खुल पाया। यहां की सभी सातों विधानसभा सीट पर कमलनाथ का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला और पार्टी प्रत्याशियों ने शानदार जीत दर्ज की। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर 35 हजार के अधिक वोटों के अंतर से भाजपा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को शिकस्त दी। वहीं अन्य छह सीटें अमरवाड़ा, परासिया, जुन्नारदेव, सौंसर, पांढुर्णा और चौरई से भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। बता दें कि छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है। मप्र सहित देश की राजनीति में यह जिला एक अहम स्थान रखता है। यहां कमलनाथ को हराना विरोधियों के लिए काफी मुश्किल माना जाता है। छिंदवाड़ा में हर बार भाजपा को मुंह की खानी पड़ती है। चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का यहां सूपड़ा साफ हो गया था। सात में से एक भी सीट पर उसे जीत नहीं मिली थी।

बजट सत्र में आएगा लेखानुदान

नए वित्त वर्ष में इस बार सरकार द्वारा वार्षिक बजट नहीं लाया जाएगा, बल्कि आगामी चार माह के लिए लेखानुदान लाकर काम चलाया जाएगा। इसकी वजह है इस दौरान होने वाले लोकसभा के चुनाव। चुनाव के बाद जुलाई में वार्षिक बजट पेश किए जाने की संभावना है। शासन स्तर पर लेखानुदान लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल लेखानुदान लाकर सरकार योजनाओं की गति न केवल जारी रखना चाहती है, बल्कि विकास कार्य के प्रोजेक्ट भी पूरे करना चाहती है। पुनरीक्षित बजट तैयार करने के लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन्हें जल्द से जल्द वित्तीय बजट साल 2023-24 में की गई घोषणाओं के मुताबिक खर्च की जानकारी देने को कहा गया है। इसमें यह भी बताना होगा कि किन योजनाओं में कितना पैसा खर्च हो चुका है और कितने की आवश्यकता है। इसकी वजह सरकार को अपनी नई शुरू की गई योजनाओं के लिए राशि की व्यवस्था करना है।

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक 2023-24 के पुनरीक्षित अनुमान और वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान व लेखानुदान (अप्रैल 2024 से जुलाई 2024) के आंकड़े आईएफएमआईएस के बजट माड्यूल में देना है। इसमें प्राप्त होने वाले राजस्व और होने वाले खर्च दोनों के लिए पुनरीक्षित अनुमान और बजट अनुमान के आंकड़े बीसीओ स्तर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभाग ने कहा है कि लेखानुदान पहले चार माह के लिए केवल आवश्यक खर्च के लिए ही लाया जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि विभाग के विभागाध्यक्ष, बजट नियंत्रण अधिकारी और वित्तीय सलाहकार बजट प्रस्तावों के लिए उत्तरदायी होंगे, विशेष तौर पर अनिवार्य व स्थापना संबंधी खर्च के सटीक आंकलन का काम करना होगा। लेखानुदान बजट तैयार करने को लेकर जो व्यवस्था तय की गई है उसके मुताबिक विभाग मजदूरी के खर्च में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 5 प्रतिशत की वृद्धि कर प्रस्ताव तैयार करेंगे। विभागीय अधिकारी कार्यालय खर्च व्यय के अंतर्गत पेट्रोल व्यय में पांच प्रतिशत की वृद्धि कर सकेंगे। विभाग सुरक्षा, सफाई और परिवहन व्यवस्था के लिए बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी। वित्त विभाग द्वारा व विभागों के वेतन मद में 2023-24 के मुकाबले 2024-25 के लिए तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। महंगाई भत्ते में बजट अनुमान 2024-25 के वेतन मद में प्रस्तावित राशि का 56 प्रतिशत रखा गया है। संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सभी खर्च वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की सीमा में रखे गए हैं।

केंद्र सरकार से मिले 57 अरब रुपए

केंद्रीय वित मंत्रालय ने प्रदेश को 57 अरब रुपए से अधिक की अतिरिक्त किश्त जारी कर दी है। यह राशि गत दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव के दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद मोदी से उनकी मुलाकात और विकास कार्यों के लिए तय प्राथमिकताओं पर चर्चा के दौरान जारी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि कई राज्यों की अपेक्षा मप्र में जीएसटी कलेक्शन में अच्छी वृद्धि हुई है। यह राशि मिलने से प्रदेश में विकास कार्यों के साथ ही सरकार को गरीब कल्याण योजनाओं को गति मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र में सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचे के विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए यह राशि दी गई है। सरकारी योजनाओं में केंद्र सरकार ने भले ही पहले 10 फीसदी की कटौती कर दी थी, लेकिन इसके एवज में लाभांश में 10 फीसदी की वृद्धि कर दी गई है। जिसकी वजह से केंद्र से मिलने वाले लाभांश की राशि 32 फीसदी की जगह 42 फीसदी हो गया है। विभाग ने कहा है कि इसको लेकर अगर प्रशासकीय विभाग के अफसर वित्त विभाग के सचिव, अपर मुख्य सचिव से चर्चा की जरूरत समझते हैं तो वित्त विभाग से इसके लिए तारीख और समय तय कर डिस्कशन कर सकेंगे।

सरकार के सामने इस समय खजाना खाली होने की वजह से लाड़ली बहना योजना, गेहूं और धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी सहित तमाम योजनाओं के लिए राशि की व्यवस्था करने की चुनौती बनी हुई है। इसी तरह से विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा अपने संकल्प पत्र में किए गए तमाम वादों पर अमल शुरू करने के लिए भी राशि की सरकार को जरूरत है। यही वजह है कि अभी से चार माह के लिए जरूरी राशि के आंकलन का काम शुरू कर दिया गया है। आंकलन के हिसाब से लेखानुदान में राशि का प्रावधान किया जाएगा। जानकारों की मानें तो सरकार अगर 100 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान करती है, अगर वित्तीय स्थिति प्रोजेक्ट के मुताबिक बेहतर नहीं है तो योजना को गति देने के लिए 20 से 30 फीसदी फंड जारी कर विकास कार्य को जारी रखा जा सकता है। ऐसे ही कोई नई स्कीम की शुरुआत लेखानुदान में नहीं होगी, क्योंकि नई योजना के लिए सालाना वित्तीय बजट जरूरी होता है। लोकसभा चुनाव के चलते केंद्र सरकार भी आम बजट पेश नहीं करेगी। हर साल फरवरी महीने में केंद्र सरकार की ओर से बजट जारी किया जाता है। इसके बाद ही राज्य सरकार तय करती है कि योजनाओं में कितना फंड दिया जा सकता है। केंद्र की ओर से मिलने वाली राशि के आधार पर ही राज्य सरकार की प्राथमिकता होती है कि योजनाओं को गति दी जाए। हालांकि लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद मौजूदा सरकार केंद्र का बजट जून-जुलाई माह में पेश कर सकती है। इसके बाद ही मप्र सरकार का सालाना वित्तीय बजट पेश किया जाएगा। वित्त विभाग के अफसरों के मुताबिक लेखानुदान में कर्मचारियों की सैलरी, वेतन वृद्धि और ऑफिस से जुड़े हुए जरूरी खर्चों के लिए प्रावधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में चल रही योजनाओं को भी जारी रखना सरकार के लिए अहम होगा। इसकी वजह से ही संविदा कर्मचारियों के वेतन भत्ते सहित अन्य विकास कार्यों के लिए इसमें राशि का प्रावधान किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसकी वजह से करीब तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी लेखानुदान में की जा सकती है। सूत्रों कहना है कि पूर्व में जिन योजनाओं का ऐलान किया था, उनके लिए राशि का प्रावधान वार्षिक बजट में किया जाएगा।

● **रजनीकांत पारे**

टारगेट पूरा करने में पिछड़ा परिवहन विभाग

परिवहन महकमे को वित्तीय वर्ष में 4400 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य मिला था, लेकिन शासन ने अगस्त 2023 में टारगेट में 400 करोड़ की बढ़ोतरी कर दी थी, जिससे टारगेट 4800 करोड़ रुपए हो गया था। विभाग ने अभी तक 3 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त कर लिया है। इसका कारण विधानसभा चुनाव बताया जा रहा है जिसमें काफी अमला जुटा रहा। अब 4800 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए विभाग को 20 दिसंबर से 31 मार्च तक यानी 100 दिन में 1800 करोड़ रुपए राजस्व जुटाना होगा। विभाग को वर्ष 2022-23 में 3800 करोड़ का टारगेट मिला था, जिसे वित्तीय वर्ष पूरा होने से पहले हासिल कर लिया था। 31 मार्च तक शासन को 4012 करोड़ रुपए राजस्व दिया था।

परिवहन विभाग ने राजस्व लक्ष्य रिवाइज किए जाने के बाद जिलों को दिए गए टारगेट को संशोधित किया था। लक्ष्य की पूर्ति में सभी जिले माइनस में चल रहे हैं। विभाग के आयुक्त एसके झा ने परिवहन अधिकारियों को वित्तीय वर्ष में मिले टारगेट को पूरा करने के लिए अवैध खनन के ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी के बाद अधिकारी-कर्मचारियों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। परिवहन विभाग में राजस्व संग्रहण वाहनों के रजिस्ट्रेशन, वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल वाहनों के परमिट, वाहनों में ओवर लोडिंग से होता है। इसके अलावा बिना अनुमति के वाहनों का मार्ग पर संचालन, बिना हेलमेट दोपहिया, बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाने, मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पेनाल्टी से भी राजस्व का संग्रहण किया जाता है। इसके अलावा विभाग ओवरलोडिंग पर भी कार्रवाई कर जुर्माना वसूलता है। इससे राजस्व अर्जित होता है। परिवहन विभाग अमले द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 का 3800 करोड़ का निर्धारित राजस्व संग्रहण का लक्ष्य 31 मार्च से 15 दिन पहले ही प्राप्त कर लिया था। उसके बाद बचे हुए दिनों में 212 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया था।

उधर, प्रदेश में परिवहन चेकपोस्ट बंद कर वैकल्पिक जांच प्रणाली शुरू किए जाने के प्रयासों के बीच पहले 40 चेकपोस्ट की जगह यह नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। प्रदेश में 120 परिवहन चेकपोस्ट हैं, लेकिन पहले चरण में 40 जगह ही नई व्यवस्था की शुरुआत होगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने 28 करोड़ रुपए का बजट और 1000 कर्मचारियों का स्टाफ मांगा है। परिवहन विभाग की इस क्रम में दिसंबर में तीसरी बैठक नई व्यवस्था को लेकर हुई है। वर्तमान में परिवहन विभाग पर प्रवर्तन में 419 का बल है जो नए चेक प्वाइंट पर पदस्थ करना होगा। इसके अलावा जो नए चेक प्वाइंट बनेंगे, वहां स्विस टेंट लगेंगे, कोई स्थायी ढांचा नहीं बनेगा। यहां प्रति चेक प्वाइंट इंटरसेप्टर वाहन, सीसीटीवी कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा, पीओएस मशीन, पोर्टेबल ब्रिज लोड चेक करने यह सभी अत्याधुनिक व्यवस्थाएं रहेंगी। वहीं नई व्यवस्था में फ्लाइंग स्क्वाड ज्यादा रहेंगे। अभी वर्तमान में प्रदेश में परिवहन पर 800 के आसपास बल है जबकि 1700 स्वीकृत है।

बता दें, अन्य प्रदेशों में परिवहन चेक पोस्ट व्यवस्था बंद हो गई है और प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स-ऑपरेटर अवैध वसूली व परेशानी के मामलों के कारण इसके विरोध में है और इसको लेकर उच्च स्तर पर मांग कर चुके हैं। सात अस्थायी चेक पोस्ट विभाग पिछले महीनों में बंद कर चुका है। परिवहन चेक पोस्टों को बंद करने की दिशा में परिवहन आयुक्त एसके झा के निर्देश पर अपर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रदेश की परिवहन चेक पोस्ट के स्थान पर वैकल्पिक चेकिंग प्वाइंट व्यवस्था शुरू की जाना चाहिए, जो पूरी तरह हाईटेक होगी। इस प्रस्ताव के बाद परिवहन विभाग ने पहले अस्थायी चेक पोस्टों को बंद कर दिया। अब हाल में नई व्यवस्था को लेकर यह तीसरी बैठक हुई है, जिसमें वर्तमान में मौजूद 120 चेकपोस्टों को चेक प्वाइंट में परिवर्तित किया जाएगा। प्रदेश में चेक पोस्टों को चेक प्वाइंट बनाने के क्रम में कैशलेस व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। यही कारण है कि नए चेक प्वाइंटों पर पीओएस मशीन लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। पूरी व्यवस्था कैमरों की निगरानी में रहेगी जिससे कभी भी चेक किया जा सके। अपर आयुक्त परिवहन विभाग अरविंद सक्सेना का कहना है कि प्रदेश में परिवहन चेक पोस्टों को बंद कर वैकल्पिक चेकिंग प्वाइंट व्यवस्था लाई जा रही है, इसकी हाल में बैठक हुई जिसमें 28 करोड़ का बजट और एक हजार का बल मांगते हुए प्रस्ताव भेजा गया है। अभी परिवहन विभाग के पास स्वीकृत से आधा ही बल है। देश में माल वाहनों के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देश में 1 अक्टूबर 2025 से सभी मध्यम और भारी माल वाहनों में एयर कंडीशन यानि वातानुकूलित कैबिन होना जरूरी होगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2025 से बनने और बिकने वाले वाहनों पर लागू होगा।

● **विकास दुबे**

ड्राइवर्स की सुविधा और हादसे कम करने के लिए लिया निर्णय

परिवहन मंत्रालय द्वारा लंबे समय से सड़क हादसे कम करने को लेकर काम किया जा रहा है। इसमें हाईवे पर बड़े हादसे बड़े माल वाहनों से होना पाया जाता है। स्टडी में इसका एक कारण यह भी सामने आया कि ऐसे वाहनों को चलाने वाले ड्राइवर्स खराब परिस्थिति में वाहन चलाते हैं। उन्हें रोजाना सैकड़ों किलोमीटर वाहन चलाना होता है, लेकिन उनके लिए कैबिन सुविधाजनक नहीं होते हैं। गर्मी में इनमें काफी गर्मी लगती है। बारिश में खिड़कियां खोले रखने पर अंदर पानी आता है और बंद करने पर कांच पर धुंध जम जाती है। ठंड में भी ऐसी ही परेशानी रहती है। इस कारण कई बार हादसे होते हैं। इसे देखते हुए ड्राइवर्स की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है, ताकि हादसों में कमी आए और ड्राइवर्स के लिए भी सफर सुविधाजनक हो। आदेश में पूरे तैयार वाहनों के साथ ही सिर्फ चेचिस वाले वाहनों के लिए भी नियम दिया गया है कि निर्माता को ऐसे वाहनों में भी एसी कैबिन देना होगा। अगर वाहन मालिक कैबिन नहीं लेना चाहता है तो उसे वाहन के कैबिन निर्माण के समय एसी की सुविधा देने वाली किट उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। इससे वाहन मालिक वाहन को अपने हिसाब से तैयार करवाता है, तब भी कैबिन में एसी की सुविधा मिल सकेगी। परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर माल वाहनों में एसी की सुविधा को अनिवार्य किया जाता है तो इससे माल वाहनों की कीमत में इजाफा होगा। इसका सीधा असर माल वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों की जेब पर पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2025 के पहले के वाहनों पर ऐसी अनिवार्यता नहीं होगी।

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के पास बनेगा लॉजिस्टिक पार्क

लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के नजदीक के ही लॉजिस्टिक पार्क भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने संभावनाएं देखना शुरू कर दी हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे लॉजिस्टिक पार्क बनने से ग्वालियर-चंबल अंचल में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इससे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक पार्क में कंपनियों के कार्यालय भी खुलेंगे। दिल्ली के नजदीक होने के कारण ग्वालियर लॉजिस्टिक पार्क को अधिक फायदा होगा, क्योंकि यहां से सीधे एक्सप्रेस-वे की कनेक्टिविटी मिलेगी।

वर्तमान में सामान की ढुलाई के लिए दिल्ली-मुंबई के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहा है, जिसके लिए रेल और सड़क दोनों परिवहन माध्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में शनिचरा के नजदीक मालनपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो भी मौजूद है, इससे भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की कनेक्टिविटी बनेगी। पिछले वर्ष सितंबर माह में एलिवेटेड रोड का भूमिपूजन करने आए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के साथ ही लॉजिस्टिक पार्क निर्माण की घोषणा की थी। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि दिल्ली से मुंबई तक के सफर में ग्वालियर एक महत्वपूर्ण गेटवे है। इसलिए यहां लॉजिस्टिक पार्क स्थापित कर रोजगार के नए अवसर और उद्योग भी पैदा किए जाएंगे।

दरअसल, लॉजिस्टिक पार्क कच्चे माल और खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है। इन पार्कों में कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं होती हैं, जिसकी मदद से देशभर से लाए माल को इसमें स्टोर किया जा सकता है। यहां माल को सुरक्षित रखने की पूरी व्यवस्था की जाती है, जिससे वह खराब नहीं होता है। आवश्यकता पड़ने या समय आने पर जरूरत के मुताबिक स्थानीय स्तर पर इस माल को सप्लाई कर दिया जाता है। इससे सामान लाने और ले जाने में होने वाले खर्चे में बचत होती है। इसका लाभ यह होता है कि वस्तु की कीमत भी कम हो जाती है। वर्ष 2042 की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर के मोबिलिटी प्लान को तैयार करने वाली अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी (यूएमटीसी) ने भी शहर में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की सिफारिश की है। अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी ने शहर का सर्वे कर चार कोनों पर चार पार्क तैयार करने की रिपोर्ट बनाई थी। इसमें भिंड रोड पर गिरगांव, मुरैना रोड पर रायरू, शिवपुरी लिंक रोड पर चौधरी का ढाबा के पास और झांसी रोड की तरफ सिकरौदा पर लॉजिस्टिक पार्क तैयार करने का प्रस्ताव बनाया गया है। इस प्रस्ताव को मप्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन के पास भी भेजा गया है। वहीं ग्वालियर-आगरा सिक्सलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के टेंडर जारी होते ही इसके अलाइनमेंट पर पड़ने वाले गांवों में जमीन में इंवेस्टमेंट की शुरूआत हो चुकी है। लोग एक्सप्रेस-वे के प्रस्तावित अलाइनमेंट के अगल-बगल जमीनें खरीदने के इच्छुक नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अब इन गांवों में किसानों से संपर्क कर जमीनों के सौदों के बारे में बातचीत शुरू की गई है।

उधर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार मप्र के 18 गांवों की 151 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें मुरैना के 17 गांवों की 150 हेक्टेयर और ग्वालियर के सुसेरा में 1.317 हेक्टेयर जमीन शामिल है। यह शासकीय और निजी खाते की भूमि है। सिंचित और असिंचित भूमि की कलेक्टर गाइडलाइन कम होती है। इसका जब अधिग्रहण होगा, तो कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से किया जाएगा।

इस सिक्सलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गत 7 दिसंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक मुरैना जिले की अंबाह तालुका के अंतर्गत ग्राम ऐसाह, लहर और दिमनी में कुल 133 सर्वे नंबरों की 29.582 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसी प्रकार ग्राम कोतवाल, नाका, बसहरी, पिलुआ, बिसेटा, गुलेंद्रा, रंचोली, खिरावली, रांसु, नयागांव, गडाजर, पिपरसेवा, पिनावली, उरहना में अलग-अलग 556 सर्वे नंबरों की 120.558 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। इसके लिए 28 दिसंबर तक दावे-आपत्ति मांगे गए हैं।

● **लोकेंद्र शर्मा**

> *ग्वालियर-चंबल अंचल में विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण कदम था अटल प्रोग्रेस-वे। वह अभी फाइलों में ही कैद है कि अब ग्वालियर में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने की तैयारी चल रही है।*

एक्सप्रेस-वे के किनारे जमीनों को लेकर बड़ी तैयारी

एक्सप्रेस-वे के लिए चिन्हित भूमि के अगल-बगल की जमीनों के दाम अगली कलेक्टर गाइडलाइन में दोगुना तक हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे किनारे की भूमि होगी। इसके अलावा लोग भी एक्सप्रेस-वे के किनारे जमीनें लेकर नए उद्योगों सहित अन्य बिजनेस खोलने की तैयारियों में जुट गए हैं। यही कारण है कि एनएचएआई के कार्यालय में भी लोग यह जानकारी लेने के लिए पहुंच रहे हैं कि किस-किस सर्वे नंबर की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। वे अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के पास ही जमीन खरीदने की इच्छा जता रहे हैं। इस एक्सप्रेस-वे के बगल से तैयार होने वाले लॉजिस्टिक पार्क की जिम्मेदारी एनएचएआई की सहयोगी संस्था नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी (एनएचएलएम) को सौंपी गई है। एनएचएलएम की टीम जल्द ही इसके लिए सर्वे की शुरूआत करेगी। संभावना जताई जा रही है कि मुरैना जिले के पिपरसेवा गांव में मौजूद उद्योग विभाग के औद्योगिक क्षेत्र का चयन इस लॉजिस्टिक पार्क के लिए किया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास कर लॉजिस्टिक पार्क तैयार किया जाएगा।

पटवारी की नई टीम नए साल में

संगठन से लेकर मीडिया टीम में होगा परिवर्तन

सूत्रों का कहना है कि पटवारी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद संगठन से लेकर मीडिया टीम में परिवर्तन होगा। हर प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से संगठन महामंत्री और मीडिया विभाग का अध्यक्ष नियुक्त करता है। हालांकि, पटवारी ने अभी सभी से अपना दायित्व निभाते रहने के लिए कहा है पर कुछ पदाधिकारियों ने पटवारी से कहा है कि वे उन्हें कार्यमुक्त कर अपने हिसाब से टीम बनाएं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में काम संभाल रहे अधिकतर वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी बदला जाएगा। उनके स्थान पर पीसीसी दफ्तर में जल्द ही पटवारी के करीबी नए चेहरे नजर आएंगे। पटवारी गंभीर और अनुशासित नेताओं को पीसीसी दफ्तर की जिम्मेदारी सौंपेगे। एक तरफ जहां कई पुराने पदाधिकारियों ने नई कार्यकारिणी में जगह पाने के लिए जोड़-तोड़ शुरू कर दी है, वहीं कई पदाधिकारियों ने पीसीसी कार्यालय से सामान समेटने की तैयारी कर ली है। कमलनाथ के पीसीसी चीफ रहते हाशिए पर पड़े कुछ पुराने पदाधिकारी पीसीसी दफ्तर में सक्रिय नजर आए। साथ ही कमलनाथ के करीबी कई पदाधिकारियों ने फिलहाल पार्टी कार्यालय से दूरी बना ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उचित समय पर नई कार्यकारिणी की घोषणा करेगी।

विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस का फोकस लोकसभा चुनाव पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शक्ति प्रदर्शन कर इस बात का संकेत दे दिया है कि हार को भूलाकर कांग्रेस नए जोश के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए नई टीम के साथ मैदान में उतरेंगे। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के आधार पर युवाओं को आगे किया जाएगा। यह ठीक उसी प्रकार से होगा जिस तरह से कमलनाथ के स्थान पर जीतू पटवारी को अध्यक्ष और उमंग सिंघार को विधायक दल का नेता बनाकर संदेश दिया है। वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके पटवारी टीम को अंतिम रूप देंगे। माना जा रहा है कि जनवरी में पटवारी अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान कर देंगे।

लोकसभा चुनाव मार्च में घोषित हो जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो पटवारी के सामने पहले चुनौती कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने की होगी। उन्हें निराशा के भाव से निकालकर भाजपा से मुकाबले के लिए प्रेरित करना होगा। प्रत्याशी चयन के साथ-साथ चुनिंदा लोकसभा सीटों पर अभी से काम करना होगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी जरूर हार गई पर छिंदवाड़ा सहित दस लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम के हिसाब से भाजपा को पराजय मिली है। इनमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, टीकमगढ़, मंडला, बालाघाट, रतलाम, धार और खरगोन सीट शामिल हैं। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मप्र कांग्रेस ने इसी साल जनवरी में जंबो कार्यकारिणी का ऐलान किया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में 50 उपाध्यक्ष, 150 महासचिव और 64 नए जिला अध्यक्ष बनाए गए थे। सालभर के अंदर ही कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग हो गई। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बड़ी संख्या में संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्तियां की थीं।

गौरतलब है कि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के साथ ही कांग्रेस की कार्यकारिणी स्वत: भंग हो गई है। तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए 50 से ज्यादा मोर्चा, प्रकोष्ठों का गठन किया था। इनके जरिए सैनिकों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, विभिन्न समाजों आदि को कांग्रेस के पक्ष में एकजुट करने का प्रयास किया गया था। प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर इन मोर्चा, प्रकोष्ठों में नियुक्तियां की गई थीं। हालांकि पार्टी को चुनाव में इन मोर्चा, प्रकोष्ठ के गठन का फायदा नहीं मिला। नए पीसीसी चीफ के नाम के ऐलान के साथ ही ये सभी मोर्चा, प्रकोष्ठ भंग हो गए हैं। इसके साथ ही नई कार्यकारिणी के गठन की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। जनवरी में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी जल्द घोषित किए जाने की प्रमुख वजह लोकसभा चुनाव नजदीक होना बताया जा रहा है। पटवारी नई ऊर्जा और नई टीम के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। सूत्रों का कहना है कि नई कार्यकारिणी में पटवारी के विश्वास पात्र और युवा चेहरे ज्यादा दिखाई देंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नई कार्यकारिणी में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए चार कार्यकारी अध्यक्ष भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। यह प्रयोग कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बनते समय भी किया था। उस समय जीतू पटवारी कार्यकारी अध्यक्ष थे। पटवारी और उमंग सिंघार मालवांचल से आते हैं। जबकि, विधायक दल के उप नेता बनाए गए हेमंत कटारे ग्वालियर अंचल से आते हैं। विंध्य, महाकौशल, बुंदेलखंड और मध्य भारत से कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर संतुलन साधा जा सकता है।

सत्ता के सेमीफाइनल में करारी हार के बाद फाइनल मैच में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कांग्रेस ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल अब कांग्रेस के सभी 66 विधायक सदन के अलावा अपने-अपने क्षेत्रों में अलग-अलग मुद्दों को लेकर मुखर होंगे। बात सिर्फ प्रेस वार्ता की नहीं बल्कि सड़कों पर आंदोलन के साथ होगी। नए साल में नए प्लानिंग के तहत क्षेत्रगत मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए आंदोलन होंगे। खास बात यह है कि प्रदेश और जिला पदाधिकारियों के अलावा कांग्रेस विधायकों की भूमिका ही अहम होगी। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, आदिवासियों पर अत्याचार समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेसी सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि संगठन की नई प्लानिंग के मुताबिक सरकार के चुनावी वादों को भी पूरा करने पर जोर होगा। फिर बात बिजली, फसल खरीदी या लाड़ली बहना योजना के संचालन की ही क्यों न हो।

● **अरविंद नारद**

लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी तीनों नए क्रिमिनल लॉ पास हो गए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में बिलों को पेश किया और कानून में बदलाव के बारे में पूरी जानकारी दी। अब राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे और देश में लागू हो जाएंगे।

राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह

लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल पास हो गए हैं। संसद के दोनों सदनों ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) बिल पारित किए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा, ये कानून नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखेंगे और महिलाओं- बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। राज्यसभा में तीनों विधेयकों की मंजूरी के बाद अमित शाह ने कहा, आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज भारत को अपना नया आपराधिक न्याय कानून मिल गया है। इस गौरवपूर्ण क्षण पर सभी भारतीयों को बधाई। संसद में पारित तीन विधेयक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों की जगह लेंगे और स्वदेशी न्याय प्रणाली के दशकों पुराने सपने को साकार करेंगे। नई न्याय प्रणाली सभी को पारदर्शी और त्वरित न्याय देने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों से सशक्त होगी। इतिहास में पहली बार हमारे कानून आतंकवाद, संगठित अपराधों और आर्थिक अपराधों को परिभाषित करते हैं। कानून से बचने के हर रास्ते को रोकते हैं।

भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 में राजद्रोह से लेकर फर्जी खबरों और मॉब लिंचिंग तक में सजा के प्रावधान बदले गए हैं। आईपीसी में धारा 124ए में राजद्रोह को लेकर प्रावधान किया गया है। इसमें दोषी को 3 साल से लेकर उम्रकैद की सजा का प्रावधान था। इस कानून को निरस्त कर दिया है। अब बीएनएस में राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है। इसकी व्यापक परिभाषा दी गई है। देशद्रोह में प्रावधान किया गया है कि देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है और इसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बीएनएस में धारा 150 में देशद्रोह से जुड़ा प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को कानून के दायरे में लाया जाएगा। बीएनएस में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नया कानून सरकार की आलोचना करने पर दंडित नहीं करेगा। शाह ने कहा, अब हम एक आजाद देश हैं। किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करने पर किसी को जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। जो लोग देश के खिलाफ बोलते हैं उन्हें जेल जाना चाहिए।

अब शादी के नाम पर गुमराह करने या पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा होगी। बीएनएस में धोखाधड़ी या झूठ बोलकर किसी महिला से शादी करने या फिर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में खंड 69 में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने के बारे में प्रावधान है। शादी के नाम पर धोखेबाजी या पहचान छिपाकर शादी करने को अपराध घोषित किया है। लव जिहाद से निपटने के लिए सजा तय की गई है। क्लॉज 69 कहता है कि जो कोई भी धोखे से या महिला से शादी करने का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाता है और बाद में शादी करने से मुकर जाता है तो ऐसे मामले अपराधी की श्रेणी में आएंगे। दोषी को 10 साल तक की कारावास की सजा मिल सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

आईपीसी में धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। इसमें वो 7 परिस्थितियां भी बताई गईं हैं, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप माना जाता है। वहीं, आईपीसी में धारा 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि, बीएनएस में इसे धारा 63 और 64 में परिभाषित किया गया है। धारा 64 में इन अपराधों के लिए सजा बताई गई है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। 18 साल से कम उम्र की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में अभी तक

यह कानून भी बदले नजर आएंगे...

नए कानून में कैदियों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। एक-तिहाई सजा काट चुके अंडर ट्रायल कैदी के लिए जमानत का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सजा माफी को लेकर भी कई प्रावधान किए गए हैं। अगर मौत की सजा मिली है तो उसे ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास है तो 7 साल की सजा काटनी होगी। 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है तो कम से कम 3 साल जेल में रहना पड़ेगा। पहले आईपीसी की धारा 377 में अप्राकृतिक यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, लेकिन नए कानून यानी बीएनएस में इसे निरस्त कर दिया गया है। हालांकि, धारा 377 पूरी तरह हटा दिए जाने से नई चिंताएं भी बढ़ गईं हैं। क्योंकि यह प्रावधान अभी भी गैर-सहमति वाले यौन कृत्यों से निपटने में मददगार है। खासकर जब रेप कानूनों में लैंगिक आधार पर भेदभाव जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में समलैंगिक रिश्तों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला ऐतिहासिक फैसला दिया था। आईपीसी में धारा 153बी का प्रावधान है। इसमें राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप और दावों को लेकर नियम हैं। बीएनएस ने यहां एक नया प्रावधान किया है। इसमें झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करने को अपराध माना गया है।

दोषी को 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित बीएनएस की धारा 70(2) के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है। 16 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म के लिए सजा बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। नाबालिग से दुष्कर्म में मौत की सजा का भी प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म पर कम से कम 20 साल जेल की सजा या मौत की सजा होगी।

अब महिलाओं को भी आरोपी बनाया जाएगा। बलाकार का कानून सिर्फ महिलाओं को लेकर लागू होता है। बीएनएस ने कुछ अन्य कानूनों, विशेष रूप से बच्चों से संबंधित कानूनों में बदलाव किया है। नाबालिगों के अपहरण से संबंधित अपराध में आईपीसी की धारा 361 अलग-अलग आयु सीमा निर्धारित करती है। पुरुष के लिए 16 और महिला के लिए 18 वर्ष। बीएनएस ने इसे दोनों के लिए 18 साल निर्धारित कर दिया है। महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने (आईपीसी की धारा 354ए) और ताक-झांक (आईपीसी 354सी) के अपराध में अब बीएनएस के तहत आरोपियों के लिए जेंडर न्यूट्रैलिटी लागू होगा। यानी अब महिलाओं पर भी कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

सरकार ने पहली बार मॉब लिंचिंग को लेकर सख्ती से कार्रवाई का मन बना लिया है। यही वजह है कि मॉब लिंचिंग के दोषी को फांसी की सजा तक देने की व्यवस्था की है। अभी तक मॉब लिंचिंग के लिए सजा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग को लेकर धारा 101(2) में सजा का प्रावधान है। इसके तहत पांच या उससे ज्यादा लोग जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर हत्या करते हैं तो आजीवन कारावास से लेकर फांसी की सजा तक मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में केंद्र से मॉब लिंचिंग पर एक अलग से कानून लाने पर विचार करने के लिए कहा था। बीएनएस में हत्या के लिए धारा 101 में सजा का प्रावधान है। इसमें दो सब-सेक्शन हैं। धारा 101(1) कहती है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है। साथ ही उस पर जुर्माना

भी लगाया जाएगा। इसके अलावा, बीएनएस में हत्या की कोशिश के मामले में धारा 107 के तहत एक्शन होगा। इसी तरह, गैर-इरादतन हत्या के मामले में पुलिस के पास जाने और पीड़ित को अस्पताल ले जाने पर कम सजा होगी। लेकिन हिट एंड रन यानी घटना के बाद पीड़ित को छोड़कर भागने पर 10 साल की सजा होगी।

अब बीएनएस में भगोड़े अपराधियों पर सख्ती की जाएगी। उनकी गैरमौजूदगी में कोर्ट में ट्रायल भी हो सकेगा। अब तक किसी भी अपराधी या आरोपी पर ट्रायल तभी शुरू होता था, जब वो अदालत में मौजूद हो। लेकिन अब फरार घोषित अपराधी के बगैर भी मुकदमा चल सकेगा। यानी कोर्ट में कार्रवाई नहीं रुकेगी। फरार आरोपी पर आरोप तय होने के तीन महीने बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। पहले 19 अपराधों में ही भगोड़ा घोषित कर सकते थे, अब 120 अपराधों में भगोड़ा घोषित करने का प्रावधान किया गया है।

बीएनएस में पहली बार संगठित अपराध से निपटने को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाया गया है। संगठित अपराध के तहत सिंडिकेट्स या गिरोह द्वारा आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। जिनमें सबसे चर्चित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 है। ये विशेष कानून निगरानी की व्यापक शक्तियां निर्धारित करते हैं। नए कानून में संगठित अपराध करने के प्रयास और संगठित अपराध करने के लिए सजा एक ही है। लेकिन इस आधार पर अंतर किया गया है कि मौत कथित अपराध के कारण हुई है या नहीं।

मौत से जुड़े मामलों के लिए आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन जहां अपराध के कारण कोई मृत्यु नहीं होती है तो वहां अनिवार्य न्यूनतम सजा पांच साल निर्धारित की गई है, इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। छोटे संगठित अपराध की एक अलग श्रेणी भी रखी गई है, जो चोरी, छीना-झपटी, धोखाधड़ी, अनाधिकृत टिकटों की बढ़ती बिक्री, सट्टेबाजी या जुआ, सार्वजनिक परीक्षा प्रश्न पत्रों की बिक्री को अपराध मानती है। इससे पहले जो विधेयक लाया जा रहा था, उसमें छोटे संगठित अपराध की परिभाषा में व्यापक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन नए बिल में ये शब्द हटा दिया गया है। हालांकि, इस प्रावधान का उद्देश्य रोजमर्रा की पुलिसिंग में छोटे कानून और व्यवस्था के मुद्दों से निपटना है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह सामान्य चोरी आदि से कैसे अलग होगा। पहले आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी। लेकिन बीएनएस में आतंकवाद को लेकर प्रावधान किया गया है। बीएनएस आतंकवाद को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाता है।

● **जितेंद्र तिवारी**

पुलिस हिरासत केवल 15 दिनों के लिए

नए कानूनों के तहत पुलिस हिरासत केवल 15 दिनों के लिए होगी। हालांकि, इसका प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और फिर चिकित्सीय जरूरत के कारण अस्पताल भेजा जाता है, तो अदालत द्वारा फिर से हिरासत की मांग करनी होगी और इस अवधि के दौरान, अदालत व्यक्ति को जमानत भी दे सकती है। गृहमंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार देश में ऐसे कानून होंगे जो भगोड़ों की गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करेंगे। पहली बार हमारे कानून सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की व्यवस्था करते हैं। न्याय के लिए सजा के हमारे सभ्यतागत सिद्धांत को पुनर्जीवित करते हैं। अत्याधुनिक तकनीकों से सशक्त न्यू इंडिया की यह नई न्याय प्रणाली देशवासियों को पारदर्शी और त्वरित न्याय देने का काम करेगी। उन्होंने कहा, मैं हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने, हमारे औपनिवेशिक अतीत से दूर रहने और गुलामी की छापों को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। ये बिल लोकसभा से मंजूरी मिलने के एक दिन बाद राज्यसभा से पारित हो गए।

कहीं जीएम फल तो नहीं खा रहे आप

अगर आप भी विदेशी यानी आयातित फल और सब्जियों के प्रति आकर्षित हैं और उसका उपभोग करते हैं तो सावधान होने की जरूरत है। भारत में सिर्फ आयातित प्रोसेस्ड फूड ही नहीं बल्कि आयात होने वाले ताजा फलों और सब्जियों में भी जेनिटिक मोडिफाई ऑर्गेनिज्म (जीएमओ) होने की आशंका है। क्योंकि देश की सर्वोच्च खाद्य नियामक संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसआई) के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बीते पांच साल में जीएमओ कंटेंट वाला कोई ताजा फल या सब्जी भारत में आयात किया गया है या नहीं। एफएसएसएआई ने इसके लिए प्रयोगशाला में कोई जांच भी नहीं की है। इतना ही नहीं आयात होने वाले इन ताजे फलों और सब्जियों में किसी खतरनाक रसायन के होने और उनकी गुणवत्ता के बारे में भी नियामक के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह खुलासा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत हासिल की गई जानकारी से हुआ है।

अभी तक दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में वैज्ञानिक द्वारा कई जीएम किस्मों को उगाया जा चुका है। इनमें फल और सब्जियां भी शामिल हैं, जैसे- टमाटर, मकई, आलू, बैंगन, पपीता, सेब, खीरा, अल्फाअल्फा आदि। भारत में इन फल और सब्जियों को मिलाकर कुल 24 फसलें ऐसी हैं जिनमें जीएम की आशंका को देखते हुए आयात को प्रतिबंधित किया गया है। इनमें अल्फाअल्फा, सेब, अर्जेंटीना कैनोला, बैंगन, फली, चिकरी, दाल, अलसी के बीज, मक्का, तरबूज, पपीता, अनानास, प्लम, पोलिश कैनोला, आलू, चावल, सेफ्लॉवर, सोयाबीन, स्कवाश, चुकंदर, गन्ना, शिमला मिर्च, टमाटर और गेहूं शामिल हैं। लंदन स्थित दुनिया की सबसे पुरानी वैज्ञानिक अकादमी रॉयल सोसाइटी की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के करीब 28 देशों में 17.97 करोड़ हेक्टेयर जमीन (दुनिया की 10 फीसदी खेती योग्य जमीन) पर जीएम फसलें उगाई जा रही हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), ब्राजील और अर्जेंटीना सबसे बड़े जीएम उत्पादक हैं। मौजूदा वक्त में जीएम फलों और सब्जियों की संख्या एक दर्जन से भी ज्यादा है। हालांकि भारत में सिर्फ जीएम कपास के ही उत्पादन और आयात को मंजूरी दी गई है जबकि जीएम सरसों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

भारत में बिना एफएसएसएआई की अनुमति के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 किसी भी जीएम फूड के आयात, निर्माण, इस्तेमाल और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। हालांकि, एक्सपर्ट यह मानते हैं कि भारत इस वक्त जिन फलों और सब्जियों को आयात करता है और जिन्हें नॉन जीएमओ बताया जा रहा है, उनमें भी जीएम कंटेंट हो सकता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, बीते एक दशक के दौरान भारत में ताजा फलों और सब्जियों का आयात 25 फीसदी बढ़ा है। फलों में पपीता के बाद 2015 में यूएसए और 2017 में कनाडा में जीएम सेब आर्कटिक एपल को भी व्यावसायिक मंजूरी दी गई है। बीते एक दशक में विदेशों से खासतौर से जीएम उत्पादक देशों से भी भारत में फल और सब्जियों के आयात में काफी बढ़ोतरी हुई है। मिसाल के तौर पर प्रमुख जीएम उत्पादक देश अमेरिका से बीते पांच साल (2018-2022) में 1,81,102.49 लाख रुपए का सेब आयात किया गया। यह इसी अवधि में भारत में कुल सेब आयात 1,08,7107.29 लाख रुपए का 17 फीसदी है। 2018-19 में अमेरिका से सेब आयात की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी थी। अमेरिका से सेब आयात में आई गिरावट की एक बड़ी वजह 70 फीसदी आयात टैरिफ, कोविड और नॉन जीएमओ सर्टिफिकेट है। हालांकि, हाल ही में जी-20 की बैठक में अमेरिका के आयात शुल्क को कम करने का फैसला किया गया है। इससे सेब आयात एक बार फिर बढ़ सकता है। इसके अलावा भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना से सबसे अधिक सोयाबीन तेल का आयात करता है।

इन फलों और सब्जियों में जीएम कंटेंट है या नहीं इस बारे में खाद्य उत्पादों के मानक और गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था एफएसएसएआई को किसी तरह की स्पष्ट जानकारी नहीं है। एफएसएसआई ने एक सवाल का 3 अक्टूबर, 2023 में दिए गए एक जवाब में कहा है कि उप्र के गाजियाबाद में स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (एनएफएल) ने बीते पांच साल में किसी भी फल या सब्जी में जीएम कंटेंट की जांच नहीं की है। इसके अलावा एफएसएसएआई के इंपोर्ट डिवीजन ने 15 फरवरी, 2023 को दिए गए आरटीआई के एक जवाब में कहा कि फलों और सब्जियों की गुणवत्ता से जुड़ी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। आयातित फलों और सब्जियों की गुणवत्ता को लेकर एफएसएसएआई के इंपोर्ट डिवीजन ने 15 फरवरी, 2023 को दिए गए अपने एक जवाब में कहा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (एफएसएस) इंपोर्ट रेग्युलेशन 2017 के तहत कस्टम अथॉरिटी के जरिए हर वह खाद्य उत्पाद को क्लीयरेंस के लिए जब एफएसएसआई को भेजा जाता है, तब वह डॉक्युमेंट्स की स्क्रूटनी, विजुअल इंस्पेक्शन, सैंपलिंग और टेस्टिंग का विषय होता है।

● **डॉ. जयसिंह सेंधव**

प्रयोगशाला है लेकिन जांच नहीं

एफएसएसएआई के पूर्व चेयरमैन पवन अग्रवाल का कहना है कि हमारी प्रयोगशालाएं सभी तरह के खाद्य उत्पादों में जीएम खोजने में अभी समर्थ नहीं हैं। उनके कार्यकाल में मसौदा विकसित किया जा रहा था। हालांकि अभी तक वह पास नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि आयात होने वाले कंसाइनमेंट में सैंपल में जीएम कंटेंट की जांच होनी चाहिए। जीएम जांच के लिए देश में निजी प्रयोगशालाएं भी मौजूद हैं, जो किसी खाद्य उत्पाद में 0.01 फीसदी जीएम कंटेंट तक की जांच कर सकती हैं। देश में पीपीपी मोड में मौजूद पांच राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं इस तरह की जांच करने के लिए बाध्य और समर्थ नहीं हैं। 2020 में नेशनल फूड लैबोरेटरी (एनएफएल) के संबंध में निकाले गए टेंडर में स्पष्ट लिखा था कि जल्द ही जीएम रेग्युलेशन के मसौदे को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद लैब को जीएम जांच भी करनी होगी। हालांकि अभी तक जीएम रेग्युलेशन के मसौदे को मंजूरी नहीं मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि लैब अभी तक जीएम जांच के लिए समर्थ ही नहीं हैं।

बढ़ेगा निवेश, आएगी नौकरियों की बहार

मप्र को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में अब राजधानी भोपाल के आसपास उद्योगों का विस्तार हो रहा है। जिले के अचारपुरा, अगरिया छापर, अजामपुर, बीलखेड़ी, बैरसिया रोड पर बड़ी संख्या में उद्योग-धंधे लग रहे हैं। नए साल में राजधानी में उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी। उद्योगों की स्थापना के लिए शासन की नीतियों के तहत काम करते हुए सिंगल विंडो के जरिए अनुमतियां देने की कोशिश होगी। जानकारी के अनुसार नए साल में भोपाल के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 1243 करोड़ का निवेश होगा। इससे 22 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग विभाग के सूत्रों का कहना है मप्र में भोपाल के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए नई इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जमीनें देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

दरअसल, सरकार की योजना है कि पीथमपुर की तरह मध्यभारत के भोपाल को बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाया जाए। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल, देश-विदेश के कई बड़े निवेशक भोपाल के आसपास औद्योगिक इकाईयां स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए सरकार ने राजधानी के आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में निवेश करने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। जानकारी के अनुसार राजधानी के आसपास रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं।

राजधानी के आसपास स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को मिलने वाली छूट और अनुमतियों की लंबी फेहरिस्त को कैसे आसान किया जाए इस पर गत दिनों कलेक्टोरेट में मंथन किया गया। कलेक्टर और जिला उद्योग केंद्र के अफसरों की बैठक में तय हुआ कि पूर्व के जो प्रस्ताव आए हैं, उनको तेजी से जगह देकर, उनको यहां डेवलप होने दिया जाए। ताकि भोपाल में और उद्योगपति आएं। अभी तक के सात क्लस्टर में भोपाल के अचारपुरा, अगरिया छापर, अजामपुर, बीलखेड़ी, बैरसिया रोड पर जमीनें दी जा रही हैं। इसके तहत 1243 करोड़ का निवेश इन क्लस्टर में होगा। इससे 22 हजार लोगों के रोजगार मिलेगा। हालाकि इसमें से कुछ इकाईयां स्थापित हो चुकी हैं, इनको सब्सिडी देकर और जान डालनी है। रोजगार की तलाश में इंदौर, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में पलायन कर रहे लोगों को भोपाल में ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि जहां विकास की जरूरत हो, वहां विकास कार्य कराए जाएं। सड़क, पानी, बिजली की जरूरत के लिए विभागों से समन्वय कर काम शुरू हों ताकि उद्योग तेजी से लगे और रोजगार के अवसर भी बढ़े।

हजारों को मिलेगा रोजगार

प्रदेश में रोजगार के मद्देनजर उन उद्योगों को जल्द से जल्द स्थापित करने जमीनें आवंटित की जा रही हैं, जिनसे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। भोपाल ही नहीं आसपास के जिलों के लोगों को भी यहां रोजगार मिलेगा। जिला उद्योग केंद्र के अफसरों के साथ मिलकर नए उद्योगों को जमीनें आवंटित करते जा रहे हैं। नई इंडस्ट्री के लगने के बाद हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। फर्नीचर क्लस्टर 100 एकड़ पर बनेगा। यहां 350 करोड़ का निवेश होगा और 10 हजार लोगों को नौकरियां मिलेंगी। 28 एकड़ में 150 करोड़ की लागत से आरा मशीन लगेगी और 2 हजार नौकरियां लगेंगी। 10 एकड़ में 34.45 करोड़ की लागत से प्लास्टिक उद्योग स्थापित होगा और 605 लोगों को रोजगार मिलेगा। फूड उद्योग 37 एकड़ में बनेगा और 152 करोड़ का निवेश होगा। इसमें 1995 नौकरियां मिलेंगी। वहीं 5 एकड़ में 15 करोड़ की लागत से रेलवे इंजीनियरिंग का उद्योग स्थापित होगा और 500 नौकरियां मिलेंगी। 21 एकड़ में लोहा व्यापारी संघ स्थापित होगा। 108.75 करोड़ रुपए के निवेश होंगे और 1162 नौकरियां मिलेंगी। 71 एकड़ में प्लास्टिक लास में 516 करोड़ का निवेश होगा और 2100 नौकरियां मिलेंगी। वहीं फार्मा क्लस्टर 23 एकड़ में बनेगा और 167 करोड़ का निवेश होगा। जिसमें 900 नौकरियां मिलेंगी।

राजधानी के उद्योगों में एग्रीकल्चर के उपकरण सिंचाई के पाइप के नए मॉडल बनने शुरू हो गए हैं। वहीं रेलवे की लाइट से लेकर फ्लश, बाथरूम, सीट, फर्श भोपाल में बन रहे हैं। हाल ही में गोलखेड़ी में राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट को जगह दी गई है। फूड उद्योग में गोविंदपुरा में तीन यूनिट अभी हाल में अपडेट होकर मिठाई के बड़े ऑर्डर बना रही हैं। जल्द ही ये यूनिट उद्योगों को लिए दी जा रही जगह में शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे ही ईवी के दो बड़े प्रोजेक्ट भोपाल में जल्द शुरू होने जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि भोपाल में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो समस्याएं और बाधाएं आ रही हैं उनको दूर किया जा रहा है। इस संबंध में जिला उद्योग केंद्र के अफसरों के साथ बैठक हुई है। इसमें अनुमति और सब्सिडी की राह को आसान कर शासन की नीति के तहत काम किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने निवेशकों को कानूनी राहत देते हुए उद्योगों की स्थापना और परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश 2023 जारी किया है। इसके तहत राज्य में उद्योग लगाने के लिए अब तीन साल तक किसी भी कानूनी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवधि में किसी भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी को इन उद्योगों के निरीक्षण का अधिकार नहीं होगा। तीन वर्ष इन उद्योगों को केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत भी अनिवार्य अनुमतियों से छूट रहेगी। अध्यादेश में कहा गया है कि राज्य सरकार एक राज्य स्तरीय साधिकारी समिति (एसएलईसी) गठित करेगी, जो निवेश प्रस्ताव के आधार पर उद्योगों को एक प्रमाण पत्र जारी करेगी। इसके आधार पर निवेशक अपने उद्योग की स्थापना का काम प्रारंभ कर सकेंगे। उद्योग संबंधी किसी भी तरह का विवाद सामने आने पर यह समिति ही उसका निपटारा करेगी। राज्य के राजस्व, नगरीय निकाय, पंचायत राज, श्रम, विद्युत, वाणिज्यिक कर, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जल संसाधन सहित सभी विभागों की अनुमति से छूट होगी। अध्यादेश में कहा गया है कि उद्योग तीन वर्ष तक आवश्यक सभी अनुमति प्राप्त कर लेंगे।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

किसानों की मौत पर बैंक अफसरों का खेल

कर्जदार किसानों की मौत हो गई, लेकिन बैंक अफसरों ने उन पर रहम नहीं किया। अफसरों ने उनके खातों की लोन लिमिट बढ़ाई और खुद पैसा निकाल लिया। ऐसा एक या दो नहीं, बल्कि 17 मृत किसानों के साथ हुआ है। ये कहानी बैतूल के घोड़ाडोंगरी की है। यहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अफसरों ने पूरी प्लानिंग के साथ 81 खाताधारकों के अकाउंट से 98 लाख रुपए निकाल लिए। इनमें से 65 खाताधारक ऐसे थे जो लंबे समय से बैंक ही नहीं गए और उन्होंने लोन लिमिट बढ़ाने का कोई आवेदन भी नहीं दिया था।

बैंक अफसर तीन साल तक घोटाले को अंजाम देते रहे। जब मामला खुला तो बैंक ने ही दो साल तक इंटरनल जांच की। जांच के बाद मामला ईओडब्ल्यू को सौंपा गया। 14 दिसंबर को ईओडब्ल्यू ने इस मामले में 5 बैंक कर्मचारियों के साथ 9 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस घोटाले को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया और खाताधारकों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की घोड़ाडोंगरी शाखा के बैंक मैनेजर समेत 13 कर्मचारियों ने इस घोटाले को अंजाम दिया। सभी ने मिलकर बैंक के जरूरी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की, खाताधारकों के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के फर्जी निशान के जरिए पैसा निकाला। खाताधारकों को पैसा निकाले जाने की खबर तक नहीं लगी। क्योंकि ज्यादातर खाताधारकों ने लंबे समय से खातों से किसी तरह का लेन-देन नहीं किया था।

ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच में पाया कि बैंक मैनेजर पीयूष सैनी, असिस्टेंट मैनेजर दीपक सोलंकी और हैड कैशियर राजेश खासदेव ने ऐसे खातों की लिस्ट तैयार की। जुलाई 2021 में करीब 68 खातों की लोन लिमिट बढ़ाई गई। उसी दिन खातों में अमाउंट को क्रेडिट किया गया और उसी दिन खातों से पैसे भी निकाल लिए। बैंक कर्मचारियों ने चेक में हस्ताक्षर की जगह अंगूठे का निशान लगाकर पैसे निकाले। जबकि बैंकिंग सिस्टम में चेक पर साइन किए जाते हैं अंगूठा नहीं लगाया जाता। जिन खातों से अंगूठे के निशान लगाकर पैसे निकाले गए उन्हें सत्यापित नहीं किया, न ही बैंक के सीबीएस सिस्टम में दर्ज किया। किसी भी खाताधारक के हस्ताक्षर के सैंपल बैंक के सीबीएस सिस्टम पर दर्ज नहीं किए गए। हैड कैशियर ने चेक से विड्रॉल डिटेल्स को सिस्टम में दर्ज ना कर वाउचर के रूप में दर्ज किया।

ईओडब्ल्यू ने जांच में पाया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कुल 63 लाख 79 हजार 810 और टर्म लोन खातों में 34 लाख 60 हजार 176 रुपए का घोटाला हुआ है। जांच में ये भी पाया कि 17 खाताधारकों की तो काफी पहले मौत हो चुकी थी। इस घोटाले की रकम का ज्यादातर हिस्सा तत्कालीन बैंक मैनेजर पीयूष जैन के खाते में आया था। ईओडब्ल्यू की जांच के मुताबिक पीयूष जैन के खाते में 89 लाख 14 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। वहीं, असिस्टेंट मैनेजर दीपक सोलंकी के खाते में 1 लाख रुपए और हैड कैशियर राजेश खासदेव के खाते में 13 बार में 3 लाख 91 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए।

घोड़ाडोंगरी के जुदाली गांव में रहने वाले हन्नू गोंड के खाते से पैसा निकाला गया था। हन्नू गोंड की मौत साल 2013 में हो चुकी है। हन्नू की बहू जुगती बाई ने बताया कि ससुर ने बैंक से कर्ज लिया था उसे चुकाने का नोटिस उनके पास आया था। इसके बाद उन्होंने जहर खा लिया, लेकिन उन्होंने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। जब उन्हें अस्पताल लेकर गए तब उन्होंने बैंक के कर्ज के बारे में बताया। उन्होंने मौत के 10 साल बाद फिर कर्ज लिया, ऐसा कैसे संभव है। बैंक अधिकारियों ने 17 मृत किसानों के खातों की लोन लिमिट बढ़ाकर पैसे निकाले। मृतकों में कोईलारी का बच्चूलाल भी शामिल था, जो जीवित है। बच्चूलाल का कहना है कि किसान क्रेडिट कार्ड में लोन लिमिट बढ़ाने की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे तो ये भी जानकारी नहीं है कि मेरे नाम का केसीसी बना है। मुझे तो डॉक्टर शर्मा ने बताया था कि केसीसी बना है। इस घोटाले के एक और पीड़ित राजू उइके का कहना है कि मैंने कोई लोन नहीं लिया, न ही पैसे निकाले। 5-6 दिन पहले सेंट्रल बैंक के कुछ अधिकारी जांच के लिए आए थे। मेरे साथ धोखा हुआ है। इससे पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे साथ कई और लोग हैं जिन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भी हुआ घोटाला

कुल 81 खातों में से 8-9 खाते ऐसे भी हैं, जिनमें किसान क्रेडिट कार्ड के इतर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत घोटाला किया गया। ये टर्म लोन खाते हैं। इन खातों में नियम के विरुद्ध टर्म लोन स्वीकृत किया गया और राशि का दुरुपयोग किया गया। जिन आवेदकों के नाम पर लोन मंजूर हुआ, जांच में उनके पास यूनिट ही नहीं पाई गई। जबकि इस योजना के अंतर्गत आवेदकों को विशेष व्यवसाय के लिए लोन दिया जाता है। लोन मंजूर होने के बाद बैंक के अधिकारी पूरी जांच करते हैं। इस घोटाले में जिन आवेदकों के नाम पर स्वरोजगार लोन जारी किया गया है, उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। क्योंकि बैंककर्मियों के साथ वे भी इस साजिश में शामिल हैं। ईओडब्ल्यू के जांच अधिकारी ने बताया कि इस पूरे घोटाले का खुलासा बैंक ऑडिट से सामने आया था। इसके बाद सेंट्रल बैंक के रीजनल मैनेजर धर्मेंद्र कुमार पांडेय की शिकायत पर मामले की जांच की गई। इस तरह पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ। सेंट्रल बैंक के रीजनल मैनेजर धर्मेंद्र कुमार पांडेय और रीजनल मैनेजर नीलेश खत्री के मुताबिक ऑडिट में घोटाले की जानकारी मिलने के बाद बैंक ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किया। खाताधारकों का सत्यापन किया। उसी के बाद मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू को की। इस पूरी कार्रवाई में डेढ़ से दो साल का वक्त लगा।

हर जगह है ठगों का साया

महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में जिस तरह से ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, उससे समाज और भी ज्यादा असुरक्षित होता जा रहा है। ठग जिस तरह से शातिर तरीके से लोगों को शिकार बना रहे हैं, उसमें डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक शामिल हैं। यानी ठग किसी को भी नहीं छोड़ रहे; चाहे वह सेना अधिकारी हों, पुलिसकर्मी हों या फिर जज ही क्यों न हों। कोई भी ठगों से नहीं बच पाया है। 10वीं, 12वीं तक पढ़े-लिखे ठग अच्छे-अच्छों को बड़ी आसानी से ठगी के शिकार बना रहे हैं। देखा जाए, तो जीवन में हर व्यक्ति कहीं-न-कहीं ठगी का शिकार जरूर होता है। हम अक्सर कहते हैं कि अरे, तुम्हें तो ठग लिया। यह समान इतने का बिक रहा है, तुम इतने में खरीद लाए। बात समान तक ही नहीं है, यह धर्म-कर्म से लेकर जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा है। लेकिन यह सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संचार क्रांति के इस दौर में अब यह एक ऐसा रूप ले चुका है, जो हर किसी को डराने वाला है। इस अपराध का नाम है- साइबर क्राइम; क्योंकि इसमें फंसकर लोग हर साल अरबों रुपए गंवा रहे हैं। आने वाले समय में यह कितना व्यापक रूप ले चुका होगा, इसका अनुमान भी लगाया जा चुका है। डेटा के ऊपर काम करने वाली दुनिया की जानी-मानी वेबसाइट स्टेटिस्टा के साइबर सिक्योरिटी आउटलुक ने दुनियाभर में अगले पांच वर्षों में ठगी के मामले में बेहताशा वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया है।

आउटलुक के जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में 8.44 ट्रिलियन डॉलर की ठगी हुई थी, जो दुनिया के कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा है और यह 2027 तक बढ़कर 23.84 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के टॉप-5 अर्थव्यवस्था वाले कई देश इसमें समा जाएंगे। इस वेबसाइट की रिपोर्ट में साइबर अपराध को डेटा की क्षति और विनाश के रूप में परिभाषित किया गया है; जिसमें चुराया हुआ पैसा, खोई हुई उत्पादकता, बौद्धिक संपदा की चोरी, व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा की चोरी, गबन, धोखाधड़ी, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में हमले के बाद व्यवधान, फोरेंसिक जांच, हैक किए गए डेटा और सिस्टम की बहाली और विलोपन और प्रतिष्ठा के नुकसान को दर्शाया गया है। वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2017 में सबसे ज्यादा ठगी बिना-पेमेंट व बिना डिलीवरी के नाम पर हुई है, जिसमें 41 फीसदी लोग ठगे गए। पर्सनल डाटा हैकिंग में 15.3 फीसदी लोग शिकार बने। फर्जी ईमेल के जरिये 12.5 फीसदी लोग ठगी का शिकार हुए। साइबर अपराधियों ने पहचान चोरी कर 8.7 फीसदी लोगों को ठगी का शिकार बनाया। वहीं क्रेडिट कार्ड के नाम पर 7.5 फीसदी लोग ठगी के शिकार हुए। 7.4 फीसदी सेक्सटॉर्शन केस में तो, 5.4 फीसदी लोग तकनीकी सहायता के नाम पर ठगी का शिकार हुए। निनेश के नाम पर 1.5 फीसदी लोग ठगी का शिकार हुए। वहीं पांच साल बाद ठगी के तरीके में काफी परिवर्तन देखे गए।

2022 में सबसे ज्यादा ईमेल व अन्य माध्यमों से साइबर अपराधियों ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैकिंग के जरिये 53.2 फीसदी लोगों को शिकार बनाया। 10.4 फीसदी लोग पर्सनल डाटा हैंकिग के जरिये ठगे गए तो, वहीं बिना पेमेंट व बिना डिलीवरी के माध्यम से 9.2 फीसदी लोग ठगी का शिकार बने। 5.4 फीसदी लोग इनवेस्टमेंट के नाम पर ठगे गए। 5.8 फीसदी लोग तकनीकी सहायता के नाम पर ठगी के शिकार बने तो, वहीं 7 फीसदी लोग सेक्सटॉर्शन (जबरदस्ती वसूली) के शिकार बने व 4.1 फीसदी क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगे गए और पांच फीसदी पहचान चोरी कर ठगी के शिकार बनाए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में आर्थिक अपराध के 1.39 लाख केस दर्ज हुए, जो 2021 के मुकाबले 11.1 फीसदी ज्यादा हैं। इस तरह साइबर क्राइम के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है।

2022 में कुल 65,893 केस दर्ज हुए, जो 2021 की तुलना में 24.4 फीसदी अधिक हैं। इनमें 64.8 फीसदी धोखाधड़ी से जुड़े थे। देखा जाए, तो ठगी के मामले में दिल्ली तीसरे स्थान पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, उप्र में 2021 में ठगी के 21,130 मामले व 2022 में कुल 25,484 लोग ठगी के शिकार हुए। महाराष्ट्र में 2021 में 18,560 मामले दर्ज हुए, तो वहीं 2022 में 18,799 लोग ठगी के शिकार हुए। 2021 में दिल्ली में ठगी के 14,550 मामले आए, तो वहीं 2022 में ठगी के कुल 14,661 मामले दर्ज किए गए।

● **राजेश बोरकर**

एक कमरे में बैठकर ठगी की वारदात

अपराधी एक कमरे में बैठे-बैठे बड़े आराम से अच्छे-अच्छों को चूना लगाने में महारत हासिल कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठगी के लिए कॉल सेंटर खोले जा रहे हैं। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लड़के-लड़कियों को नौकरी पर रखा जाता है और वे सब मिलकर ठगी का धंधा करते हैं। हर साल ऐसे कॉल सेंटर खुलते और पकड़े जाने पर बंद होते हैं। इस पर मूवी की सीरीज भी आ चुकी है, जिसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह लोग ठगी को अंजाम देते हैं। ठगी के ऐसे-ऐसे हथकंडे कि कोई सोच भी नहीं सकता। पहले ठगों का केंद्र झारखंड का जामताड़ा होता था; लेकिन अब कई राज्यों जैसे राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, उप्र, हरियाणा व कई अन्य राज्यों सहित विदेशों से भी तार जुड़े हुए हैं, जहां बैठकर ठगों के सरगना गैंग चला रहे हैं। देखा जाए, तो आजकल अमूमन लोग लालच के कारण ठगी का शिकार बनते हैं। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपनी गाढ़ी कमाई गंवा देते हैं। लोगों के अंदर इतना लालच बस गया है कि वो किसी न किसी तरीके से ठगों के जाल में फंस ही जाते हैं। चाहे वो क्रेडिट कार्ड का सुनहरा ऑफर हो या पार्ट टाइम काम का झांसा या इनवेस्टमेंट के नाम पर ज्यादा पैसा कमाने की चाहत या फिर मुफ्त में गिफ्ट की चाहत या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सर्विस बंद करने या किसी अन्य मामलों में फंसने का डर। ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने संगठित अवैध निवेश और पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर ठगी करने वाली 100 से अधिक वेबसाइट्स को बंद कर दिया है।

हादसों का दिसंबर

मप्र में नई सरकार के गठन के बाद जहां एक तरफ खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ दिसंबर हादसों का महीना बन गया। इस माह में मप्र में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन दुर्घटनाओं में आए दिन किसी न किसी की जान जा रही है। सबसे बड़ा हादसा 27 दिसंबर को गुना में हुआ। डंपर से टक्कर के बाद आग में खाक हुई बस में 13 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। आग की शिकार बस 15 साल पुरानी थी, उसका फिटनेस व बीमा भी खत्म हो चुका था, फिर भी वह मिलीभगत से सड़क पर दौड़ रही थी। घटना को लेकर अनेक सवाल उठे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुना पहुंचे और अस्पताल जाकर हादसे में 14 घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने साफ कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके आदेश पर कलेक्टर, एसपी समेत परिवहन विभाग के कई शीर्ष अधिकारियों को हटा दिया गया।

27 दिसंबर को रात्रि लगभग 8.30 बजे हुए बस हादसे ने पूरे मप्र समेत देश को हिला कर रख दिया था। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की थीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुना पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की थी और सख्त एक्शन लेते हुए कलेक्टर, एसपी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का तबादला किया था। परिवहन अधिकारी व सीएमओ नगरपालिका को निलंबित करने के आदेश दिए थे। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुरू से ही जीरो टॉलरेंस के मूड में हैं। माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट के बाद कुछ और भी कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है।

मप्र में भले ही गुना बस हादसा चर्चा का केंद्र रहा, लेकिन राज्य में कई हादसे हुए जिसमें लोगों को जान गंवानी पड़ी। इस बीच पन्ना जिले में बाइक सवार तीन युवक मिक्सर मशीन वाहन से टकरा गए। जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उमरिया में बाइक और कार की आमने सामने भिड़ंत में मामा-भांजी को गंभीर चोटें आई है। उमरिया में ही दो बाइकों की टक्कर में तीन लोग घायल हो गए। इधर अनूपपुर में कार और बाइक की टक्कर हो गई। इस घटना में दो लोग जख्मी हुए हैं। वहीं झाबुआ में केमिकल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पन्ना जिले के पहड़ीखेरा मार्ग में घने कोहरे की वजह से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जहां बाइक सवार तीन युवक मिक्सर मशीन वाहन से टकरा गए। घटना में दो लोगों की जान चली गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उमरिया कोतवाली अंतर्गत नेशनल हाईवे 43 पर भरौला और लोढ़ा के बीच दो बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें 108 के माध्यम से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद हादसे का शिकार हो गए। घायलों की पहचान जय पाल, बैगा कोहका, तमन्नारा, प्रदीप सेन, अमृत यादव लोढ़ा आदि के रूप में हुई है। इधर उमरिया में ही राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर करकेली पेट्रोल पंप के पास बाइक और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। बाइक पर बैठे मामा-भांजी गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक चालक की पहचान करही टोला निवासी प्रदीप बैगा के रूप में हुई है। फिलहाल दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय उमरिया में प्राथमिक इलाज के बाद जबलपुर के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। अनूपपुर के बिजुरी थाना क्षेत्र के ग्राम बेलिया में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक सवार 2 लोगों को चोटें आई हैं। जिन्हें कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। झाबुआ के मेघनगर औद्योगिक इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया। जहां केपीएल फैक्ट्री का केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि टैंकर पलटने के बाद केमिकल का कोई रिसाव नहीं हुआ। एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। घटना की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दिसंबर महीने के आखिरी दिन तक सड़क हादसों के अलावा कई अन्य हादसे भी हुए जिसमें लोगों की जान गई।

● **राकेश ग्रोवर**

विजिबिलिटी कम होने से बढ़े सड़क हादसे

मप्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के कारण कोहरे भी छा रहे हैं। वहीं कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से सड़क हादसे भी हो रहे हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से एक बस ट्रक से टकरा गई। शुक्र है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इधर कोहरे के कारण एक ट्रक अनियंत्रित होकर दीवार में जा घुसा। इस हादसे में भी कोई जनहानि नहीं हुई। शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र के ककरवाया के पास थीम रोड़ क्रॉसिंग पर गत दिनों एक बस सड़क क्रॉस करते वक्त ट्रक से टकरा गई। इस घटना में बस और ट्रक स्टाफ को मामूली चोट आईं हैं। बताया गया है यह हादसा कोहरे की वजह से हुआ है। देहात थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी शहर के भूत पुलिया पर गत दिनों एक ट्रक अनियंत्रित होकर सिंधिया छत्री की दीवार को तोड़ते हुए भीतर घुस गया। जिससे दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक स्टाफ मौके से फरार हो गया। ट्रक रातभर खड़ा रहा। जानकारी के मुताबिक रात 10 से 11 बजे के बीच ट्रक ग्वालियर बायपास की ओर से आया और भूत पुलिया के अंधे मोड़ पर अनियंत्रित होकर सीधे सिंधिया छत्री की दीवार में जा घुसा। तीन माह के भीतर इस स्थान पर यह चौथी घटना है। इस मार्ग पर सुबह 7 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है। इसके बाद भी भारी वाहन का आवागमन जारी रहता है। फिजिकल थाना पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। मप्र के इंदौर में भी नए रेलवे ट्रैक की टेस्टिंग के दौरान दसवीं की दो छात्राएं ट्रेन की चपेट में आ गईं और दोनों की ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रेल मंत्री के द्वारा रतलाम डीआरएम को घटना की जांच के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने घटना की जांच की मांग की थी।

सहकारिता चुनाव को मिली हरी झंडी

अप्रैल में जारी हुई थी अधिसूचना

गौरतलब है कि प्रदेश में 22 हजार सहकारी समितियों के चुनाव कराए जाने के लिए सहकारिता चुनाव प्राधिकरण ने इसी साल अप्रैल में इसकी अधिसूचना जारी की थी। लेकिन मामला एक बार फिर फंस गया और प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। गौरतलब है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव वर्ष 2012 के बाद से नहीं हुए हैं, जो हर पांच साल में होने थे। जबकि अन्य समितियों के चुनाव भी दो साल से टल रहे हैं। इस कारण समितियां नए काम शुरू नहीं कर पा रही हैं। सामान्य कामकाज के संचालन के लिए सहकारिता विभाग के अधिकारियों को प्रशासक बनाया गया है।

मप्र के 40 लाख से ज्यादा किसानों से जुड़ी साढ़े चार हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों यानी पैक्स के चुनाव होने की संभावना जग गई है। दरअसल, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने पैक्स के चुनाव की तैयारियां करने का निर्देश दे दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 10 साल से सहकारी समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं। अब माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की आचार सहिता लगने से पहले पैक्स के चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। मप्र राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी एमबी ओझा का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराए जाने हैं। इसके लिए सहकारिता विभाग से जानकारी मांगी है।

सहकारी अधिनियम में सहकारी संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने के छह माह पहले समिति द्वारा चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजने का प्रविधान है। समिति के प्रस्ताव पर सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी कार्यालय सदस्य सूची तैयार करके चुनाव कराते हैं। यदि किसी कारण से समय पर चुनाव नहीं हो पाता है तो यह अवधि छह माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसमें निर्वाचित संचालक मंडल के स्थान पर प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। यह भी अधिकतम छह माह रह सकता है। विशेष परिस्थिति में अवधि छह माह और बढ़ाई जा सकती है। इसके बीच चुनाव कराने होंगे लेकिन प्रदेश में पिछले 10 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। छतरपुर के सहकारिता नेता हरिओम का कहना है कि प्रदेश में 10 साल से अधिक समय से सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराने से किसानों को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित हुई हैं।

प्रदेश में साढ़े चार हजार से अधिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर मप्र राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयन से जानकारी मांगी है। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले सहकारिता के चुनाव कराए जा सकते हैं। इससे अपेक्स बैंक के अध्यक्ष का चुनाव संभव होगा। मप्र राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने सभी जिलों के सहकारी अधिकारियों से सात दिन के अंदर सदस्यता सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा है। चुनाव प्रस्ताव के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में विकासखंड वार संस्थाएं सम्मिलित करने की स्वतंत्रता जिला अधिकारियों की होगी। वह जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सहकारी संस्थाओं का चयन करेंगे।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पूरी चुनाव प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के पहले पूरी करने के आदेश दिए हैं। यह चुनाव चार चरणों में पूरे होंगे। मप्र राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी एबी ओझा के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के पहले करा लिए जाएं। इसके अनुक्रम में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने मुख्य सचिव को इस आदेश से अवगत करा दिया है। इसके बाद पाया गया है कि 2019 में लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता 10 मार्च 2019 से प्रभावशील हो गई थी एवं सात चरणों में से प्रथम चरण का मतदान 11 अप्रैल 2019 को हो गया था। इसलिए उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के अनुसार 10 मार्च 2024 के पहले प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराया जाना आवश्यक होगा। इसे देखते हुए सहकारी समितियों के लिए चार चरणों में निर्वाचन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

प्रदेश में पंजीकृत सभी कार्यशील सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाए जाने का मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में प्रावधान है। प्रदेश में लगभग 4531 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं पंजीकृत हैं। इनमें से अधिकांश सहकारी संस्थाओं में वर्तमान में निर्वाचन न होने से प्रशासक कार्यरत हैं। जबकि निर्वाचित संचालक मंडल के स्थान पर अधिनियम के अनुसार प्रशासन 6 माह की समयावधि के लिए ही नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन लगभग चार साल से चुनाव नहीं हो सके हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुक्रम में समय सीमा में चुनाव कराने सभी संभागों के संयुक्त आयुक्त सहकारिता को मप्र राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ओझा ने निर्देशित किया है कि सभी समितियों की अद्यतन सदस्यता सूची सहित रिटर्निंग अधिकारी नियुक्ति करने अधिकारियों-कर्मचारियों की सोसायटीवार सूची 7 दिन के अंदर भेजें। इसके साथ ही चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 2013 से सहकारी समितियों के चुनाव नहीं हुए। कई जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में पांच साल से अधिक समय से संचालक मंडल नहीं है। छतरपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष करुणेन्द्र सिंह को राज्य सरकार ने अपने एक आदेश से बना दिया था। इसको लेकर अदालत में अपील की गई। तर्क दिया गया कि अपात्र व्यक्ति को बैंक अध्यक्ष बनाया गया है। सिंगल बैंच ने अध्यक्ष की नियुक्ति अमान्य कर दी थी। शासन ने डबल बैंच में अपील की थी। कोर्ट ने चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के निर्देश पर मप्र राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने आयुक्त सहकारिता को पत्र लिखते हुए कहा है कि 4,531 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता प्रभावशील होने के पूर्व हों। पिछले लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 10 मार्च 2019 को लागू हुई थी। सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने चार चरणों में सहकारिता के चुनाव कराने का प्रस्ताव तैयार किया है।

● **प्रवीण सक्सेना**

रघुपति राघव राजा राम सज गया अयोध्या धाम

प्रभु श्रीराम का मंदिर करोड़ों हिंदुओं का सपना है, जो अब साकार होने जा रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान श्रीराम की प्राण-प्रतिष्ठा होते ही ये सपना पूरा हो जाएगा। लोगों के दिलों में बसने वाले भगवान श्रीराम का अयोध्या में भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, जिसकी केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया में धूम है। अयोध्या में बने इस मंदिर की अपनी ही एक भव्यता है, जिसे केवल एक शहर नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष ने अपना योगदान दिया है।

● राजेंद्र आगाल

प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि अधोध्या में बना राम मंदिर सनातन प्रेमियों के लिए खास महत्व रखता है। यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई है, जिसमें लगभग 500 साल का समय लगा है। ऐसे में अयोध्या राम मंदिर का खास धार्मिक महत्व तो है ही साथ ही इससे प्राचीन इतिहास भी जुड़ा है। अब रामलला वर्षों बाद टेंट से निकलकर मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और यह समय भक्तजनों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। अयोध्या में मंदिर विवाद से लेकर विध्वंस और मंदिर निर्माण की घटनाएं देख तुलसीदास जी द्वारा श्रीरामचरितमानस के बालकांड में लिखा यह दोहा याद आता है कि– होइहि सोइ जो राम रचि राखा। यानी होगा वही जो राम ने लिख रखा है। आज वर्षों बाद भी वही हुआ जो प्रभु श्रीराम की इच्छा थी। यानी रघुपति राघव राजा राम...सज गया अयोध्या धाम। अब सभी को 22 जनवरी का इंतजार है जब रामलला का पहला दर्शन होगा।

बता दें कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकेंड का होगा, जो 12 बजकर 29 मिनट 8 सेकंड से 12 बजकर 30 मिनट 32 सेकंड तक होगा। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यह मुहूर्त पंडित गणेश्वर शास्त्री ने निकाला है। 22 जनवरी 2024 को होने वाले इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भगवान की सबसे पहली आरती उतारेंगे। इसके बाद मंदिर परिसर में बनी जटायु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे। भगवान श्रीराम का यह मंदिर राम जन्मभूमि अयोध्या में भले ही बन रहा है, लेकिन इसमें पूरे देश को समाहित किया गया है। भगवान श्रीराम के इस मंदिर में लगी हुई वस्तुएं भारत के कोने-कोने से आई हैं। भगवान श्री राम के मंदिर में लगाए जा रहे पत्थर कोई आम पत्थर नहीं बल्कि पिंक सैंडस्टोन है। मंदिर का पत्थर राजस्थान के भरतपुर जिले के बंशी पहाड़पुर गांव के पहाड़ियों का है। मंदिर में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों पर कन्याकुमारी के कारीगर नक्काशी कर रहे हैं। मंदिर में लगाए जाने वाले दरवाजों का कॉन्ट्रैक्ट हैदराबाद की एक कंपनी के पास है, जो महाराष्ट्र के जंगल से लकड़ी ढूंढ कर लाए हैं, जो कि कई दशकों तक चलेंगे। राम मंदिर के दरवाजों की खासियत यह है कि ये सोने से मढ़े जाएंगे। मंदिर में 50 से भी अधिक दरवाजे लगाए जाएंगे। मंदिर में इस्तेमाल होने वाला ग्रेनाइट तेलंगाना और कर्नाटक से लाया गया है। वहीं पत्थरों में मूर्ति बनाने का काम उड़ीसा के कारीगर कर रहे हैं। श्रीराम जन्मभूमि के पास लगाए जाने वाला रामस्तंभ राजस्थान के माउंट आबू से लाया गया है। रामलला के दरबार में एटा जिले में तैयार हुआ अष्टधातु का 2100 किलो का घंटा लगाया जाएगा। यह 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा है। राम मंदिर के पूजा के लिए गुजरात के वडोदरा जिले से 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी आएगी।

22 जनवरी का सबको इंतजार

आखिरकार वह तारीख नजदीक आ ही गई, जिसका इंतजार हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोग पिछले 500 वर्षों से कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर नया मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया है। बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तैयारियां अपने अंतिम स्तर पर हैं। आने वाली 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा होगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश के अलग-अलग हिस्सों से साधु-संतों को अयोध्या बुलाया जा रहा है। इसके अलावा अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे प्रतिष्ठित लोग भी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। जैसे-जैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तारीख नजदीक आ रही है, उसके साथ ही अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं।

सिंहासन से लेकर दरवाजे तक सोने से बने

अयोध्या में तैयार हुए इस ऐतिहासिक मंदिर में कई चीजें सोने से बनी होंगीं। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर में जो 14 दरवाजे लगे हैं, उन सभी पर सोने की मोटी परत चढ़ी होगी। लोगों को सोने से चमचमाते हुए ये दरवाजे नजर आएंगे। यानी सोने से चमकते इन द्वारों से लोगों का स्वागत होगा। ये दरवाजे अंदर से कई सालों तक चलने वाली सागौन की लकड़ी से बने हुए हैं। इनके बाहर जो कलाकारी हुई है, वो पूरी तरह से सोने की है। इन पर हाथी, शंख, चक्र और गदे जैसे चित्र बने हैं। राम मंदिर परिसर में कुल 46 दरवाजे होंगे, सोने से जड़े दरवाजे मंदिर के गर्भगृह में होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामलला को 108 सोने के सिक्कों से बना एक खास हार पहनाया जाएगा। इसके अलावा रामलला की चरण पादुकाएं भी सोने की होंगीं। इनमें चांदी और सोने का काम किया गया है। चरण पादुकाओं का वजन करीब 1 किलो होगा। रामलला जिस सिंहासन पर विराजमान होंगे, उस पर भी सोने की परत चढ़ाने की बात सामने आई थी। ये करीब 8 फुट लंबा होगा। इसके अलावा मुकुट से लेकर तमाम तरह के जेवरात भी सोने के होंगे। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की जो मूर्ति स्थापित होगी, वो उनके बाल रूप की होगी। पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि वो रामलला के लिए सोने से बने धनुष और बाण भेंट करेगा। इसके अलावा देशभर से लोग अलग-अलग तरह की सोने और चांदी की चीजें राम मंदिर के लिए भेंट कर रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में करीब 900 करोड़ का खर्च आया है। देशभर की पवित्र नदियों और कुडों से लाए जल से रामलला का अभिषेक होगा। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही इसमें आम लोग दर्शन के लिए जा सकेंगे। मंदिर बनाते समय इसकी सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। राम मंदिर कैसा बना है? मंदिर की वास्तुकला कैसी है? इसमें किन सामग्रियों का इस्तेमाल हुआ है? आज सभी भारतीय को यह सब जानने की उत्सुकता है।

कैसा बना है राम मंदिर?

राम की नगरी में राम नाम की गूंज है। रामलला की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम नगरी में उत्सव सा माहौल है। तैयारियां जोरों पर हैं। नया एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन, सड़के हों या बस स्टैंड सब संवर रहे हैं और सजाए जा रहे हैं। चौराहों-दीवारों पर देवी-देवताओं की आकृतियां उकेरी जा रही हैं। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पहुंचकर 22 जनवरी के ऐतिहासिक पलों से पहले की झलकियां दे दीं। प्रधानमंत्री ने अयोध्या के नए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही प्रोटोकॉल तोड़कर यहां के निषाद परिवार से मिलकर उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्यौता भी दिया। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही इसमें आम लोग दर्शन के लिए जा सकेंगे। मंदिर बनाते समय इसकी सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। राम मंदिर कैसा बना है? मंदिर की वास्तुकला कैसी है? इसमें किन सामग्रियों का इस्तेमाल हुआ है? आज सभी भारतीय को यह सब जानने की उत्सुकता है।

गौरतलब है कि 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए। इससे पहले तीन दिवसीय वैदिक अनुष्ठान आयोजित किए गए, जिसमें 40 किलोग्राम चांदी की ईंट की स्थापना कर सभी प्रमुख देवताओं को मंदिर में आमंत्रित करने के लिए रामार्चन पूजा की गई। भूमिपूजन के साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर के पहले चरण का आधिकारिक तौर पर निर्माण शुरू हो गया। 18,000 करोड़ रुपए में बनने वाले राम मंदिर के निर्माण का काम एलएंडटी कंपनी को मिला। राम मंदिर को नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली के भीतर समाहित द्रविड़ वास्तुकला की झलक है। मुख्य मंदिर जहां रामलला की मूर्ति रखी जाएगी, वह उत्तर भारत की नागर शैली में है। वहीं, कोनों पर बने चार मंदिर द्रविड़ वास्तुकला से प्रभावित हैं।

राम मंदिर निर्माण की कारीगरी में दिखेगा पूरे देश का अक्स

श्रीराम मंदिर के निर्माण में जहां कई प्रदेशों के कारीगरों की शिल्प दिखाई देगी तो निर्माण की सामग्री भी अलग-अलग प्रांतों की होगी। मंदिर में पत्थरों को तराशने का काम में राजस्थान, उड़ीसा और मप्र के शिल्पकारों ने किया। वहीं इसमें लगने वाले पिंक कलर के सैंड स्टोन राजस्थान के भरतपुर के वंशीपहाड़पुर गांव से लाकर लगाए गए हैं। मंदिर के दरवाजों की लकड़ी भी महाराष्ट्र से लाई गई है। देश के अलग-अलग हिस्सों से आए कारीगर महीनों से अयोध्या में डेरा डाल मंदिर को भव्य स्वरूप देने में जुटे हुए हैं। राम मंदिर निर्माण का काम अंतिम दौर में है। ग्राउंड फ्लोर का काम करीब पूरा हो गया है, अब फिनिशिंग अंतिम चरण में है। मंदिर की पुरानी कार्यशाला में खंभों को तराशने और डिजाइनिंग का काम चल रहा है जो पहले और दूसरे फ्लोर पर लगने हैं। यहां पर काम करने वाले कारीगरों का कहना है कि काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश मिले हैं। राजस्थान के दो दर्जन से ज्यादा कारीगर पत्थरों पर डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर 14 दरवाजों के निर्माण में महाराष्ट्र के जंगलों की लकड़ी लगी है। इन दरवाजों के निर्माण का काम हैदराबाद के कारीगर कर रहे हैं। इन पर डिजाइनिंग करने वाले कन्याकुमारी से आए हैं। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा का कहना है कि सिर्फ दरवाजे बनाने में ही तीन प्रांतों की भागीदारी है। मंदिर के निर्माण कार्य में लगाए गए 300 से ज्यादा कारीगरों को अलग-अलग प्रदेशों से चुना गया है। रामलला की मूर्ति निर्माण में भी दो प्रदेशों के विशेषज्ञ मूर्तिकार लगे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक, रामलला की 51 इंच की दिव्य और मुख्य प्रतिमा के निर्माण में तीन विशेषज्ञ मूर्तिकार लगाए गए हैं। दो मूर्तियां कर्नाटक के श्याम पत्थर से तराशी गई है। वहीं, तीसरी प्रतिमा राजस्थान के जयपुर के सत्यनारायण पांडे संगमरमर पत्थर से तराश रहे हैं।

इसमें रामेश्वरम, तिरूपति और कांचीपुरम में स्थित प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय मंदिरों के तत्व शामिल हैं।

दरअसल, भारत में मंदिरों की स्थापना की तीन प्रमुख शैलियां हैं जिन्हें नागर, द्रविड़ और वेसर के नाम से जाना जाता है। नागर उत्तर भारतीय मंदिर की वास्तुकला है। यहां एक पत्थर के चबूतरे पर एक पूरा मंदिर बनाया जाता है जिसके ऊपर सीढ़ियां चढ़ती हैं। दक्षिण भारत के विपरीत, इसमें आमतौर पर विस्तृत चारदीवारी या प्रवेश द्वार नहीं होते। प्राचीनतम मंदिरों में केवल एक शिखर था, लेकिन बाद में कई शिखर आए। गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के नीचे स्थित होता है। राम मंदिर का डिजाइन गुजरात के सोमपुरा परिवार ने तैयार किया है जिसने पहले भी कई बड़े मंदिरों के डिजाइन तैयार किए हैं। इनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर, अक्षरधाम और अंबाजी मंदिर और लंदन का स्वामीनारायण मंदिर शामिल है। इनकी 15 पीढ़ियां देश-विदेश में अब तक 131 से अधिक मंदिर का डिजाइन तैयार कर चुकी हैं। सोमनाथ मंदिर का डिजाइन प्रभाशंकर सोमपुरा ने तैयार किया, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है।

मंदिर की विशिष्टताएं

एक बार पूरा होने पर राम मंदिर दुनियाभर में वास्तुकला के चमत्कारों में से एक होगा। इसके अलावा यह भारत और दुनियाभर में सबसे बड़ा मंदिर भी होगा। राम मंदिर का गर्भगृह और भी खास और अनोखा है। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोण में है और इसे इस तरह से बनाया गया है कि हर साल रामनवमीं के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें गर्भगृह में विराजमान श्रीराम की मूर्ति पर पड़ेंगी। मंदिर की परिक्रमा गोलाई में बनाई गई है। इसके भूतल पर पांच मंडप बनाए गए हैं जिनमें गृह मंडप, कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और प्रार्थना मंडप शामिल हैं। फिलहाल मंदिर की पहली मंजिल फर्श और प्रवेश द्वार पूरी तरह से तैयार है। जहां भगवान श्रीराम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी वह गर्भगृह भी तैयार हो चुका है। दूसरी और तीसरी मंजिल निर्माणाधीन है। यह कल्पना की गई है कि राम मंदिर एक हजार वर्षों तक भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा रहेगा। निर्माण के दौरान मंदिर की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है जो बिना किसी नुकसान के 8 तीव्रता के भूकंप को झेलने में सक्षम है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में अद्वितीय वास्तुशिल्प योजना शामिल है, जिसमें इसके निर्माण के दौरान किसी भी रूप में लोहे के उपयोग को शामिल नहीं किया गया है। मुख्य मंदिर की इमारत राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र के 4.7 लाख घन फीट वजनी गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी है। तख्त 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों से बनाए गए हैं जबकि जड़ाई का काम रंगीन और सफेद संगमरमर से किया गया है। मंदिर के दरवाजे सागौन की लकड़ियों से बनाए गए हैं जो महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले के जंगलों से आती हैं। इमारत में इस्तेमाल किया गया ग्रेनाइट तेलंगाना और कर्नाटक से आया है, जबकि फर्श सामग्री मप्र से ली गई है। जटिल बलुआ पत्थर की नक्काशी ओडिशा के कुशल मूर्तिकारों द्वारा भारत भर की विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके बनाई गई है। लकड़ी का काम तमिलनाडु के श्रमिकों के साथ आंध्रप्रदेश स्थित एक कंपनी को सौंपा गया था। पीतल के बर्तन उप्र से और सोने का काम महाराष्ट्र से मंगाया गया है। मंदिर के काम में एलएंडटी ने लगभग 4,000 श्रमिकों को लगाया, जिसमें राजस्थान और मैसूर के कारीगर और पत्थरों को तराशने वाले स्थानीय पत्थर तराशने वाले भी शामिल हैं।

राम मंदिर भव्यता के साथ भारतीय परंपरा एवं तकनीक का भी पर्याय है। यह जानकारी रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने दी। वह रामजन्मभूमि परिसर के ही निकट स्थित रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भवन में संवाददाताओं से वार्ता करते हुए राम मंदिर की विशिष्टताएं गिना रहे थे। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है और नींव के ऊपर कांक्रीट का भी प्रयोग नहीं किया गया है। निर्माण की तकनीक की विशिष्टता नींव से ही निहित है। मंदिर की नींव चार सौ फीट लंबे एवं तीन सौ फीट चौड़े विशाल भूक्षेत्र पर मोटी रोलर कांपेक्टेड कांक्रीट की 14 मीटर मोटी कृत्रिम चट्टान ढालकर की गई है। मंदिर की प्लिंथ 380 फीट लंबी एवं 250 फीट चौड़ी है तथा मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 161 फीट है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने मंदिर निर्माण से जुड़ी अन्य मौलिक जानकारी भी साझा की। मंदिर में नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना एवं कीर्तन मंडप के रूप में पांच मंडप होंगे। मंदिर की प्लिंथ तक पहुंचने के लिए 32 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा है, जिसकी लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट है। परकोटा के चारों कोनों पर भगवान सूर्य, मां भगवती, गणपति एवं भगवान

शिव के सहित परकोटा में ही वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी एवं देवी अहिल्या का भी मंदिर निर्मित होना है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने रामजन्मभूमि मुक्ति संघर्ष के संक्षिप्त इतिहास का भी विवेचन किया। उनका कहना है कि भव्य राम मंदिर 492 वर्ष के सुदीर्घ संघर्ष और 37 वर्ष के सतत् जागरण से संभावित हुआ है। उन्होंने रामजन्मभूमि मुक्ति के लिए ग्राउंड पैनीट्रेटिंग रडार सर्वे का भी स्मरण कराया। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश पर 2003 में इस सर्वे से तय हुआ कि 1528 से पूर्व सतह के नीचे हिंदू भवन था। इसी सर्वे के बाद एएसआई ने उत्खनन कराया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि विवादित भूमि की सतह के नीचे उत्तर भारतीय शैली का मंदिर था।

त्रेतायुग थीम से सज रही अयोध्या

अयोध्या में राममंदिर की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है। रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में 2.7 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 162 फीट की होगी। इस पूरे मंदिर परिसर में भगवान श्रीराम के मंदिर के साथ ही और भी 6 मंदिर बनाए जा रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाएगा। वहीं, पूरे अयोध्या को त्रेतायुग थीम से सजाया जा रहा है। सड़कों के किनारे लग रहे सूर्य स्तंभ भगवान राम के सूर्यवंशी होने के प्रतीक को दर्शाते हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक, धर्म पथ के सड़कों के किनारों पर दीवार बन रही है जिस पर रामायण काल के प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। दीवारें टेराकोटा फाइन क्ले म्यूरल कलाकृतियों से सजी होंगी जो त्रेतायुग की याद दिलाएगी। वहीं अयोध्या में अब रंग रोगन, साफ-सफाई और कलाकृति का काम हर तरफ नजर आता है। वहीं, दूसरी तरफ नयाघाट से सहादतगंज तक जाने वाली सड़क को रामपथ नाम दिया गया है। क्योंकि, अयोध्या को त्रेतायुग की थीम से सजाया जा रहा है तो आइए जानते हैं कि क्या था त्रेतायुग। श्रीराम का त्रेतायुग से क्या संबंध था।

त्रेतायुग हिंदू मान्यताओं के अनुसार चार युगों में से एक युग है। त्रेता युग मानवकाल के द्वितीय युग को कहते हैं। जब सतयुग समाप्त हो गया तब त्रेतायुग का आरंभ हुआ और यह युग सनातन धर्म का दूसरा युग था। पुराणों के अनुसार, त्रेतायुग लगभग 12 लाख 96 हजार साल का था। त्रेतायुग में मनुष्य की औसत आयु 10,000 हजार वर्ष थी। त्रेतायुग में धर्म 3 स्तंभों पर खड़ा था। कहते हैं कि त्रेतायुग में लोग कर्म करके फल प्राप्त करते थे। इस युग में लोग धर्म का पालन भी करते थे।

अयोध्या एयरपोर्ट में दिखेगी त्रेता युग की झलक

अयोध्या एयरपोर्ट की बात करें तो इसका आर्किटेक्चर और डिजाइन बेहद खास है। इस एयरपोर्ट की बनावट की थीम श्रीराम के जीवन से प्रेरित है। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि इस एयरपोर्ट में रामकथा की झलक मिले। अयोध्या एयरपोर्ट 8000 स्क्वायर मीटर में बना है। इसके निर्माण में दो साल का वक्त और 250 करोड़ रुपए की लागत आई है। एयरपोर्ट का डिजाइन नागर शैली से प्रेरित है, जिसे आर्किटेक्ट विपुल वार्ष्णेय और अनुज वार्ष्णेय ने अमलीजामा पहनाया है। इनकी टीम ने तीन साल पहले अयोध्या एयरपोर्ट के डिजाइन की जिम्मेदारी संभाली थी। आर्किटेक्ट विपुल वार्ष्णेय का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में हो रहा है। इसी से प्रेरित होकर एयरपोर्ट का डिजाइन तैयार किया गया है। एयरपोर्ट के 7 शिखर नागर शैली से प्रेरित हैं। बीच में मुख्य शिखर, आगे 3 और पीछे 3 शिखर हैं। बता दें कि नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की तीन में से एक शैली है। इस शैली में मंदिरों का निर्माण होता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी इसी शैली में हो रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट में हर जगह भगवान श्रीराम का प्रतिबिंब दिखाने की कोशिश की गई है। बाहर ही तीर-धनुष का बड़ा म्यूरल (भित्तिचित्र कला) लगाया गया है। विपुल का कहना है कि इसको बहुत सोच-समझ कर लगाया गया है। इसमें यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि पुरुषार्थ से ही असत्य पर विजय संभव है। यही श्रीराम के जीवन का संदेश भी है। एयरपोर्ट की लैंड-स्केपिंग में पंचतत्व का ध्यान रखते हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। फ्लोरिंग में भी कई रंगों का प्रयोग किया गया है जो पंचतत्व पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि से प्रेरित हैं।

श्रीराम का त्रेतायुग से क्या संबंध?

त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और अंतिम में श्रीराम के रूप में जन्म लिया था। श्रीराम का जन्म त्रेतायुग में हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भगवान विष्णुजी के अवतार थे। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र जी अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र थे। श्रीरामचंद्र जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास भी किया था। श्रीराम का अवतार राक्षसों का नाश करने के लिए भी हुआ था, इन्होंने रावण का संहार और राक्षसों का नाश कर दिया था। वहीं, श्रीरामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे तो इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपों से भी सजाया था। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का अति सूक्ष्म मुहूर्त होगा, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ये मुहूर्त चुना है। शुभ मुहूर्त का यह क्षण मात्र 84 सेकंड का होगा जो 12 बजकर 29 मिनट 8 सेकंड से 12 बजकर 30 मिनट 32 सेकंड तक होगा।

क्या है अयोध्या विवाद?

अयोध्या में लगभग 5 हजार मंदिर हैं। इसमें 95 फीसदी मंदिर सीताराम के हैं। फिर आखिर इस श्रीराम मंदिर को लेकर सैकड़ों सालों तक संघर्ष और लंबी कानूनी लड़ाई क्यों हुई। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस सवाल का जवाब भी दे दिया है। उसकी मानें तो यह लड़ाई श्रीराममंदिर को लेकर नहीं, बल्कि श्रीराम की जन्मभूमि को लेकर थी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि जन्मस्थान की अदला-बदली नहीं होती। यह मंदिर जन्मस्थान का मंदिर है। अन्यथा मंदिर तो

बहुत हैं, सारे देश में लाखों मंदिर होंगे, यह झगड़ा जन्मस्थली को लेकर था।

अयोध्या में श्रीराम की जिस जन्मस्थली की बात राम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है, वहां पहले तीन गुंबदों की ऐसी इमारत थी, जो देखने में पूरी तरह मस्जिद लगती थी। इसी इमारत को हिंदू समाज श्रीराम का जन्मस्थान बताता है, जबकि मुस्लिम समाज इसे मस्जिद कहता था। हिंदू समाज का दावा है कि यहां पहले मंदिर था, जिसे तोड़कर विवादित ढांचा बनाया गया। जबकि मुस्लिम समाज का दावा था कि यहां कुछ नहीं था और ना कुछ तोड़ा गया। विवाद इस बात पर था कि जो तीन गुंबदों का ढांचा तोड़ा गया, वह मंदिर था या मस्जिद? इसे लेकर चंपत राय कहते हैं कि यहां तीन गुंबदों का एक ढांचा था। इसके तीन गुंबद थे, कोई दरवाजा नहीं था। हिंदू समाज कहता था कि यह श्रीराम का जन्मस्थान है। दूसरे लोग कहते थे कि मस्जिद है। अंग्रेजी में लिखा गया है बैरन लैंड। इसका मतलब यहां कुछ भी नहीं था। जब कुछ था ही नहीं तो तोड़ा भी कुछ नहीं गया। ये लड़ाई तब शुरू हुई जब विवादित ढांचा ढहाया गया था। लड़ाई सिर्फ मंदिर की थी, तो मंदिर किसी अन्य स्थान पर क्यों नहीं बनाया गया। इस पर श्रीराम मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि यह लड़ाई मंदिर की नहीं, बल्कि यह इज्जत और सम्मान की लड़ाई थी। यही वजह रही कि हिंदू पक्ष इस लड़ाई को अपने सम्मान की लड़ाई मानकर लड़ता रहा। चंपत राय ने कहा कि 1528 में क्या आबादी रही होगी। 500 साल पहले यहां की जनता ने लड़ाई लड़ी। जय राजकुमारी ने इसे लेकर तलवार उठाई। उन्होंने कहा कि रानी तो कई मंदिर बनवा सकती थीं, तो लड़ाई की क्या जरूरत थी, लेकिन सवाल ये था कि यह स्थान हमारा है। हमारे घर में कोई कैसे घुस गया। ये इज्जत और सम्मान की लड़ाई थी।

श्रीराम मंदिर को तोड़ने का दावा हिंदू पक्ष करता है, तो क्या और भी मंदिर अयोध्या में तोड़े गए थे। इसे लेकर श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट का दावा है कि श्रीराममंदिर के अलावा मुगलकाल में दो और मंदिर तोड़े गए थे। जिसमें एक स्वर्गद्वारी मंदिर था तो दूसरा मंदिर त्रेता के ठाकुर का था। हालांकि चर्चा सिर्फ श्रीराम मंदिर को लेकर होती है, क्योंकि हिंदुओं का दावा है कि यह स्थान श्रीराम की जन्मभूमि है। चंपत राय का कहना है कि संघर्ष केवल रामजन्मभूमि का है, केवल मंदिर

तो इस देश में कम से कम 3000 तोड़े गए। कई किताबें लिखी गई हैं। अयोध्या में ही तीन मंदिर तोड़े गए। एक राम जन्मभूमि। दूसरा स्वर्गद्वारी और तीसरा त्रेता के ठाकुर का मंदिर। तीनों मंदिरों के तोड़ने का वर्णन किताबों में है।

श्रीराम की जन्मभूमि पर बनी तीन गुंबदों वाले ढांचे को ढहाने का समय गीता जयंती के दिन नियत किया गया था। राम मंदिर ट्रस्ट कहता है कि ये संयोग था कि उस दिन 6 दिसंबर था। उसी दिन श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और उस दिन तीन गुंबद वाला ढांचा गिर गया। चंपत राय ने कहा कि जब हमें इसका पता लगा तो आंख-नाक सब खुल गए थे। मंदिर-मस्जिद की लड़ाई अदालत में लंबे समय तक चलती रही। 1995 में एक आदेश के तहत इस संबंध में दायर अलग-अलग मुकदमों को क्लब कर दिया गया। इसके बाद भी हाईकोर्ट से फैसला आने में एक दशक से अधिक का समय लग गया। जब फैसला आया तो दोनों पक्षों ने उसे पूरे मन से स्वीकार नहीं किया और दोनों पक्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में सारे दस्तावेज अंग्रेजी में अनुवाद होकर जमा होने चाहिए, तभी सुनवाई होती है। लिहाजा अलग-अलग भाषाओं के दस्तावेज ट्रांसलेट होने में लंबा समय लग गया। सवाल यह भी था कि यह ट्रांसलेट कौन कराए? 2017 में उप्र में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उप्र सरकार ने इन दस्तावेजों को ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी उठाई। चंपत राय का कहना है कि ये दस्तावेज हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पारसी और फ्रेंच भाषा में थे। जब अदालत में सारे डॉक्यूमेंट्स अंग्रेजी में प्रस्तुत हो गए तब प्रक्रिया आगे बढ़ी।

विवादित ढांचा गिरने के बाद लंबे संघर्षों और कानूनी लड़ाई के बाद शुरू हुई दोनों पक्षों में समझौता वार्ता। यह समझौता वार्ता विश्वविद्यालय मीटिंग हॉल और लखनऊ से लेकर हनुमानगढ़ी समेत कई मंदिरों में हुई। साढ़े चार महीने तक चली समझौता वार्ता में जब सहमति नहीं बन सकी, तो कोर्ट ने भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता होना संभव नहीं है। इस समझौता वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकल सकता। चंपत राय का कहना है कि जब चार महीने बाद भी समझौता वार्ता से कुछ हासिल नहीं हुआ तो कहा गया कि क्यों समय खत्म कर रहे हो। कुछ नहीं होगा। समझौते के लिए जो टीम बनी थी, उसने भी मान लिया कि कुछ नहीं हो सकता। और लिखकर दिया कि समझौता संभव नहीं है। तब अदालत ने अपनी प्रक्रिया शुरू की। 6 अगस्त 2019 को कोर्ट में मैराथन बहस चलने के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को समाप्त मान लिया और 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने अपना निर्णय सुना दिया। इस फैसले के अनुसार तीन गुंबदों वाली इमारत की भूमि हिंदू समाज को दी गई और सरकार को 2 महीने के भीतर एक नया ट्रस्ट बनाने का आदेश भी दिया गया। इसी के बाद केंद्र सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और उक्त भूमि भी इसी ट्रस्ट को सौंप दी गई।

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर लक्ष्मी भी बरसेगी

अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, कारोबारियों के लिए भी बेहद खुशी का अवसर बनने जा रहा है। कारोबारी जगत अवसर को भुनाने में जुटा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) का अनुमान है कि प्रभु श्रीराम के मंदिर से संबंधित उत्पादों की बिक्री से केवल जनवरी में 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो सकता है। सीएआईटी के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि राममंदिर का उत्साह पूरे देश में है और व्यापार जगत इसमें बड़े अवसर देख रहा है। देशभर के व्यापारी सीएआईटी के नेतृत्व में एक जनवरी से दुकान-दुकान, बाजार-बाजार जाएंगे। श्रीराम की अलख जगाएंगे। हर शहर और हर घर अयोध्या बनेगा। राममंदिर से संबंधित तकरीबन सभी उत्पादों को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है, लेकिन राममंदिर की प्रतिकृति के लिए लोग ज्यादा उत्सुक हैं। खंडेलवाल का कहना है कि श्रीराम ध्वजा, श्रीराम के चित्र और मालाएं, लॉकेट, चाबी के छल्ले, रामदरबार की फोटो समेत अन्य संबंधित सामान उपलब्ध होने लगे हैं। यही नहीं, रामनामी कुर्ते, टीशर्ट और अन्य वस्त्रों की मांग भी बढ़ गई है। कपड़ा उद्योग को भी खूब काम मिल रहा है।

मेट्रो में 45 फीसदी बिजली रीजेनरेट

किसी भी वाहन के ब्रेक लगने पर ऊर्जा की खपत होती है पर भोपाल मेट्रो ट्रेन में ऐसा नहीं होगा। मेट्रो ट्रेन में ब्रेक लगते ही बिजली का बनना शुरू हो जाएगा और इससे कुल बिजली की खपत का 45 फीसदी रीजेनरेट किया जाएगा। मप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन मेट्रो और लिफ्ट के रुकने से पैदा हुई ऊर्जा का इस्तेमाल अपने कार्यों के लिए करेगा। जानकारी के अनुसार मेट्रो कोच और स्टेशन पर लगी लिफ्ट के रुकते समय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा वापस मेट्रो की इलेक्ट्रिक सप्लाई की लाइन में जा सके, इसके लिए मेट्रो के कोच में ही पहियों के पास से उपकरण लगाए जा रहे हैं। मेट्रो कोच अपनी यात्रा के दौरान जितनी बार भी रुकेगा तो ब्रेक लगने से उत्पन्न हुई ऊर्जा को पहिए के पास लगे उपकरण इसे वापस लाइन में भेज देंगे। पूरे ट्रैक पर बहुत सारी मेट्रो एक साथ चलती रहेंगी। इनके रुकने से पैदा ऊर्जा बिजली के रूप में वापस इलेक्ट्रिक लाइन में पहुंचेगी और इसका उपयोग दूसरी ट्रेनों के संचालन में होगा।

मेट्रो रेल कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि थर्ड रेल तकनीक में रेलवे ट्रैक पर सिरेमिक इंसुलेटर लगाए जाते हैं, ताकि कोई इसके संपर्क में आ भी जाए तो उस पर करंट का प्रभाव न पड़े। जबकि मेट्रो में करंट के लिए ट्रेन में धातु (मेटल) का एक कान्टैक्ट ब्लाक होता है, जिसे कलक्टर शूज (कान्टैक्ट शूज) कहा जाता है। यह कलक्टर शूज उसी तरह से इंसुलेटर के संपर्क में रहता है, जैसे आम ट्रेनों के इंजन का पेंटो ओएचई से रगड़ता रहता है। कलक्टर शूज के साथ एक सहूलियत और होती है कि इसका संपर्क इंसुलेटर के ऊपर, नीचे या फिर बराबर में कहीं से भी किया जा सकता है। इसे कंडक्टर रेल भी कहते हैं। इसी में करंट प्रवाहित होता है। देश में बेंगलुरु, कानपुर और नागपुर में पावर सप्लाई के लिए थर्ड रेल का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां यह मेट्रो की दाहिनी पटरी के समानांतर बिछाई गई है।

मेट्रो कोच और स्टेशन पर लगी लिफ्ट के रुकते समय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा वापस मेट्रो की इलेक्ट्रिक सप्लाई की लाइन में जा सके, इसके लिए मेट्रो के कोच में ही पहियों के पास से उपकरण लगाए जा रहे हैं। मेट्रो कोच अपनी यात्रा के दौरान जितनी बार भी रुकेगा तो ब्रेक लगने से उत्पन्न हुई ऊर्जा को पहिए के पास लगे उपकरण इसे वापस लाइन में भेज देंगे। पूरे ट्रैक पर बहुत सारी मेट्रो एक साथ चलती रहेंगी। इनके रुकने से पैदा ऊर्जा बिजली के रूप में वापस इलेक्ट्रिक लाइन में पहुंचेगी और इसका उपयोग दूसरी ट्रेनों के संचालन में होगा। गौरतलब है कि राजधानी में मेट्रो का ट्रायल रन पूरा हो गया है। अब इसके कमर्शियल रन की तैयारी की जा रही है। इस दौरान थर्ड रेल तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। यानी अब मेट्रो पटरियों में प्रवाहित होने वाले करंट से दौड़ेगी। इसके ब्रेक से ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे मेट्रो के संचालन में 45 प्रतिशत तक बिजली की बचत होगी।

मेट्रो में पावर सप्लाई के लिए दो तरीके हैं। पहला है ओएचई का, जिसका प्रयोग आम ट्रेनों के लिए भी किया जाता है। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में मेट्रो में भी इसी का इस्तेमाल होता है। दूसरा तरीका है थर्ड रेल का। इसमें ट्रेनों की पटरियों के बराबर या बीच में एक और पटरी बिछाई जाती है। भोपाल में पटरियों के ठीक बगल में एक थर्ड रेल चलेगी जिससे मेट्रो को करंट मिलेगा। इसी थर्ड रेल से मेट्रो को करंट मिलेगा भी। और इससे ही मेट्रो अपने द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को वापस भेज देगी, जिसका उपयोग दूसरी मेट्रो कर सकेंगी।

ट्रेन में ब्रेक लगाने के दौरान बहुत सारी ऊर्जा निकलती है जो गर्मी के रूप में यूं ही बेकार हो जाती है। इस ऊर्जा को ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से संरक्षित किया जाता है। इसके तहत डीसी ट्रैक्शन मोटर ब्रेक लगने पर जेनरेटर की तरह काम करने लगता है। यह सिस्टम 15 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन में काम करता है। इंजन की गति के मुताबिक हर बार ब्रेक लगने पर 30 से 50 किलोवाट तक ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रणाली से यह ऊर्जा वापस थर्ड रेल में चली जाएगी। भोपाल मेट्रो के निदेशक (सिस्टम) शोभित टंडन का कहना है कि अभी तक इस ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं हो पाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि थर्ड रेल सिस्टम में ट्रेन की ब्रेकिंग से जो ऊर्जा पैदा होती है, वह डीसी फार्म में होती है। जबकि बाकी मेट्रो तंत्र अल्टरनेटिंग करंट (एसी) पर चलता है। इंजीनियरों ने इस कमी को दूर करते हुए खास इन्वर्टर की व्यवस्था की है, जो ट्रेन की ब्रेकिंग से पैदा होने वाले केवी 750 वोल्ट डीसी करंट को 33 एसी करंट में बदलकर फिर से सिस्टम में भेज देगी।

● **सिद्धार्थ पांडे**

आधुनिक प्रणाली का उपयोग

भोपाल मेट्रो का संचालन आधुनिक, सुरक्षित और हाईटेक तकनीक से होगा। अनअटेंडेंट आब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की सहायता से मेट्रो और प्लेटफार्म पर संचालन के दौरान हर वस्तु पर सुरक्षाकर्मी बारीक नजर रखेंगे। ऐसा कोई भी सामान जिसका कोई दावेदार नहीं होगा। उसे तुरंत ही प्लेटफार्म से हटाया जाएगा। डीरेलमेंट डिटेक्शन सिस्टम के जरिये ट्रैक पर किसी तरह की बाधा होने पर या मेट्रो ट्रेन के डीरेलमेंट होने पर तुरंत जानकारी मिलेगी। ऐसे में ट्रेन को समय पर रोका जा सकेगा। वहीं मेट्रो के संचालन का सिस्टम पूरी तरह से साइबर सिक्योरिटी से लैस होगा। ऐसे में इसे हैक करना लगभग नामुमकिन होगा। साथ ही इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर ट्रेन का संचालन सही रास्ते पर है। मेट्रो कई आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस होगी, जिसमें अनअटेंडेंट आब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और डीरेलमेंट डिटेक्शन सिस्टम के जरिये यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पांचों चुनावी राज्यों के बहाने लोकसभा की राह तैयार कर रही थी लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपना चेहरा सामने रखकर बड़ा दांव चल दिया, अब सवाल है कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस और उसकी छतरी के नीचे बिखरता इंडिया गठबंधन क्या करेगा?

चौबीस का चेहरा

आम चुनाव में करीब सवा सौ दिनों का वक्त है, जब दिल्ली की गद्दी का फैसला होगा। इन सवा सौ दिनों में कोई तस्वीर राजस्थान, मप्र और छत्तीसगढ़ में बदल जाए, ऐसा लगता नहीं है। इन तीन राज्यों में लोकसभा की कुल 65 सीटें हैं जिनमें से 61 भाजपा ने 2019 में तब जीती थीं जब 2018 में इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीती थी। अब तो तीनों राज्यों की सियासत ही पलट चुकी है। तीनों राज्यों में नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे कांग्रेस के तीनों इक्के हार गए। कांग्रेस के तीनों कद्दावर नेता अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल की हार ने कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी क्योंकि उत्तर भारत में सिवाय हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के पास कोई राज्य नहीं है। कांग्रेस हिंदी पट्टी के इसी हिस्से से सत्ता की सियासत से गायब हो गई। दक्षिण में कर्नाटक के बाद तेलंगाना में उसे जीत तो मिली, लेकिन वहां से दिल्ली का रास्ता निकलता नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जिस विचारधारा की पीठ पर सवार होकर कांग्रेस राष्ट्रीय विकल्प बनने की दिशा में बढ़ना चाह रही थी, उसे झटका लगा।

दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले या कहें आखिरी राजनीतिक प्रयोग जिस तरह कांग्रेस ने किया और सामने प्रधानमंत्री मोदी ने खुद के चेहरे को ही रखकर नायाब सियासी प्रयोग किया, उसने 2024 के चुनाव की इबारत अभी से ही लिख डाली। इसकी तीन वजह है। पहला, राहुल गांधी का ओबीसी कार्ड कांग्रेस पर ही भारी पड़ गया। दूसरा, भ्रष्टाचार के मुद्दे का असर लाल डायरी से महादेव ऐप और ईडी तक पहुंचा तो मारक हो गया। तीसरा, कमलनाथ के बजरंग बली से लेकर बागेश्वर प्रयोग ने बताया कि कांग्रेस का नरम हिंदूवाद भाजपा के हिंदुत्व को मात देने की हैसियत नहीं रखता। महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक का सवाल भी एकमुश्त हिंदू ब्लॉक वोट में गुम हो गया तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को जो ऑक्सीजन दी थी, उसकी उम्र भी मप्र में सबसे बुरी हार के बाद पूरी हो गई। यानी 2024 का रास्ता मोदी-शाह की बिसात के लिए इतना आसान हो चुका है कि अब विपक्ष के भीतर और देश के भीतर वे सारे सवाल जो कल तक तानाशाही का प्रतीक थे, अब जनादेश का जामा पहनकर भाजपा की चुनावी जीत का पर्याय बन चुके हैं।

याद कीजिए संसद के भीतर जब अडाणी कांड के बाद समूचा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगा रहा था तब अपने भाषण का अंत प्रधानमंत्री ने यह कहकर किया था कि देश देख रहा है एक अकेला कितने पर भारी है। सही मायने में संसद और सड़क दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी कितनों पर भारी पड़े, यह देश के भीतर उठते हुए मुद्दे और उसके बावजूद चुनावी जीत ने साफ-साफ दिखला दिया है। संसद के भीतर कॉर्पोरेट लूट से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर के मुकाबले रुपए की दर, कोर सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ, बढ़ती गरीबी-भुखमरी में पांच किलो मुफ्त अनाज सरीखे बहुतेरे सवालों के साथ जांच एंजेसियों का विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल वाले हालात; मणिपुर पर मोदी की चुप्पी और चुनावी बॉन्ड से लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना-राकांपा पर सुप्रीम कोर्ट की लंबी खामोशी; लेकिन संसद के भीतर सरकार को डिगा पाना तो दूर प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर भी कोई राजनीतिक आंच नहीं आई। उस पर चुनाव के वक्त रैलियों में प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को ही अपना हथियार भी बनाया और ढाल भी। फिर मुद्दा भ्रष्टाचार का हो या कॉर्पोरेट मित्रों को शह देने का, मुफ्त अनाज बांटने का हो या युवाओं की बेरोजगारी का, सबकुछ मोदी सरकार के अनुकूल कैसे होता चला गया और चुनावी जीत भी मोदी सरकार के गवर्नेंस और प्रधानमंत्री के चेहरे से जुड़ गई। तो 2024 का रास्ता कैसे आसान हो गया, अब इसे दोहराने की जरूरत नहीं।

ब्रांड मोदी की चमक फीकी नहीं पड़ी

तीन हिंदीभाषी प्रदेशों- मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। इस जीत से यह धारणा मजबूत हुई है कि चुनावी मैदान में ब्रांड मोदी ही पार्टी का तुरुप का इक्का है। भाजपा भले ही अपने आप को कार्यकर्ताओं की पार्टी कहती रही हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के दौर में अधिकतर मतदाता मोदी के नाम पर ही पार्टी को वोट देते हैं। इससे न सिर्फ अधिकतर राजनीतिक विश्लेषक, बल्कि उनके धुर विरोधी भी इत्तेफाक रखते हैं। उनके सियासी प्रतिद्वंद्वी आज खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं कि इस बार की जीत भाजपा या आरएसएस की नहीं, बल्कि मोदी की है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पार्टी या पार्टी की विचारधारा पर किसी नेता विशेष के व्यक्तित्व का भारी पड़ना कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में नेहरू और इंदिरा गांधी से लेकर माकपा में ज्योति बसु और तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी तक कई ऐसे कद्दावर नेता हुए जिनकी शख्सियत उनकी पार्टी से बड़ी बन गई। आज भी नवीन पटनायक, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जैसे अनेक नेता हैं जिनकी पार्टी का भूत, वर्तमान और भविष्य जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता से सीधा जुड़ा है, न कि उनके दलों की विचारधारा से। जहां तक भाजपा का सवाल है, वहां अटल बिहारी वाजपेयी युग से लेकर मोदी के दौर तक संगठन या सरकार में पार्टी की विचारधारा को ही सर्वोपरि समझा जाता रहा है। यह बात और है कि मोदी के शासनकाल से पहले भाजपा को अपने बल पर बहुमत कभी नहीं मिला था। अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उसे सहयोगी पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ता था।

विधानसभा के तीन राज्यों में भाजपा ने एकतरफा जीत हासिल की

मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की भारी जीत स्पष्ट संकेत दे रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी अपने पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़ देंगे। पार्टी को 350 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। भाजपा के मौजूदा गठबंधन सहयोगियों और नए सहयोगियों को जोड़ लें, तो बहुत मुमकिन है कि सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) 400 से ज्यादा सीटें अपनी झोली में डालकर राजीव गांधी के 1984 वाले 404 सीटों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दे। पांचवीं विधानसभा मिजोरम में जनादेश स्थानीय पार्टी के हक में गया लेकिन वहां भी भाजपा को तीन सीटें मिलीं जबकि कांग्रेस केवल एक जीत पाई है। कांग्रेस को इकलौती राहत दक्षिण में मिली, जहां उसने तेलंगाना की सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को निर्णायक मात दी और सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। कर्नाटक में भाजपा को हराने के बाद दक्षिण में कांग्रेस की यह दूसरी चुनावी जीत है। इन परिणामों के बाद कुछ लोग उत्तर-दक्षिण ध्रुव की बात करने लगे हैं। विभाजनकारी ढंग से ऐसी बात करना न सिर्फ नादानी है बल्कि खतरनाक दांव भी है। कांग्रेस को सबसे पहले ऐसे हितैषियों से दूर रहना होगा और इस तरह के आख्यानों से दूरी बनानी होगी। उत्तर में अब भी दर्जनभर से ज्यादा गैर-भाजपाई राज्य हैं और इनमें से एक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है।

दरअसल, राज्यों के चुनावी परिणाम ने कांग्रेस की जड़ों को हिला दिया है और जो इंडिया गठबंधन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल को विकल्प के तौर पर पेश करने को तैयार था, कांग्रेस की छतरी तले जमा होने को तैयार था, उसके सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि 2024 में वह पांच बरस पुरानी अपनी राजनीतिक जीत भी बचा पाएगा या नहीं। इसलिए ध्यान से देखिए तो चुनाव परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर अखिलेश यादव हों या केजरीवाल, दोनों ने कांग्रेस की हार को लेकर भाजपा से ज्यादा तीखे सवाल उठाए। कांग्रेस को कठघरे में तो शरद पवार और संजय राउत ने भी खड़ा कर दिया। यहां तक कि नीतीश कुमार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला भी मप्र में सपा के साथ समझौता न करने पर बिफर पड़े। लेकिन समझना यह भी जरूरी है कि सपा और आम आदमी पार्टी ही नहीं, वामपंथियों को भी किसी भी राज्य में आधा फीसदी से ज्यादा वोट नहीं मिले यानी नोटा के वोट से भी कम वाली स्थिति सपा, आप, जेडीयू, भाकपा, माकपा और ओवैसी तक की पार्टी की रही। चाहे अनचाहे कांग्रेस की हार ने इंडिया गठबंधन के उस सपने को बिखरने के कगार पर ला खड़ा किया जो कर्नाटक चुनाव के बाद तैयार हुआ था।

पांच राज्यों के चुनाव में जीत का कयास लगाकर इंडिया गठबंधन का ताना-बाना 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ही बनाया जाने लगा था। यानी सवाल राज्यों के चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव की जीत-हार का भी जोड़ा जाने लगा। इसलिए गांधी परिवार को दरकिनार करने वाले राजस्थान के अशोक गहलोत का कद बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। कांग्रेस का भरोसा इस कदर कुलांचे मार रहा था कि तेलंगाना के चुनाव प्रचार के आखिरी घंटे में रोड शो के वक्त राहुल और प्रियंका के साथ ट्रक पर गहलोत दिखाई देने लगे। यह एहसास हर किसी को था कि गहलोत जीतेंगे तो लोकसभा चुनाव में राजस्थान की भूमिका बड़ी होगी। यही आलम मप्र को लेकर पनपा। जीत के प्रति कमलनाथ इतना आश्वस्त रहे कि वोटिंग के अगले दिन वे दुबई रवाना हो गए और तमाम कार्यकर्ता जीत का राग ही अलापते रहे। दिल्ली में बैठा कांग्रेस आलाकमान उन्हीं लोगों से घिरा रहा जो गहलोत या कमलनाथ के पे-रोल पर उनकी वाहवाही दिल्ली दरबार में करने से चूकते नहीं।

ध्यान दीजिए तो चुनाव राज्यों में हो रहे थे, लेकिन सपने लोकसभा चुनाव को लेकर बुने जा रहे थे। इसलिए कांग्रेस के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे, लेकिन कांग्रेस के हक में वोटों की तादाद लोकसभा की तुलना में बेहतर जरूर रही। अगर इसे लोकसभा का ही सेमीफाइनल ये सोच कर माना जाए कि मोदी का चेहरा ही हर जगह सामने था जैसा लोकसभा में होता है, तो कुल पड़े वोटों में कांग्रेस को करीब ग्यारह लाख ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस को 4.91 करोड़ तो भाजपा को 4.80 करोड़ वोट मिले जबकि कुल 638 विधायकों में से भाजपा के 344 तो कांग्रेस के 233 विधायक चुने गए। इस लिहाज से सांसदों के आंकड़े को देखें, तो कुल 82 सांसदों में से भाजपा के 50 और कांग्रेस के 32 सांसद होने चाहिए, लेकिन हकीकत में भाजपा के 65 तो कांग्रेस के महज 6 सांसद हैं। यानी जो खेल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस खेलना चाह रही थी उसी खेल को राज्यों में खेलकर भाजपा ने 2024 का रास्ता अभी ही साफ कर लिया।

मोदी-शाह की जोड़ी भी इस हकीकत को समझ रही थी कि कांग्रेस का ध्यान राज्यों से ज्यादा लोकसभा चुनाव पर है और उसकी समूची रणनीति राज्यों में जीत मानकर मोदी सरकार की नीतियों को कठघरे में खड़ा करने की है- तो मप्र में जो 18 बरस की सत्ता-विरोधी हवा बहनी थी उसे थामने के लिए शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करना; राजस्थान में तमाम घोटालों के लेकर सचिन पायलट के निशाने पर कहीं वसुंधरा तो कहीं गहलोत का आना; तो अपने अनुकूल हालात बनाने के लिए यहां भी नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही सामने रखा गया और मोदी ने किसी हुनरमंद कारीगर की तर्ज पर सचिन पायलट के घावों को ही सहलाया। गुजरात और उप्र को जिस तरह अपनी जीत की राजनीतिक प्रयोगशाला में मोदी-योगी ने तब्दील किया उसमें मप्र तीसरा तो राजस्थान चौथा राज्य हो सकता है। अगर इन चार राज्यों (यूपी, गुजरात, मप्र, राजस्थान) में भाजपा की लोकसभा की सीटें देखें तो आधी जीत तो यहीं से हुई है। कुल 160 में से 140 सीट भाजपा ने जीती है। मतलब कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की शुरुआत ही 140 सीट से होनी है, इस पर राज्यों के चुनाव परिणामों ने मुहर लगा दी।

● **विपिन कंधारी**

5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरु हो गई हैं। भाजपा-कांग्रेस के साथ ही अन्य पार्टियों ने भी इस दिशा में काम करना शुरु कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अपनी गारंटी पर जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस भी विभिन्न गारंटियों के सहारे चुनाव जीतने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन ये पार्टियां यह भी जानती हैं कि असली गारंटी तो वोटर ही हैं। यानी चुनाव में वोटर जिसके साथ खड़ा रहेगा, उसी को जीत का ईनाम मिलेगा।

वोटर ही गारंटी

5 राज्यों के अहम चुनाव हो गए और भाजपा तीन राज्यों में अच्छी बढ़त के साथ जीत गई। दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कांग्रेस ने कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी अपना झंडा फहरा दिया और पूर्वोत्तर के मिजोरम में कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही नहीं चली, जहां जनता ने क्षेत्रीय दल जेडपीएम पर भरोसा जताया। देश के लिहाज से देखें, तो यह चुनाव 60-40 से भाजपा के पक्ष में रहा। कह सकते हैं कि देश ने मिला-जुला जनादेश दिया है। इन चुनाव नतीजों से जो लोग यह संकेत निकाल रहे हैं कि 2024 का चुनाव दक्षिण और उत्तर भारत के बीच होगा, वे गलत साबित हो सकते हैं। पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से देखें, तो हाल के वर्षों में मोदी-शाह की जोड़ी ने अपनी राजनीति का एक खास तरह का अपना इलाका विकसित किया है, जहां भाजपा बहुत ताकतवर है। लेकिन इसके बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि इस खास इलाके के बाहर भाजपा भी अनगिनत चुनौतियां झेल रही है, जिनमें दक्षिण (तमिलनाडु आदि), पूर्वी तटीय क्षेत्र (आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा) के साथ-साथ पश्चिमी तटीय क्षेत्र (कर्नाटक, केरल) में वह हाशिये पर है। ऐसे में एक बहुत संगठित और रणनीति से बनाया विपक्षी गठबंधन भाजपा के लिए गंभीर चुनौती पेश कर सकता है। भाजपा का थिंक टैंक जानता है कि तीन राज्यों में उसकी बड़ी जीत 2024 में उसके पूरा लोकसभा चुनाव जीतने की गारंटी नहीं देती। इन तीन राज्यों की कमोवेश सभी सीटें तो उसने 2019 में भी जीती थीं। ऐसे में अधिकतम वह 2019 का नतीजा ही इन तीन राज्यों में दोहरा सकती है। अपनी मजबूत भाषा और राजनीतिक चतुराई से हार को भी जीत जैसा बताने में माहिर प्रधानमंत्री मोदी ने इसलिए नतीजों की शाम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बार-बार यह कहा- इन नतीजों से साफ हो गया है कि देश की जनता भाजपा को चाहती है। मोदी का यह भाषण अपने कार्यकर्ताओं का हौंसला बढ़ाने और विपक्ष, खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, का हौंसला तोड़ने की एक मनोवैज्ञानिक कोशिश थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके इस जाल में फंसे होंगे, तो जरूर गहरी निराशा में गए होंगे; क्योंकि खुद उसके नेतृत्व ने इस तरह का मनोवैज्ञानिक जवाबी हमला भाजपा पर नहीं किया। देखें, तो सच यह है कि कुल पांच राज्यों में से दो में भाजपा हारी है। इसलिए देशभर का जनादेश उसको नहीं मिला है; जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में दावा किया था। हकीकत यह है कि भाजपा के वर्चस्व को कांग्रेस ने अब

जाति के चुनावी कार्ड के खतरे

इंडिया गठबंधन को जल्द अपनी रणनीति बनानी होगी। अब यह गिनवाने का कोई मतलब नहीं है कि हाल में विश्वकर्मा जयंती पर शुरू हुई विश्वकर्मा योजना की क्या प्रगति है या पांच राज्यों के चुनाव के ठीक पहले बड़े धूमधाम से शुरू हुई इस योजना की चर्चा चुनाव के दौरान क्यों नहीं हुई। अर्थव्यवस्था में अपने हुनर से योगदान देने वाली और आज की राजनीति में पिछड़ा या ओबीसी में गिनी जाने वाली जातियों के लोगों को उनके काम के लिए सुविधाजनक शर्तों पर पूंजी/ऋण उपलब्ध कराने वाली इस योजना को मोदी सरकार द्वारा विपक्ष के जातिवार जनगणना अभियान की काट के तौर पर पेश किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अदालती लड़ाई जीतकर अपने यहां जातिवार जनगणना कराने (और फिर उसके अनुसार आरक्षण का कोटा बढ़ाने) जैसे फैसले के बाद भाजपा बैकफुट पर लग रही थी। बिहार में तो उसने जातिवार जनगणना का समर्थन किया था, लेकिन विरोध भी उसकी तरफ से ही हुआ। जातिवार जनगणना कराने और उसके आंकड़े प्रकाशित होने के बाद जैसी प्रतिक्रिया बिहार, उत्तर भारत और देश में मिलती लग रही थी उससे नीतीश कुमार ही नहीं, कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी बहुत उत्साहित लग रहे थे।

दक्षिण में मजबूत चुनौती दे दी है। आज दक्षिण भारत में भाजपा कहीं भी सत्ता में नहीं है। लेकिन सिर्फ दक्षिण ही भाजपा की राजनीतिक चिंता में नहीं है। देश का राजनीतिक नक्शा बताता है कि भाजपा आज भी 1980 के दशक वाली कांग्रेस की तरह पैन-इंडिया जनाधार वाली पार्टी नहीं बन पाई है। कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां भाजपा का एक भी विधायक नहीं है। नहीं भूलना चाहिए कि देश में आज की तारीख में सिर्फ नौ राज्य ऐसे हैं, जहां भाजपा की अपने बहुमत वाली सरकार है। बाकी नौ राज्यों में उसकी सरकारें अन्य दलों के गठबंधनों के सहयोग से हैं। इनमें भी कुछ जगह उसकी अपनी सीटें नाममात्र की ही हैं। तीन राज्यों में हार के बाद कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए; लेकिन इसके लिए गंभीर देशव्यापी मुहिम चलाने या कानून के दरवाजे पर दस्तक देने जैसी कोई बात नहीं की। विरोध यदि दिखावे भर का हो, तो जनता उस पर विश्वास नहीं करती। ईवीएम एक ऐसी मशीन है, जिसकी विश्वसनीयता पर सत्ता में आने से पहले सबसे ज्यादा विरोध भाजपा का रहा है। पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने तो ईवीएम के इस्तेमाल को लोकतंत्र के लिए खतरा तक कहा था और बैलट पेपर से ही चुनाव की मजबूत वकालत की थी। बहुत-से लोग अमेरिका जैसे आधुनिक तकनीक वाले देश का उदाहरण देते हैं, जहां आज भी ईवीएम से नहीं, बैलट पेपर से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देश में कई बड़े लोग मानते हैं कि यदि संदेह है, तो ईवीएम की जगह बैलट पेपर से चुनाव करवाने में क्या दिक्कत है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद भाजपा उसके असर को बनाए रखने के लिए अंतरिम बजट लाकर तय समय से एकाध महीने पहले चुनाव करवाने की कोशिश कर सकती है। अनुच्छेद-370 खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय की मुहर भी भाजपा को देश में राजनीतिक लाभ दे सकती है। ऐसे में 2024 में प्रधानमंत्री मोदी यह नारा दे सकते हैं कि यह उनका आखिरी चुनाव है। लिहाजा जनता उन्हें एक और मौका दे। राजनीतिक रूप से यह एक मजबूत रणनीति होगी, जिसका सामना कांग्रेस के लिए सरल नहीं होगा। इसकी काट के लिए कांग्रेस को भी अपनी तरफ से जनता को कोई गारंटी देनी होगी। इंडिया गठबंधन का चेहरा अभी अस्पष्ट है। यदि यह गाठबंधन गति पकड़ता है, तो भाजपा को एक संगठित चुनौती दी जा सकती है। अन्यथा कांग्रेस के पास अकेले चुनाव में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसा करके वह दक्षिण के राज्यों में तो कमाल कर सकती है; लेकिन हिंदुत्व की पकड़ वाली मोदी-शाह की मजबूत पट्टी में उसे दिक्कत आएगी।

जाति का कार्ड कई राज्यों में किया गया प्रयोग

मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जाति के कार्ड का प्रयोग करने से पहले कांग्रेस को यह बुनियादी बात याद नहीं रही कि मंडल के एक बड़े नेता शरद यादव मप्र के होकर भी कभी वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। 1974 में पहला चुनाव जीतने के बाद वे लगातार उप्र और बिहार में ही जगह तलाशते रहे। मोहन प्रकाश राजस्थानी से ज्यादा बनारसी पहचान के लिए जाने जाते हैं। नारायण स्वामी, फुले, पेरियार और करुणानिधि का जीवन-संघर्ष और काम ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, अनूप मंडल, जगदेव महतो, राजनारायण, बीपी मौर्या, कांशीराम और अर्जुन सिंह भदौरिया जैसों का काम मुलायम सिंह, लालू यादव और नीतीश कुमार के उछल-कूद करने का आधार बना, बिहार में निरंतर चल रहे पैंतीस साल के पिछड़ा राज का आधार बना। बाद के नेताओं ने पिछड़ा गोलबंदी बढ़ाई और स्वाभिमान बढ़ाया, लेकिन न तो प्रशासन के स्तर पर बढ़िया काम किया न अपना जीवन सामान्य रखा। सब नए राजा-महाराजा बन गए, सबने परिवार से उत्तराधिकारी बनाया, सबने दौलत इकट्ठा की। इस चुनाव में अपने साथ जाति के सवाल को भी पिटवाकर राहुल गांधी (नीतीश तो सामने आए नहीं) और उनके भक्तों ने साबित किया कि उनको अब भी बहुत कुछ सीखना है।

इस परिदृश्य में भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्ष को अब अपने इंडिया गठबंधन पर जल्दी और गहराई से काम करने की जरूरत है। निश्चित ही कांग्रेस उसकी अगुवा होगी और सभी दलों को अपने अहम छोड़कर सीटों का तालमेल करना होगा। इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई बैठक में इस दिशा में काम हुआ भी है। कांग्रेस के पास अवसर है कि वह हिम्मत दिखाए और कुछ बड़े फैसले करे। उसके सभी सांसद चार महीने फील्ड में जाकर पार्टी को जमीन पर मजबूत करने का काम करें। राहुल गांधी के पास भी अवसर है कि वह भारत जोड़ो की एक और यात्रा शुरू करके अधिकतर राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दें। चार महीने चीजें बदलने के लिए कम नहीं होते। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि तीन राज्यों में हार की उसकी निराशा भी खत्म होगी और नई ऊर्जा से पार्टी कार्यकर्ता आगे बढ़ पाएंगे। यह चुनाव अपने आप में काफी विविधता लिए था। कांग्रेस ने सभी राज्यों- खासकर राजस्थान, मप्र और छत्तीसगढ़ में पूरी तरह अपने क्षेत्रीय क्षत्रपों अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल को आगे करके उन्हें पूरी छूट दी हुई थी। ये तीन नेता अपने हिसाब से सब चीजें तय कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तीनों राज्यों में चुनाव सभाएं भले कीं; लेकिन उनका रोल यहीं तक सीमित रहा। कहा जा सकता है कि इन तीन राज्यों में कांग्रेस की हार दरअसल राहुल गांधी या खड़गे की नहीं, इन तीन नेताओं की हार ज्यादा है। वैसे ही, जैसे तेलंगाना में रेवंथ रेड्डी की कड़ी मेहनत कांग्रेस की बड़ी जीत का आधार है। भाजपा ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे रखा था और अपनी रणनीति के मुताबिक उसने बहुत चतुराई से जहां-जहां भी हो सकता था, धार्मिक ध्रुवीकरण का कार्ड भी खेला। भाजपा इस रणनीति में इन तीन राज्यों में विजयी रही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे रखना भाजपा की एक और रणनीति का बड़ा हिस्सा था। इस रणनीति को अपनाकर भाजपा ने चुनाव के बाद अपने क्षेत्रीय क्षत्रपों के लिए मुख्यमंत्री पद की किसी भी दावेदारी का रास्ता भी बंद कर दिया। अर्थात् जीत के बाद मुख्यमंत्री तय करने की सारी ताकत भाजपा नेतृत्व ने अपने हाथ में ले ली।

● इन्द्र कुमार

कब खत्म होगा अवैध प्रवासियों का संकट?

देश के विभिन्न इलाकों में रह रहे अवैध प्रवासियों की समस्या के संकट में बदल जाने का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार के सामने उनके सही आंकड़े जुटाना मुश्किल हो गया है। विगत दिनों केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा देकर बताया है कि देश के विभिन्न इलाकों में रह रहे अवैध प्रवासियों के आंकड़े जुटाना संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग चोरी-छुपे देश की सीमा में दाखिल होते हैं, और अपना हुलिया और पहचान बदलकर स्थानीय लोगों में घुल-मिल जाते हैं। ऐसा करके वो अपनी पहचान छुपाने की हर संभव कोशिश करते रहते हैं।

मालूम हो कि इन दिनों सर्वोच्च न्यायालय नागरिकता कानून की धारा 6ए की वैधता पर सुनवाई कर रहा है जो असम में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों से संबंधित है। हाल ही में अदालत ने केंद्र सरकार से इससे संबंधित आंकड़े मांगे थे कि देश में 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 तक कितने बांग्लादेशी नागरिकों को असम में भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। साथ ही अवैध घुसपैठ रोकने के लिए अदालत ने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा था। शीर्ष अदालत की इस मामले पर केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग के पीछे अवैध प्रवासियों की नागरिकता से लेकर उनकी वजह से पैदा होने वाली अन्य समस्याओं पर उठते सवालों का हल निकालने की कोशिश है, मगर अदालत को दिए गए केंद्र सरकार के जवाब से इस समस्या की जटिलता का अंदाजा लगता है। सवाल का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि 1966 से 1971 की अवधि के संदर्भ में विदेशी न्यायाधिकरण के आदेशों के तहत 32,381 ऐसे लोगों का पता लगाया गया जो विदेशी थे। 25 मार्च 1971 के बाद भारत में अवैध तरीके से घुसे प्रवासियों के सवाल पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि अवैध प्रवासी बिना वैध दस्तावेजों के गुप्त तरीके से देश में प्रवेश कर लेते हैं। उनका पता लगाना और उन्हें हिरासत में लेना और निर्वासित करना एक जटिल प्रक्रिया है। ऐसे लोग देश के विभिन्न हिस्सों में छिपकर रह रहे हैं इनका सटीक आंकड़ा जुटाना संभव नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने एक विवादास्पद बात बोल दी। उन्होंने कहा कि असम भारत का हिस्सा नहीं रहा है। यह म्यांमार का हिस्सा था। उनके कहने का आशय यह है कि भारत तो खुद असम में घुसपैठिया है। संभवत: इसी मानसिकता के कारण जिन्ना के निजी सचिव मोइनुल हक चौधरी के समय से ही असम में जनसंख्याकीय आक्रमण चल रहा है। चौधरी ने जिन्ना से वादा किया था कि वह उन्हें चांदी की थाली में असम पेश करेंगे। बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम के दौरान और बाद में बंगाली हिंदू और मुसलमान दोनों का बड़े पैमाने पर असम राज्य में आगमन हुआ था। उनके आने के साथ ही संस्कृति, भाषा, राजनीतिक पहचान, जनसंख्या की संरचना, विद्रोह, जातीय हिंसा, सुरक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों ने असम और पूर्वोत्तर के लोगों के जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुररहमान ने अपनी पुस्तक पूर्वी पाकिस्तान; जनसंख्या और अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पूर्वी पाकिस्तान के पास अपने विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए और चूंकि असम में प्रचुर मात्रा में वन और खनिज संसाधन कोयला पेट्रोलियम आदि है, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए असम को अपने में शामिल करना बहुत जरूरी है। इसलिए तब का पूर्वी पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश के साथ सीमा पार से असम में अवैध तरीके से प्रवास की समस्या गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और जनसंख्या के बढ़ते बोझ का मुद्दा है। वास्तव में यह असमी समुदाय के सांस्कृतिक और सभ्यतागत गौरव को बचाने की बात है न कि केवल उसकी धार्मिक पहचान की।

भारत की बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय भूमि और नदी सीमा है। सीमा के दोनों ओर से लोगों में सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समानताएं बहुत हैं। बांग्लादेश से घुसपैठ के मुद्दे ने असम को कई दशकों से परेशान किया है। मुख्य रूप से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा उचित कदम उठाने में असमर्थता के कारण आज की तारीख में असम की भूमि का महत्वपूर्ण हिस्सा बांग्लादेशी नागरिकों के पास चला गया है। बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के इस अंतहीन प्रवाह के कारण ही असम आंदोलन की शुरुआत 1979 में निचले असम के मंगलदोई क्षेत्र में हुई थी। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में इसके परिणामस्वरूप 1985 में ऐतिहासिक असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। असम समझौते में उल्लेख किया गया है कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम में बसने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, बल्कि अवैध प्रवासी है। हालांकि समझौते के इस प्रावधान को अभी तक लागू नहीं किया गया है जो कभी ना खत्म होने वाली घुसपैठ की समस्या के पीछे एक मुख्य कारण रहा है।

● **बृजेश साहू**

1991 के बाद और बढ़ गई समस्या

वर्ष 1991 की जनगणना के बाद समस्या और बढ़ गई जब सीमावर्ती राज्यों असम और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का असामान्य रूप से उच्च विकास दर का एक भयंकर प्रतिरूप देखा गया। 1991 में असम और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर स्थानीय हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर से बहुत अधिक थी। 1991 तक असम में चार जिले ऐसे थे (धुरी, ग्वालपाड़ा, बरपेटा और हैलाकंदी) जहां मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था। 2001 में असम में 6 मुस्लिम बहुल जिले थे जो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बढ़कर 9 हो गए। असम की संस्कृति और समाज के ऊपर अप्रवास के भाषाई प्रभाव को भी हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि पिछले कई वर्षों में अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है, तदानुसार बंगाली मातृभाषा के रूप में घोषित करने की मांग करने वालों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। जब बांग्लादेश का गठन हुआ था तब असमिया और बंगाली बोलने वालों का प्रतिशत क्रमशः 60.89 प्रतिशत और 19.85 प्रतिशत था, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार असमिया बोलने वालों का प्रतिशत घटकर 49.4 प्रतिशत हो गया जबकि बंगाली भाषा बोलने वालों का प्रतिशत बढ़कर 27.91 प्रतिशत हो गया। ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत में अवैध घुसपैठ और प्रवासियों की वजह से कई स्थितियों में आंतरिक सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है।

बच्चों की दुश्मन बनी हवा

बच्चों की सेहतभरी जिंदगी के साल लगातार कम हो रहे

भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के कारण बच्चों की सेहतभरी जिंदगी के साल लगातार कम होते जा रहे हैं। किसी भी आयु वर्ग के मुकाबले बच्चे इसके सबसे बड़े शिकार हैं। यह देश की आर्थिक और सामाजिक खुशहाली पर गहरी चोट कर रहा है। गर्भ में पल रहे बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। जहरीली हवा के प्रभाव से न केवल जन्म के समय बच्चों में विकृतियां आ रही हैं, बल्कि इसके दीर्घकालिक असर ने उनका जीवन और भी कष्टमय बना दिया है। विशेषज्ञों ने हवा में बढ़ रहे इस जहर का बच्चों पर पड़ रहे प्रभाव की जांच की। हेल्थ रिसर्च डेटाबेस, पबमेड पर वायु प्रदूषण और बच्चे शब्दों की खोज (सर्च) की जाए तो 7,684 परिणाम मिलते हैं, जबकि साइंस डायरेक्ट नामक डेटाबेस में सर्च करने पर 29,538 परिणाम मिलते हैं। इनमें से हर परिणाम दिलचस्प है, जो एक गंभीर तस्वीर दिखाता है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का प्रभाव उनके गर्भधारण करने से पहले ही शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत पुरुषों और महिलाओं की गर्भधारण करने की क्षमता पर इन प्रदूषकों के प्रभाव से होती है। शोध से पता चलता है कि वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से महिलाओं में डिम्बग्रंथि (ओवारियन) रिजर्व प्रभावित होता है। विभिन्न वायु प्रदूषक एंटी-मुलरियन हार्मोन (एएमएच) को कम करते हैं जो महिलाओं में डिम्बग्रंथि रिजर्व का सूचक है। डिम्बग्रंथि रिजर्व कम होने से गर्भधारण करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के कारण बच्चों की सेहतभरी जिंदगी के साल लगातार कम होते जा रहे हैं। किसी भी आयु वर्ग के मुकाबले बच्चे इसके सबसे बड़े शिकार हैं। यह देश की आर्थिक और सामाजिक खुशहाली पर गहरी चोट कर रहा है। गर्भ में पल रहे बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। जहरीली हवा के प्रभाव से न केवल जन्म के समय बच्चों में विकृतियां आ रही हैं, बल्कि इसके दीर्घकालिक असर ने उनका जीवन और भी कष्टमय बना दिया है। विशेषज्ञों ने हवा में बढ़ रहे इस जहर का बच्चों पर पड़ रहे प्रभाव की जांच की। वायु प्रदूषण का जहरीला सफर गर्भ से शुरू होता है। गर्भावस्था के दौरान जब माएं प्रदूषित हवा के संपर्क में आती हैं तो गर्भ में पल रहे बच्चे को गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। यही हवा नवजात शिशु से लेकर किशोर तक को जीवनभर का बोझ का कारण बन जाती है। वायु प्रदूषण भारत सहित पूरे ग्लोबल साउथ (विकासशील एवं गरीब देश) में भयावह स्तर पर पहुंच चुका है। भारत इस बात के लिए बदनाम है कि वायु प्रदूषण के कारण दुनियाभर में जन्म के एक महीने के भीतर होने वाली शिशुओं की मृत्यु में से एक-चौथाई यहीं होती हैं।

स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रमाण और अच्छी तरह से डिकोड किए गए विज्ञान में उन जैविक मार्गों को परिभाषित किया जा चुका है, जिनके माध्यम से प्रदूषक शरीर में प्रवेश करते हैं और अंगों को प्रभावित करते हैं। इनसे न केवल शिशुओं को प्रभावित करने वाले निचले श्वसन संक्रमण का पता चला है, बल्कि जन्म के समय कम वजन और समय पूर्व जन्म के कारण बच्चों की सेहत पर होने वाले असर के तथ्य सामने आए हैं। जीवन के पहले पड़ाव में बच्चे बेहद नाजुक होते हैं, वायु प्रदूषण उनके जीवन को बेहद असुरक्षित बना देता है। खासकर गरीब घरों के बच्चों को इसका खतरा अधिक होता है। हवा में व्याप्त विषाक्त धूल कणों के संपर्क में आने वाली मां के गर्भ में पल रहे भ्रूण के जीवित रहने की संभावना कम हो सकती है। प्रदूषित हवा के कारण मृत बच्चे का जन्म, समय से पहले जन्म और जन्म के समय कम वजन जैसी घटनाएं हो सकती है। उन्हें बाद के जीवन में अंत: स्रावी (इंडोक्राइन) और चयापचय (मेटाबोलिक) के साथ-साथ मधुमेह जैसी कई बीमारियों का खतरा रहता है। यदि वायु प्रदूषण मां के श्वसन स्वास्थ्य पर असर डालता है तो गर्भ में पल रहे भ्रूण में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी का कारण भी बन सकता है।

गर्भाशय में फेफड़ों के खराब विकास से वायुमार्ग की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। वैज्ञानिक समझाते हैं कि कणीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर की वजह से माताओं की इम्युनिटी कम हो सकती है। समय से पहले या मृत बच्चे का जन्म या अविकसित दिमाग वाले बच्चे के जन्म का खतरा बढ़ सकता है। पैदा होने वाले कमजोर बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं और निचले फेफड़ों का संक्रमण (एलआरआई), दस्त, मस्तिष्क क्षति और सूजन, रक्त विकार और पीलिया के जोखिम का सामना नहीं कर सकते हैं। प्रदूषित हवा के जल्दी संपर्क में आने से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। यह मस्तिष्क व तंत्रिका संबंधी विकास, फेफड़ों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है और मोटापे का कारण बन सकता है। इसके अलावा मानसिक विकार पैदा हो सकते हैं, जैसे- ध्यान में कमी, कम बुद्धि, अविकसित दिमाग आदि। यहां तक कि बच्चों के फेफड़ों की कार्यक्षमता में स्थायी कमी हो सकती है, जिससे वे बड़े होने के बाद भी फेफड़ों की पुरानी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, जो उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

भारत में वायु प्रदूषण के प्रभाव से बच्चों की मृत्यु, गंभीर श्वसन संक्रमण, समय से पहले और मृत जन्म, स्टंटिंग, अनीमिया, एलर्जिक राइनाइटिस (हे फीवर) और दिमागी विकास जैसी बीमारियों के पुख्ता प्रमाण बढ़ रहे हैं। खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन का उपयोग करने वाले घरों में गर्भावस्था के दौरान माताओं और जन्म के समय कम वजन के शिशुओं के मामले सामने आ चुके हैं। वायु प्रदूषण की वजह से बच्चों के जीने और उनके भविष्य के अधिकार का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में हमें चेतने की जरूरत है और कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) में ऐसे कार्य शामिल करने होंगे, जो वायु प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को कम कर सकें।

● **अक्स ब्यूरो**

मोदी की गारंटी पर पूरा फोकस

छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों को पूरा करने में लगी है। गत दिनों विष्णुदेव साय की सरकार ने मोदी की गारंटी का तीसरा वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री साय ने अभनपुर के ग्राम बेंद्री में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल के धान के बकाया बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदेंगे। जरूरत पड़ने पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी की अवधि भी बढ़ाई जाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत हमने दो साल के बकाया बोनस के भुगतान का वादा किया था और इसे अटल बिहारी की जयंती सुशासन दिवस पर पूरा कर दिया गया है। हमारी कथनी-करनी समान है। प्रदेश ही नहीं पूरे देश ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। किसानों के बैंक खाते में बोनस की राशि पहुंच गई है। कई किसानों को तो दो लाख से अधिक की राशि मिली है। किसानों में बहुत खुशी है। हमने प्रदेश की जनता से जो भी वादा किया है, वे सभी वादे पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शपथ लेने के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में गरीबों के 18 लाख आवासों के निर्माण की मंजूरी दी। इससे उन लोगों को आवास मिल सकेगा, जो पिछले पांच साल में आवास से वंचित रहे थे। मोदी की गारंटी के अंतर्गत जो भी वादा हमने किया है। सभी वादे पांच साल के अंतर्गत पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की दूसरी गारंटी को भी पूरा कर दिया है। राज्य में अब 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदी जा रही है। वहीं, धान के लिए इस बार किसान को 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर किसानों को दो साल से लंबित 3716.38 करोड़ रुपए का धान का बोनस वितरित किया। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को देश में सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। रायपुर जिले के बेंद्री गांव में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बोनस की राशि वितरित की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। एक अधिकारी ने कहा, राज्य सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीद शुरू कर दी है। इसके लिए टोकन भी बांटे गए हैं। जिन किसानों ने अपना धान पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुसार सोसाइटियों में बेच दिया है, उन्हें धान की नवीनतम निर्धारित मात्रा के अंतर की राशि भी बेचने की सुविधा दी गई है। सरकार ने किसानों के खाते में 3716 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। यह पैसा सीधे किसानों के अकाउंट में पहुंचा। इसके साथ ही सरकार ने सुशासन दिवस के अवसर पर यह भी फैसला किया है कि इसी दिन सभी नगरीय निकायों में एक सप्ताह तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती नगरीय निकाय में अटलजी की कविता पाठ, अटल विचार संगोष्ठी, निबंध स्पर्धा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर सुशासन दिवस के अवसर पर राज्य के किसानों को खरीफ विपणन साल 2014-15 और साल 2015-16 की बकाया धान की बोनस राशि 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपए का भुगतान किया गया। धान उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना के लिए राशि का प्रावधान भी किया है।

प्रदेश की भाजपा सरकार गरीब परिवारों को नए साल यानी जनवरी 2024 से पांच सालों तक मुफ्त में चावल देगी। विष्णुदेव साय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ में भी गरीब परिवारों को अगले पांच साल तक निशुल्क चावल देने का निर्णय लिया है। इसके चलते उचित मूल्य दुकानों से गरीब परिवारों को नए साल से जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक चावल फ्री में मिलेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से प्रदेश के अन्त्योदय, प्राथमिकता, निशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के 67 लाख 92 हजार 153 पात्र राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निशुल्क चावल मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों पर आगामी 5 वर्ष जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक मासिक पात्रता का चावल निशुल्क वितरण किए जाने के तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय, प्राथमिकता, निशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के राशनकार्डधारियों को आगामी पांच वर्ष निशुल्क चावल वितरण कराने के निर्देश दिए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्त्योदय श्रेणी के 14 लाख 92 हजार 438, प्राथमिकता श्रेणी के 52 लाख 46 हजार 656, एकल निराश्रित श्रेणी के 37 हजार 708 और निशक्तजन श्रेणी के 15 हजार 351 राशनकार्डधारी जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्ष तक निशुल्क चावल वितरण से लाभांवित होंगे।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

अब इन गारंटियों पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने वादा किया है कि जो विवाहित महिलाएं हैं, उनके बैंक खाते में हर महीना एक हजार रुपए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत देंगे। इसके लिए भी हमने अनुपूरक बजट में प्रावधान कर दिया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कार्ड धारी परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देने का भी काम करेंगे। भूमिहीन कृषि मजदूरों को एक साल में दस हजार रुपए देने का काम करेंगे। विभिन्न विभागों के एक लाख रिक्त पदों को पूरी पारदर्शिता के साथ भरेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग तेंदूपत्ता को हरा सोना कहते हैं। हमारी सरकार तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक का भुगतान करेगी। इसके साथ ही संग्राहकों के लिए चरण पादुका सहित अन्य लाभकारी योजनाओं को निरंतर जारी रखा जाएगा। अब आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अब बीमारी के इलाज के लिए ऋण लेने, खेत बेचने की जरूरत नहीं होगी।

इलेक्शन मोड में सरकार

यह साल भी हर साल की तरह गुजरने वाला है। 2024 चुनावों के नजरिये से बड़ी हलचल वाला होने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद अक्टूबर के आसपास महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट, भाजपा और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट की मिलीजुली सरकार ने इस चुनाव के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया है। एक आरोप हाल ही में संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने सरकार पर लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने टमाटर घोटाला करके 35,000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा और आरएसएस पर टमाटर की कालाबाजारी करवाकर करोड़ों रुपए की इस लूट का आरोप लगाया। उन्होंने वंचित के सांगली में बिजली अधिग्रहण बैठक में खुले मंच से कहा कि हमें आरएसएस-भाजपा शासन के 10 वर्षों का हिसाब-किताब शुरू करना चाहिए। नरेंद्र मोदी एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक तानाशाह हैं। लोकसभा चुनाव तक वह एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। मोदी पत्रकारों के सामने जाकर जवाब देने से डरते हैं, क्योंकि पत्रकार उनसे ज्यादा होशियार हैं। वह बहुत डरपोक प्रधानमंत्री हैं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि जब व्यापारियों और सरकार की मिलीभगत हुई, तो टमाटर की कमी हो गई, दाम बढ़ा दिए गए, चुनाव का खर्चा निकाल लिया गया और दाम फिर गिर गए।

प्रकाश अंबेडकर ने जो आरोप महाराष्ट्र की जोड़-तोड़ की सरकार पर लगाए हैं, वो पिछले महीनों में महंगे हुए टमाटर को लेकर लगाए। जो टमाटर किसानों से 2 से 3 या बहुत हुआ तो 4 रुपए किलो खरीदा जाता था और बाजार में 10 से 15 रुपए किलो बिकता था, वो अचानक 200 रुपए किलो पहुंच गया था। इसके पीछे की कहानी और घोटाले की योजना कोई नई या लंबी नहीं है। बस व्यापारियों पर दबाव बनाकर उन्हें टमाटर को होल्ड करने को कहा जाता है और यह खेल बड़े आराम से हो जाता है। जब भी चुनाव पास आते हैं, तो हर सरकार और सरकार में बैठे मंत्री से लेकर संतरी तक खूब पैसा बटोरते हैं। तो खाली टमाटर से ही सरकार ने चुनावों के लिए पैसा नहीं जुटाया है, उसके लिए और भी रास्ते जरूर निकाले होंगे; क्योंकि आजकल चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग के नियमों को ध्यान में न रखते हुए करोड़ों से लेकर अरबों रुपए पार्टियां खर्च करती हैं और हर एक चुनाव में हर पांच साल में इसी तरह से जनता के सिर पर वो पैसे खर्चने का बोझ बढ़ता रहता है और हर साल महंगाई भी कमाई से ज्यादा बढ़ती रहती है। ऐसे कई मामले हैं, जिनमें पैसे को पार्टियां और उनके उम्मीदवार पानी की तरह बहाते हैं और फिर भी वो कभी गरीब नहीं होते। सरकार में आते ही वो और अमीर होते चले जाते हैं। यह तो रही पैसा जुटाने के एक तरीके की बात। महाराष्ट्र सरकार ने आगामी चुनाव जीतने के लिए दूसरा तरीका निकाला है- मराठों को ओबीसी दर्जे में लाकर आरक्षण देने का।

असल में महाराष्ट्र में सरकार गिरने के बाद भी अभी उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भाजपा के माफिक कमजोर नहीं हुई है। इसके लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण देने की बात दोहराई है। अभी इसी महीने महाराष्ट्र सरकार ने सभी प्रमुख मराठी समाचार पत्रों में पहले पन्ने पर विज्ञापन देकर महाराष्ट्र में एक हलचल पैदा कर दी है। मराठा आरक्षण की समय सीमा से ठीक पहले आया यह विज्ञापन महाराष्ट्र में चुनाव जीतने की जमीन तैयार करने के वास्ते है। किंतु इसमें मराठों की अपनी-अपनी मांगें भी हैं, जो सरकार के लिए सिरदर्द बन सकती हैं। एक-दो उदाहरण देखें, मसलन मराठवाड़ा के मराठा कुनबी जाति प्रमाण-पत्र मांग रहे हैं। दूसरी ओर मराठा आरक्षण के लिए कानूनी मोर्चे पर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के 2021 के मराठा आरक्षण को अमान्य करने के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने को तैयार भी हो गई है। सुनवाई कब शुरू होगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री शिंदे द्वारा स्थापित समिति ने आरक्षण पर रिपोर्ट सौंपने के लिए जनवरी तक का टाइम मांगा है। कुछ राजनेता मराठा आरक्षण को ओबीसी के तहत देने के खिलाफ हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी आबादी 52 फीसदी है। यह महाराष्ट्र का प्रमुख बीपी वोट बैंक है। इसलिए ओबीसी अपना दम दिखा रहे हैं और मराठों को ओबीसी के तहत आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं। अब सरकार मराठा आरक्षण का रास्ता निकालना चाह रही है, जिसमें उसकी नस दब भी सकती है। विपक्षी दल ऐसे ही किसी मौके की तलाश में है, जिसमें वो सरकार की नाकामी का फायदा उठा सकें। बाकी तस्वीर आने वाले दिनों में सामने आएगी।

● **बिन्दु माथुर**

मुंबई में नेतागिरी के दम पर कालाबाजारी

एक युवक उप्र से वर्ष 2004 में मुंबई आता है और ठीक 19 साल में न सिर्फ करोड़पति बन जाता है, बल्कि सोने और डायमंड के मुंबई के व्यापार में उसका पूरा दबदबा हो जाता है। दबदबा इतना कि बिना उसकी मर्जी के कोई सोने और डायमंड का बड़ा व्यापारी अपना धंधा नहीं कर पाता है। यह युवक कोई और नहीं, बल्कि मोहित कंबोज नाम का भाजपा नेता है। अभी कुछ महीने पहले ही एक खबर सामने आई थी कि सोने और डायमंड के कुछ व्यापारियों में से एक व्यापारी ने सरकार की राजस्व न चुकाकर भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से करीब 3,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली है और आजाद घूम रहा है। कालाबाजारी करने में ऐसे जितने लोग सफल हो रहे हैं, उनको मोहित कंबोज जैसे नेताओं की शह मिली है, जो अपना हिस्सा लेकर कालाबाजारी करने वाले सोने और डायमंड के व्यापारियों की भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं से पैठ कराते हैं। अभी हाल ही में मुंबई की एक अदालत ने भाजपा नेता मोहित कंबोज और कई अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को बंद करने की सीबीआई की रिपोर्ट खारिज की थी। मोहित कंबोज और इन दूसरे आरोपियों पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 103 करोड़ रुपए की गड़बड़ी करने का मामला चल रहा था, जिसे सीबीआई ने आरोपियों को जेल न भेजकर फाइल ही बंद कर दी।

वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म?

राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की सारी कोशिशें करने के बावजूद असफल रहीं वसुंधरा राजे के स्थान पर मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ ले ली है और अब राजे की राजनीतिक संभावनाओं पर चर्चा होने लगी है। भाजपा ने जब मुख्यमंत्री पद के लिए शर्मा के रूप में नए चेहरे को चुना तो तारीफ तो बहुत हुई और यह भी कहा गया कि इस चयन से आम कार्यकर्ता में यह विश्वास बढ़ा है कि हर समर्पित कार्यकर्ता कल किसी भी पद पर पहुंच सकता है। लेकिन यह भी सवाल उठा कि राजस्थान की सबसे मजबूत नेता वसुंधरा राजे अब क्या करेंगी? या पार्टी अब उनके लिए क्या सोच रही है?

सवाल इसलिए है कि वसुंधरा राजे प्रदेश की सबसे लोकप्रिय नेता हैं और फिर भी उनकी बजाय भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुना गया। 70 साल की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे न केवल राजस्थान बल्कि देशभर में अब भी लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके लिए पार्टी का क्या प्लान है, इस बारे में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने फिलहाल पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद मुख्यमंत्री पद न दिए जाने के बाद उनके भविष्य पर भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व राजे को पार्टी के भीतर या केंद्र सरकार में मौका दे सकता है।

राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रहने से पहले वसुंधरा राजे केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री रही हैं। वसुंधरा राजे दो बार दमदार मुख्यमंत्री रही हैं और फिलहाल भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 2014 में भाजपा जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सत्ता में आई तो वसुंधरा को केंद्र की राजनीति में आने के लिए कहा गया था, यह तब की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सबसे करीबी साथी अमित शाह देशभर में पार्टी का विस्तार कर रहे थे और साथ ही उस पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर रहे थे। मगर तब वसुंधरा ने इससे इनकार कर दिया था। फिर वह राजस्थान में पार्टी के नेताओं और विधायकों के बीच अपने वफादारों की फौज का विस्तार करती हुई राज्य में भाजपा को मजबूत करने के साथ ही खुद की जड़ें भी गहरी करती जा रही थीं। इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले जब उनको केंद्र में ले जाने की बात चली, तो उन्होंने खुद ही यह ऐलान तक कर दिया कि मैं राजस्थान से बाहर कहीं नहीं जाने वाली, मेरी डोली राजस्थान आई थी और अब मेरी अर्थी ही राजस्थान से जाएगी।

राजस्थान में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे के भविष्य का प्लान तैयार कर लिया था। राजस्थान की राजनीतिक समझ रखने वाले कहते हैं सन् 2018 में जब राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आई, तभी वसुंधरा राजे के बजाय भाजपा नेतृत्व ने उनकी जगह राजस्थान में नए नेतृत्व को आगे लाने का निर्णय कर लिया था। इसी कारण उनको दरकिनार करते हुए छोटे-छोटे प्रतिद्वंदियों को ताकतवर बनाया जाता रहा। जानकार कहते हैं कि इसके बावजूद राजनीतिक रूप से बेहद जिद्दी स्वभाव की वसुंधरा राजे अपने स्वभाव के मुताबिक राजस्थान में अपनी ताकत दिखाने के नुस्खे तलाशती रही और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की राह अपने स्तर पर मजबूत करती रहीं। हालांकि भाजपा नेतृत्व भी किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के अपने लक्ष्य पर अटल रहते हुए हर तरह से वसुंधरा को मुख्यधारा से दूर ही रखे रहा। फिर भी, भाजपा के नेताओं द्वारा बीच-बीच में जब-तब उनको राजस्थान से बाहर भेजे जाने की चर्चा चली, तो वह दृढ़ता से डोली और अर्थी वाला अपना लोकप्रिय जुमला उछालकर जिद पर अड़े रहने का संदेश देती रहीं और विधायकों व नेताओं का साथ व समर्थन भी जुटाती रहीं। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी वसुंधरा ने पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की, और हालांकि भाजपा आलाकमान ने उनके समर्थकों और विश्वासपात्रों को बड़ी संख्या में टिकट भी दिए, लेकिन उनके चेहरे पर वोट मांगने के बजाय कमल के निशान को पार्टी का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करते ही उन्हें दरकिनार करके भजनलाल शर्मा जैसे वसुंधरा राजे से बेहद अल्प राजनीतिक कद के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया। अब जब भाजपा ने राजस्थान में नेतृत्व का स्वरूप ही बदलकर वसुंधरा से फोकस शिफ्ट कर दिया है, तो सवाल किया जा रहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? राजनीति से जुड़े लोगों और राजनीतिक विश्लेषकों की इस मामले में अलग-अलग राय है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि भाजपा टैलेंट को जाया नहीं करती, किसी न किसी रूप में उनका उपयोग करती ही है।

इसी तथ्य के अनुरूप वसुंधरा राजे को केंद्र सरकार में या संगठन में कोई सक्रिय जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि, वसुंधरा राजे पार्टी से मिले किसी प्रस्ताव को स्वीकार करेगी या नहीं, इस पर अलग-अलग मत हैं। वसुंधरा राजे के एक करीबी का कहना है कि यह पूरी तरह से राजे के निर्णय पर ही निर्भर रहेगा कि वे दिल्ली से मिलने वाले किसी भी तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं या नहीं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बहुत संभावना इस बात की भी है कि केंद्र अपनी ओर से वसुंधरा राजे को कोई प्रस्ताव दे ही नहीं।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

सब कुछ मोदी और शाह पर निर्भर

हालांकि, यह भी तय है कि डोली और अर्थी वाला उनका दांव भजनलाल शर्मा को नेतृत्व मिलने के बाद अब ठंडा पड़ गया है और संभव है कि वे देश या दिल्ली में कोई सम्मानजनक पद लेकर तत्काल राष्ट्रसेवा में लग जाएं, या फिर लोकसभा चुनाव की प्रतीक्षा करे, ताकि चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री पद की संभावना जग सके। वसुंधरा राजे की राजनीति जानने वाले कहते हैं कि मप्र में शिवराज सिंह चौहान के, मैं अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, ये मेरा काम नहीं है... बयान के बाद वसुंधरा राजे पर भी ये दबाव बना है कि वे भी केंद्र से कुछ ना मांगें। हालांकि, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से वसुंधरा राजे के रिश्ते रहे हैं, तथा तीनों ही अपने-अपने स्तर पर राजनीतिक रूप से बेहद सख्त और लगभग अटल-अविचल रहने वाले हैं, उससे तो यह संभावना कतई नहीं है कि तीनों में से कोई एक भी झुकेगा। फिर, वसुंधरा राजे भी शिवराज सिंह की तरह ही मांगना तो पसंद नहीं करेंगी, यह सब जानते हैं। ऐसे में, सियासी शतरंज पर भले ही यह कहा जाता रहा हो कि राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है लेकिन जब संभावनाएं खुद ही भावनाओं का खेल बन जाए, तो राजनीति खेल से ज्यादा और कुछ भी नहीं होती। फिर भी कहना मुश्किल है कि वसुंधरा राजे के साथ खेल हो गया और उनका खेल खत्म हो गया है। लेकिन खेल की गेंद किसके पाले में है, यह भी साफ है।

मोहभंग या कुछ और?

अखिलेश यादव की नाराजगी से बचने का प्रयास तो नहीं

कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उप्र जोड़ो यात्रा से दूरी इसलिए तो नहीं बनाई है कि अखिलेश यादव को और ज्यादा नाराज होने से रोका जा सके? मप्र में अखिलेश यादव के साथ जो सलूक हुआ है, उसके बाद तो वो हद से ज्यादा चिढ़े हुए हैं। चूंकि उप्र जोड़ो यात्रा में दलित और मुस्लिम आबादी वाले इलाकों पर फोकस किया गया है, इसलिए अखिलेश यादव की नाराजगी तो बढ़ ही सकती है। जैसे केरल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अच्छे दोस्त होने के बावजूद सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को भी गुस्सा आया था, अखिलेश यादव की नाराजगी तो बनती ही है। दलित वोटर के करीब पहुंचने से तो मायावती को ही दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुस्लिम वोटर के पास कांग्रेस के जाने से अखिलेश यादव तो अपने वोट बैंक पर डाका डालना ही समझेंगे। वैसे भी 2022 के चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी को ही मिले थे। ऐसे में जबकि चुनाव राम मंदिर के माहौल में हो रहा है, अखिलेश यादव को ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद तो होगी ही, और वो ये भी जानते होंगे कि मायावती उसमें रोड़े डालने की कोशिश करेंगी ही। अब अगर कांग्रेस भी उसमें हिस्सेदारी कर ले तो भाजपा के लिए चीजें आसान हो जाएंगी और सीधा नुकसान अखिलेश यादव को ही होगा।

सहारनपुर से कांग्रेस की उप्र जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है, और पश्चिम उप्र के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कई इलाकों से गुजरते हुए ये यात्रा लखनऊ पहुंचकर खत्म होगी। यात्रा के दौरान 11 जिलों की 16 संसदीय सीटों को कवर करने की योजना बनाई गई है। यात्रा का रूट भी इस हिसाब से तैयार किया गया है कि मुस्लिम और दलित वोटर के पास पहुंचकर संपर्क साधा जा सके। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद और रामपुर जैसे 7 जिलों में कई जगह आधी आबादी मुस्लिम वोटर की है, जबकि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जैसे इलाकों में दलित वोटर भी अच्छी संख्या में हैं। कहने को तो यह उप्र में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की तैयारी से जुड़ा इवेंट है, लेकिन इस शुभारंभ अवसर पर न राहुल गांधी दिखाई दिए और न उप्र की प्रभारी प्रियंका गांधी। आखिर ऐसा क्यों? उप्र जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के हिस्सा लेने, न लेने की कहानी कांग्रेस नेता तकरीबन वैसे ही सुना रहे हैं, जैसे तेलंगाना चुनाव में सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार की संभावना जताई जा रही थी। सोनिया गांधी तो चुनाव प्रचार करने पहुंची नहीं, एक वीडियो संदेश जरूर भिजवा दिया था और सोनियम्मा का माहौल बनाने की कोशिश की गई।

दिलचस्प बात ये है कि राहुल गांधी भी उप्र कांग्रेस के नेताओं के सामने तेलंगाना को ही रोल मॉडल के रूप में पेश कर रहे हैं। अभी 18 दिसंबर को कांग्रेस मुख्यालय में उप्र कांग्रेस के नेताओं के साथ कांग्रेस नेतृत्व की एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में उप्र के नेताओं ने अब तक की चुनावी तैयारियों का अपडेट दिया, और आगे की तैयारियों की रूपरेखा भी पेश की। साथ ही, गांधी परिवार के साथ-साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को उप्र की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी दिया। मीटिंग में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस नेताओं को निराश न होने और मेहनत करने की सलाह दी, लेकिन वैसी मेहनत जैसी तेलंगाना के नेताओं ने की और कांग्रेस की सरकार बनवा दी। वैसे राहुल गांधी इस बात के भी पक्षधर दिखे कि कांग्रेस नेताओं को पहले मजबूत विपक्ष बनने का प्रयास करना चाहिए। राहुल गांधी ने भले ही उप्र के नेताओं की हौंसला अफजाई करने की कोशिश की हो, लेकिन उप्र कांग्रेस के नेताओं से वो काफी निराश भी नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने बताया कि उप्र के नेताओं में सेल्फ-मोटिवेशन की कमी है, बनिस्बत तेलंगाना के नेताओं के मुकाबले। तेलंगाना में लंबे समय से कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उप्र में ऐसे नेताओं की कमी है जो उस हिसाब से मेहनत करते दिखे हों। राहुल गांधी ने कहा कि उप्र में दिक्कत ये है कि वहां तीन ऐसे नेता नहीं हैं, जो मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हों। फिर राहुल गांधी ने बताया कि तेलंगाना में ऐसे चार कांग्रेस नेता थे जो मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे और उन्हीं नेताओं ने अपनी मेहनत से तेलंगाना में जीत का आधार तैयार किया। ऐसे में जबकि उप्र कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी के साथ-साथ मल्लिकार्जुन खरगे को भी उप्र से चुनाव लड़ने का सुझाव दे रहे हों, और उसके फायदे समझाए जा रहे हों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का उप्र से परहेज समझ में नहीं आ रहा है।

2022 के उप्र विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी की कोई दिलचस्पी नहीं देखने को मिली थी। उप्र से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले राहुल गांधी ठीक उसी वक्त पंजाब चुनाव में हद से ज्यादा सक्रिय देखे गए थे, क्या उप्र से दूरी बनाने की कोई बड़ी वजह 2019 में अमेठी की हार की भी हो सकती है? ये तो देखा ही जा चुका है कि अमेठी की हार के बाद राहुल गांधी लोगों को उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति में फर्क समझाने लगे हैं और 2024 के आम चुनाव से पहले तो उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति पर बहस और भी तेज हो चली है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उप्र में कुछ दिन गुजारे जरूर थे, लेकिन उसके बाद से तो लगता है जैसे दक्षिण की राजनीति में भी उनको मजा आने लगा है। शायद इसलिए भी क्योंकि वायनाड से सांसद होने के साथ-साथ कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है।

2022 के उप्र में चुनाव में प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आई थीं, लेकिन उसके बाद से वो दूर ही दूर नजर आ रही हैं। ये भी ठीक है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा या हाल के विधानसभा चुनावों की व्यस्तता भी एक वजह रही हो, लेकिन उप्र जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना तो कर ही सकती थीं। अगर सोनभद्र, हाथरस और लखीमपुरखीरी जाने के लिए प्रियंका गांधी धरने पर बैठ सकती हैं, तो उप्र जोड़ो यात्रा से दूर रहने का सही तर्क समझ में नहीं आता है। आखिर उप्र जोड़ो यात्रा से प्रियंका गांधी के दूर रहने की क्या वजह हो सकती है? वो तो उप्र की प्रभारी भी हैं। ऐसे में जबकि कांग्रेस विपक्ष को साथ लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, आखिर प्रियंका गांधी को उप्र की फिक्र क्यों नहीं है? ये ठीक है कि अजय राय को प्रियंका गांधी का भरोसेमंद नेता माना जाता है, लेकिन इतने बड़े इवेंट से दूरी बना लेना क्या कहा जाएगा, कहीं प्रियंका गांधी का राजनीतिक दायरा बढ़ाने के लिए उप्र से दूर तो नहीं किया जा रहा है?

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

राजनीति को नई दिशा देने बेताब

अब से ठीक तीन साल पहले बिहार में बदलाव को लेकर जिन चार चेहरों में होड़ लगी हुई थी, उनमें दो चेहरे तो अब भी दमखम के साथ मैदान में डटे हैं। तीसरा जनता को जागरूक करने के अभियान में जुटा है। पर, चौथा चेहरा सियासत के दांव-पेंच से ऊब कर फिलवक्त नेपथ्य में चला गया है। ये चारों चेहरे थे- आरजेडी के तेजस्वी यादव, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, नवगठित द प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी और अभी जनसुराज यात्रा पर बिहार का भ्रमण कर रहे प्रशांत किशोर। हालांकि प्रशांत किशोर के मन में बिहार बदलने की इच्छा पिछले साल से ही जागृत हुई है।

वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में विदेश से दो विषयों में पीजी की पढ़ाई के बाद बिहार को बदलने का जज्बा लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी अचानक अवतरित हुई थीं। सियासी मैदान में उनकी एंट्री भी अनोखे अंदाज में रही। एक सुबह बिहार के छोटे-बड़े तमाम अखबारों के पहले पूरे पन्ने पर छपे विज्ञापन के जरिए पुष्पम प्रिया ने राजनीति में एंट्री मारी थी। अपने ज्ञान, काले रंग के ड्रेस और अंदाज-अदा से वे भीड़ तो आकर्षित करती रहीं, लेकिन ईवीएम में भीड़ का एकांश भी नहीं दिखा। जिसे जीतना था, लोगों ने उसे जिता दिया। तब से पुष्पम प्रिया नेपथ्य में हैं। कभी-कभार उनके संदेश 'एक्स' पर जरूर आते हैं, लेकिन राजनीति में रूचि होने के बावजूद उसमें फिर चुनावी अखाड़े में उतरने के संकेत नहीं मिलते।

पुष्पम प्रिया के पिता प्रो. विनोद कुमार चौधरी जेडीयू के पूर्व एमएलसी थे। इसी साल उनका निधन हुआ है। नीतीश कुमार से उनके अच्छे संबंध रहे। निधन के बाद नीतीश शोक प्रकट करने उनके घर भी गए थे। उन्हीं की बेटी हैं पुष्पम प्रिया। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले अखबारों में बड़ा विज्ञापन देकर अपनी द प्लूरल्स पार्टी का उन्होंने खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित किया था। पुष्पम प्रिया की पढ़ाई लंदन में हुई, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने जिस दमदार अंदाज में राजनीति में एंट्री ली, वैसा दमखम फिर कभी नहीं दिखा। इसकी वजह शायद यह रही कि 43 सीटों पर खड़े उनकी पार्टी के उम्मीदवार बुरी तरह मात खा गए। खुद पुष्पम प्रिया ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था। दोनों पर हार हुई। एक सीट पर तो उन्हें नोटा से भी कम 1500 वोट मिले थे। उन्होंने दस साल में बिहार को बदलने का वादा किया था।

पुष्पम प्रिया के ठीक उलट प्रशांत किशोर हैं। राजनीति में तो वे बाद में आए। उससे पहले उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए काम किया। उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति से दूसरे दलों को जिताते-जिताते अब खुद जीत का जज्बा पाल लिया है। पुष्पम प्रिया और प्रशांत में फर्क यही है कि एक ने कामयाबी का सपना देखना पहली बार में मिले झटके के बाद छोड़ दिया तो दूसरे की आंखों में सपना अब भी आकार लेने के अंदाज में दिख रहा है। प्रशांत का मानना है कि जब वे नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को चुनाव जिता सकते हैं तो खुद की पार्टी खड़ी कर वे क्यों नहीं जीत सकते। हालांकि प्रशांत ने थोड़ी समझदारी से काम लिया है। उन्होंने पहले जनसुराज नाम का एक संगठन बनाया, फिर उसके बैनर तले 2 अक्टूबर 2022 से बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। वे जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक कर रहे हैं। उनको पहली बार में ही कामयाबी तब मिली, जब उनके समर्थन से सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार एमएलसी चुना गया। प्रशांत ने अब घोषणा की है कि अगर कोई उनकी पसंद का कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो उसे हर तरह की वे मदद देंगे। भविष्य में उनकी योजना जनसुराज को राजनीतिक पार्टी में तब्दील करने की है। गांवों की यात्रा में लोगों को मौजूदा राजनीति से वे आगाह करते हैं। उनका मानना है कि बिहार को बदलने के लिए नई सोच वाले युवाओं को आगे आना होगा। लालू-नीतीश के राजनीतिक युग से बाहर निकलना होगा।

प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि उन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए बतौर रणनीतिकार काम किया था। बिहार में वर्ष 2015 में उन्होंने नीतीश कुमार की जीत की रणनीति बनाई थी, जो कामयाब रही। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तीसरी बार भाजपा से कड़ी टक्कर के बीच जीत की रणनीति भी उन्हीं की थी। वे तो इस बात का भी दावा करते हैं कि उनका कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता। बंगाल में जब भाजपा की जीत के अनुमान लगाए जा रहे थे, उसके काफी पहले उन्होंने कह दिया था कि भाजपा डबल डिजिट से आगे नहीं निकल पाएगी। हुआ भी वैसा ही। उनकी जनसुराज यात्रा में सबसे अधिक निशाने पर होते हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का परिवार। इसलिए लोगों में यह संशय भी बना हुआ है कि वे कहीं भाजपा के लिए तो काम नहीं कर रहे।

बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अपना दमखम दिखाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था। उनका नारा बेअसर रहा। पार्टी को करारी शिकस्त मिली। हां, उनकी वजह से एनडीए में तब की साझीदार जेडीयू की हालत जरूर खस्ता हो गई। भाजपा के बराबर सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने के बावजूद जेडीयू को सिर्फ 43 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। अब तो उनकी पार्टी भी दो हिस्सों में बंट गई है। एक धड़ा चाचा पशुपति पारस संभाल रहे हैं तो दूसरे धड़े के नेता चिराग खुद बने हुए हैं। फर्क यही है कि दोनों धड़े अब एनडीए का हिस्सा हैं। एलजेपी के छह सांसदों में चाचा समेत पांच एक तरफ हैं तो चिराग अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं। उनकी राजनीतिक-सामाजिक सक्रियता अब भी बनी हुई है।

● **विनोद बक्सरी**

तेजस्वी बढ़ा रहे पिता लालू की सियासी विरासत

बिहार में रोजगार की भरमार लगा देने के वादे के साथ लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी को कामयाबी मिली थी, लेकिन तब जेडीयू और कांग्रेस के साथ आरजेडी का गठबंधन था। लालू यादव भी चुनाव में सक्रिय थे। तेजस्वी की पहली असल परीक्षा तो 2020 के विधानसभा चुनाव में हुई, जब जेल में होने के कारण लालू साथ नहीं थे। वाम दलों को जोड़कर तेजस्वी ने न सिर्फ महागठबंधन के कुनबे का विस्तार किया, बल्कि आरजेडी के चुनावी पोस्टरों से लालू-राबड़ी भी नदारद रहे। तेजस्वी के नेतृत्व में लड़े गए पहले चुनाव में महागठबंधन को बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन विधायकों की मामूली कमी के कारण वे सरकार बनाने से चूक गए। तेजस्वी ने अपना तेज इस रूप में भी साबित किया कि आरजेडी सबसे अधिक विधायकों वाला दल बन गया।

इमरान चुनाव से 'रन आउट'

अब अकेले पड़ गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री

फौज और इमरान की पार्टी के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि यदि अदालत किसी मामले में इमरान के साथियों को रिहा करने का हुक्म देती है तो दूसरे ही पल किसी और मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इमरान खान की कैबिनेट में रहे तमाम नेता या तो इमरान खान को छोड़ चुके हैं या फिर जेल में हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने वाला है। जो भी इमरान की पार्टी की ओर से पर्चा जमा करने जाता है या तो उससे पर्चे छीन लिए जा रहे हैं, या फिर उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 22 दिसंबर को देर शाम तहरीक-ए-इंसाफ के आंतरिक चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर पार्टी का वजूद समाप्त कर दिया है। ऐसे में अब इमरान खान के पास ना पार्टी रही और ना चुनाव चिन्ह। स्थिति कमोबेश 2018 वाली हो गई है। बस किरदार बदल गए हैं। तब नवाज शरीफ को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराकर इमरान खान को जितवाया गया था और अब इमरान खान को जेल में डालकर और अयोग्य ठहराकर नवाज शरीफ के लिए रास्ता आसान किया जा रहा है। अब इमरान की आखिरी उम्मीद अदालत से है, देखना यह है कि पाकिस्तान में कभी सबसे लोकप्रिय व्यक्ति रहे इमरान का अब क्या हश्र होता है।

क्रिकेटर से प्रधानमंत्री बने इमरान खान फिलहाल चुनावी मैदान में 12वें खिलाड़ी बन गए हैं। ना तो उनकी पार्टी चुनावी मैदान में उतर सकती है, ना ही उनका चुनाव चिन्ह बल्ला उनके साथ रहा और ना ही उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है। फिलहाल उनके सामने अंधेरा ही अंधेरा है। खुद जेल में हैं और उनकी पार्टी की मान्यता पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने खत्म कर दी है। इमरान खान क्रिकेट के मैदान से राजनीति में छलांग लगाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने और फिर राजनीति के हाशिये पर धकेल दिए जाने वाले पहले वे शख्स हैं जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान के दो-दो सेना प्रमुखों से लोहा लिया और यह कोशिश की कि परदे के पीछे से सत्ता चलाने वाली फौज सीमा और बैरकों तक सीमित रहे, लेकिन अपने इस प्रयास में ना सिर्फ वह फेल हुए, बल्कि खुद का ही सत्यानाश कर डाला। पाकिस्तान का मुकद्दर लिखते-लिखते खुद ही बेचारे बन गए। आज वह 100 से ज्यादा मुकदमों का सामना कर रहे हैं। इमरान खान के बनने और बिगड़ने की कहानी लगभग दो दशक पहले शुरू हुई, जब 2002 में वह पहला चुनाव लड़े थे। एक समय था जब वह पाकिस्तान के तानाशाह जनरल मुशर्रफ के भी करीबी थे। नवाज शरीफ का तख्तापलट कर जब मुशर्रफ 2001 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इमरान खान को अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाना चाहा। लेकिन तब इमरान ने मना कर दिया।

पाकिस्तान के लिए क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने वाले इमरान युवा पीढ़ी के हीरो बनकर उभरे और उस छवि को उन्होंने राजनीति में भुनाने का कोई अवसर जाने नहीं दिया। उन्होंने पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और चुनावी बेईमानी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया और आवाम को एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए उन्हें अवसर देने के लिए कहा। पाकिस्तान की सेना को भी शरीफ और जरदारी परिवार के बीच सत्ता बंटवारे के बदले किसी नए विकल्प पर विचार करने का ख्याल आया और इमरान के लिए जनरल कियानी के मन में विशेष प्यार जग गया और फिर येन केन प्रकारेण इमरान खान को सत्ता सौंपने का निर्णय सेना ने कर लिया। 2018 में पाकिस्तान में आम चुनाव होना था और उसके पहले इमरान खान के लिए मैदान तैयार करना जरूरी था, लिहाजा सेना और पाकिस्तान की अदालतों ने मिलकर सबसे पहले नवाज शरीफ को ना सिर्फ प्रधानमंत्री पद से हटवाया, बल्कि उन्हें पनामा केस के एक मामले में फंसाकर आजीवन चुनाव लड़ने के अयोग्य भी ठहरा दिया। सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को बहुमत नहीं मिला तो स्पेशल प्लेन करके तब के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने अलग-अलग जीते पार्टियों के सांसदों को इस्लामाबाद लाकर इमरान खान को समर्थन दिलवाया और आखिर उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बिठा ही दिया।

नया पाकिस्तान बनने के बजाय इमरान खान के काल में पाकिस्तान डूबने लगा। एक तरफ एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा और दूसरी तरफ कोरोना और अन्य कारणों से अर्थव्यवस्था बैठने लगी। हालात दिवालिएपन की हो गई। जो इमरान खान यह कहकर सत्ता में आए थे कि मर जाएंगे, लेकिन आईएमएफ से कर्ज नहीं लेंगे, उन्हीं इमरान खान ने कर्ज के लिए अपने वित्तमंत्री बदल दिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रमुख बदल दिया और कर्ज की शर्तों को पूरा करने के लिए आवाम को मिलने वाली गैस और बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ा दिए। अब सेना का इमरान खान से मोहभंग हो गया था। जनरल बाजवा ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ मे ले ली। जाहिर है इमरान खान से टकराव शुरू हुआ और उसके परिणामस्वरूप खान की प्रधानमंत्री के पद से विदाई तय हो गई। इमरान ने सत्ता में बने रहने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। नेशनल एसेम्बली में अपने खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव को गैरकानूनी करार करवा दिया। लेकिन जब बात नहीं बनी तो इमरान खान ने जनरल बाजवा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले यह बयान दिलवाया कि अमेरिका की शह पर उनकी सरकार गिरवाई गई है। पाकिस्तान में एक इम्पोर्टेड सरकार बनवाई जा रही है। इसके लिए उन्होंने अमेरिका से पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजा गया एक साइफर का हवाला दिया। जनता के बीच में कोरे कागज को लहराकर उसे साइफर होने और उसमें उनके खिलाफ साजिश की बात को मुद्दा बनाया। परंतु जब इमरान की कैबिनेट बैठक में साइफर को लेकर कुछ ऐतराज का ऑडियो सामने आया तो इमरान खान ने उसे अमेरिका के बजाय जरनल बाजवा का षड्यंत्र बता दिया। मार्च 2021 में इमरान को आखिर सत्ता छोड़नी पड़ी और वहीं से उनके दुर्दिन शुरू हो गए। इमरान खान इस समय अडियाला जेल में हैं। उनके खिलाफ तीन बड़े मामले हैं। एक तो साइफर का मामला है, जिस पर अडियाला जेल में ही सुनवाई हो रही है। दूसरे उन पर पाकिस्तान के सरकारी खजाने से सामान चुराकर बेचने का मामला है, जिसे पाकिस्तान में तोशाखाना का केस कहते हैं।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

mycem cement

HEIDELBERGCEMENT

mycem power

Trusted German Quality

Over 150 Years

Send 'Hi' 7236955555

समस्याओं का समाधान भागवत गीता में

आज के समय में जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, जिनसे हम सुबह-शाम जूझ रहे हैं। आज व्यक्ति कदम-कदम पर पर्सनल, प्रोफेशनल और कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। जीवन के सही ढंग को अपनाकर कैसे इन समस्याओं का सामना करें, इसके उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि श्रीमद्भगवत गीता में हर समस्या और परेशानी का समाधान मिलता है। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करने के लिए जो ज्ञान दिया उन्हें गीता के 18 अध्यायों में कवर किया गया है। आज हम श्रीमद्भगवत गीता से कुछ ऐसे टिप्स लेंगे जिन्हें अपनाकर आपका जीवन भी आसान हो जाएगा।

लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी- गीता के अनुसार जिंदगी में सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति क्रियान्वित होना। अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कई लोग जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और यदि उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो वे अपना लक्ष्य बदल लेते हैं। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि अपना लक्ष्य निर्धारण करने के बाद कड़ी मेहनत करना चाहिए और उस पर फोकस बनाए रखना चाहिए।

कर्म है आवश्यक- जब भी कोई काम करने का सोचते हैं तो हम उसके पहले परिणाम पर विचार करते हैं। गीता में कहा गया है कि काम करने से पहले उसके परिणाम पर विचार नहीं करना चाहिए जबकि उस प्लान या उस विचार को एक्जीक्यूट करने पर फोकस चाहिए।

परिवर्तन संसार का नियम- जब भी किसी इंसान के जीवन में दुख आता है, तो वह उसी दुख का दुखड़ा हर समय रोने लगता है। जबकि गीता में समझाया गया है कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, हमेशा परिवर्तन होते रहेंगे। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जैसे हमारी खुशी एक समय तक ही रहती है वैसे ही दुख भी एक समय तक ही रहेंगे और समय आने पर फिर परिवर्तन होगा।

सत्य की होती है जीत- हमने कई बार सुना है कि जो गलत या झूठा होता है वह आगे बढ़ जाता है और सच को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन श्रीकृष्ण कहते हैं कि सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। हमें हमेशा सही काम करना चाहिए और जिस भी काम को हम करें उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, देर-सवेर हमें सफलता जरूर मिलेगी।

सब कुछ किसी कारण से होता है- श्रीकृष्ण कहते हैं कि हर काम, हर परिस्थिति, हर घटना के पीछे कोई न कोई ठोस कारण होता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप सफल हो रहे हैं तो इसके पीछे भी जरूर कोई कारण है। हमें अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए।

मनुष्य जन्म ईश्वर का एक अमूल्य उपहार है। संसार में इससे अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। जिसने इसे पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। मानव शरीर बड़े भाग्य और पुण्य कर्मों के फल से प्राप्त होता है, इसलिए मानव जीवन संसार की सभी वस्तुओं में सबसे अनमोल है। संसार के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है। यह जीवन ईश्वर की रचना का सबसे सुंदर और सर्वोच्च प्रमाण है।

मानव शरीर ईश्वरीय रचना का अद्भुत नमूना है। मनुष्य को छोड़कर सभी प्रजातियां अधूरी हैं। किसी का भी संपूर्ण विकास नहीं हुआ है। यह ईश्वर की कृपा है कि उसने हमें सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ उपाधि मनुष्य जन्म दिया है, अन्यथा हम न जाने कहां-कहां और किन-किन योनियों में भटकते रहते! मनुष्य योनि से पतित होकर प्राणी पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष आदि योनियों को प्राप्त करता है। मनुष्य जीवन की महिमा का जितना बखान और गुणगान किया जाए उतना कम है। सभी शास्त्रों और महापुरुषों ने इस मानव शरीर की महत्ता और विशेषताओं का गुणगान किया है। कहा जाता है कि असंख्य योनियों में मनुष्य जन्म सर्वोच्च योनि है। कई योनियों को पार करने के बाद जीव को नृत्य करने का अवसर मिलता है। इस शरीर को भगवान का वरदान माना जाता था। यह जीवन अत्यंत दुर्लभ एवं अमूल्य है। इसका हर पल और हर सांस करोड़ों में भी नहीं पाई जाती।

यदि किसी मनुष्य के पास सब प्रकार का सुख-संपत्ति हो, परंतु शरीर में श्वास न हो तो सब व्यर्थ है। एक बार यह जीवन हाथ से निकल गया तो समझो कि आप अनेक जन्मों और युगों के चक्र में पड़ गए। मानव जीवन अनंत यात्रा का एक ऐसा पड़ाव है, जिस पर पहुंचकर हम आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं।

मानव शरीर पाकर आत्मा मोक्ष व ईश्वर-प्राप्ति की अधिकारी बन जाती है। इस शरीर में आत्मा उन्नत अवस्था को प्राप्त करती है। ईश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया है। आपको उठने, सावधान रहने, सुधार करने और सर्वश्रेष्ठ बनने का सुनहरा अवसर दिया गया है। मानव जीवन कर्म सुधार एवं आत्मोत्थान का स्वर्णिम अवसर है। मनुष्य जन्म की अवस्था तक पहुंचकर हमने सभी प्राणियों से आगे बढ़कर बाजी जीत ली है। अब यह जीती हुई बाजी मत हारो। हमें अपने गुण, कर्म व स्वभाव को इस प्रकार बनाना है कि हम पुन: मानव शरीर पाने के अधिकारी बनें। यदि इस दुर्लभ मानव जीवन को समय रहते नहीं संभाला गया, इसका मूल्य नहीं जाना गया, इसे सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण ढंग से नहीं जिया गया तो उपनिषदों के शब्दों में महाविनाश होता है। इससे बड़ा कोई नुकसान और विनाश नहीं होगा। मनुष्य जन्म बार-बार नहीं मिलता। यह जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। अधिकांश लोग सांस लेते हैं और जीते हैं, लेकिन जीवन का पता नहीं चलता। आम आदमी अपना जीवन धन-संपदा, भोग-विलास और रोगों के संग्रह में व्यतीत कर देता है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हुए इस लोक और परलोक को संभाल पाते हैं।

● **ओम**

ये जिंदगी...

कभी जेठ की तपती धूप सी लगती
ये जिंदगी,
कभी सर्दियों की गुनगुनी धूप लगती
ये जिंदगी।
कभी कांटों में गुलाब का फूल सी
मुस्कुराती है ये जिंदगी,
तो कभी डूबते सूरज सी
लगती है ये जिंदगी।
कभी कल्पनाओं के सागर में
गोते लगाती है ये जिंदगी,
तो कभी सूरज की पहली किरण सी
लगती है ये जिंदगी।
कभी यथार्थ से दूर भागती है
हमारी ये जिंदगी,
कभी मौत के भय
बदहवास सी दौड़ती ये जिंदगी।
कभी चट्टान सी कठोर लगती
ये जिंदगी
कभी मोम सी कोमल लगती
ये जिंदगी।
कभी मंजिल के बहुत करीब
लगती है ये जिंदगी,
कभी एक-एक पल को
पीछे धकेलती ये जिंदगी।
कभी कीचड़ में कमल सी खिलती है
ये जिंदगी,
कभी धरती पर बोझ सी लगती है
ये जिंदगी।
क्या कहूं कैसी है ये जिंदगी
जैसी भी है
बहुत अच्छी है ये जिंदगी
ईश्वर की कृपा, प्रसाद है जिंदगी।

- कालिका प्रसाद सेमवाल

संकल्प

नहीं चाहिए मुझे किसी का सहारा।

मैं अपने बलबूते पर नशा मुक्ति अभियान चलाती रहूंगी।

मेरे देश के युवा शक्ति को नशे की गर्त में धकेलते इन देशद्रोही तत्वों को नेस्तनाबूत करूंगी।

दृढ़ संकल्प हैं यह मेरा।

उसके गगन भेदी आक्रोश से सबका मन व्यथित हो रहा था।

किसी को नहीं छोडूंगी। मेरे सत्यार्थी पति के हत्यारों को फांसी दिलवाकर रहूंगी।

युवाओं को नशे की गर्त में धकेलते बेईमानों को मैं छोडूंगी नहीं।

अंतिम सांस तक मुकाबला होगा।

बहुत कोशिश हुई उसकी आवाज दबाने की। उसे मौन करने की। न्याय की मांग करते पति के मृत्यु देख से भी न डगमगाए, बुलंद संकल्प लिए एक अकेली लड़ती रही। धीरे-धीरे कारवां बढ़ता गया। आज जब उसे न्याय मिला है, नशे के व्यापारियों को सजा मिली है, सारी दुनिया उसके साथ खड़ी है।

आत्मविश्वास से आगे बढ़ती नशामुक्ति आंदोलन की बागडोर संभाले वह आगे बढ़ी है।

- चंचल जैन

सम्मान से सम्मान

राजेश जी की बचपन से ही बड़ी इच्छा थी कि वे लगातार स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं में छपते रहें। उनकी लिखी रचनाओं पर सभा, संगोष्ठियों में चर्चा हो। उन पर समीक्षाएं लिखी जाएं। उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी, पर उनकी रचनाएं गिनी-चुनी पत्र-पत्रिकाओं और सहयोग राशि के बदले छपने वाली पुस्तकों तक ही सीमित रहीं। उन पर कोई चर्चा तक नहीं होती। बस वे अलमारियों की शोभा बढ़ातीं।

लगभग तीन साल पहले एक साहित्यिक समारोह में कुछ बड़े साहित्यकारों से मिलने के बाद उन्होंने अपने शहर में एक साहित्यिक संस्थान का गठन किया। जिले के कुछ नामचीन साहित्यकारों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद पर बिठाते हुए स्वयं संस्थापक सचिव-समन्वयक बने रहे। अब उनकी संस्थान जन-सहयोग से प्रतिवर्ष 1110/-, 2100/- एवं 5100/- के कुल 11 राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों, संपादकों को सम्मानित करती है, जिनके चयन के लिए गठित समिति में उन्हीं की चलती है।

अब तो राजेश जी की वही रचनाएं उन्हीं बड़े-बड़े पत्र-पत्रिकाओं में छपती हैं, जहां से वे खेदसहित एक बार लौट आई थीं। यही नहीं हर महीना-दो महीना में उन्हें देश के विभिन्न शहरों की साहित्यिक संस्थानों से सम्मानित करने की सचित्र खबरें फेसबुक पर देखने-पढ़ने को मिलती हैं।

पिछले दिनों एक फेसबुक पोस्ट से पता चला कि उनके साहित्य पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सात शोधार्थियों ने पीएचडी के लिए भी पंजीयन कराया हुआ है।

- डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा

खतरे में टेस्ट क्रिकेट का भविष्य

चुनौतियों का सामना कर रहा टेस्ट क्रिकेट

खेल का सबसे पुराना और पारंपरिक प्रारूप टेस्ट क्रिकेट, हाल के वर्षों में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। दर्शकों की संख्या में गिरावट और टी-20, टी-10 क्रिकेट जैसे खेल के छोटे प्रारूपों का उदय, टेस्ट क्रिकेट के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में टेस्ट क्रिकेट को दर्शकों की संख्या में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। टेस्ट क्रिकेट के प्रति राय और भावनाएं हर कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर बदलती रहती हैं, जिसमें इसे सर्वश्रेष्ठ प्रारूप कहे जाने से लेकर क्या टेस्ट क्रिकेट का अस्तित्व खतरे है तक शामिल है। टी-20 क्रिकेट जैसे खेल के छोटे प्रारूपों का उदय टेस्ट क्रिकेट का अंत है? कई प्रशंसक अब टी-20 क्रिकेट की तेज-तर्रार प्रकृति में अधिक रुचि रखते हैं, जो युवा दर्शकों के लिए अधिक आकर्षक है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जैसी टी-20 की फ्रेंचाइजी आधारित लीगों ने खेल के छोटे प्रारूपों की लोकप्रियता में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है।

टी20 क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के बीच अब दुनियाभर में टी-10 क्रिकेट को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए भारत में भी इस फॉर्मेट के मुकाबले शुरू होने की तैयारी जोरों पर है। यहां तक कि इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है और यह लीग अगले साल सितंबर-अक्टूबर में खेली जा सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन छोटे-छोटे फॉर्मेटों से एकदिवसीय और टेस्ट क्रिकेट का भविष्य खतरे में पड़ सकता है?

हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टी-20 क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के बीच अब दुनियाभर में टी-10 क्रिकेट मुकाबलों को मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस को देखते हुए भारत में भी इस फार्मेट के मुकाबले शुरू होने की तैयारी जोरों पर है। कहा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट के इस सबसे छोटे और नए फार्मेट की एक लीग शुरू करने पर विचार कर रहा है। यहां तक कि इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। अगर सबकुछ ठीक रहता है तो यह लीग अगले साल सितंबर-अक्टूबर में खेली जा सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन छोटे-छोटे फार्मेटों से सबसे बड़े टेस्ट और एकदिवसीय फार्मेटों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है? खेल विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरह खिलाड़ी वनडे क्रिकेट को छोड़कर टी-20 का रुख कर रहे हैं उससे एकदिवसीय क्रिकेट के भविष्य पर खतरे के बादल तो मंडराने लगे ही हैं, साथ ही टेस्ट के प्रति दर्शकों की उदासीनता से क्रिकेट के इस सबसे लंबे प्रारूप का अस्तित्व भी अंत की ओर बढ़ रहा है।

टी-20 की लोकप्रियता का आलम यह है कि इस समय 14 फ्रेंचाइजी लीग खेली जा रही हैं। साल के लगभग हर महीने में कहीं न कहीं फ्रेंचाइजी लीग हो रही होती है। कई स्टार खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़कर टी-20 का रुख कर रहे हैं। वे समय से पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं। साउथ अफ्रीका के फॉफ डुप्लेसिस इसकी बड़ी मिसाल हैं। वे लीग क्रिकेट में कप्तानी करते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए नहीं खेलते। इंग्लैंड के मोइन अली ने लीग क्रिकेट की खातिर ज्यादा समय निकालने के लिए टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। देखा जाए तो ये दोनों फैक्टर वाजिब साबित होते हैं और इसके आधार पर कहा जा सकता है कि वनडे और टेस्ट दोनों तरह की क्रिकेट खतरे में है। इस चिंता को कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी समय-समय पर जाहिर किया है। वर्तमान में पाकिस्तान के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर डेविड वार्नर के करियर की आखिरी टेस्ट सीरीज है। इस सीरीज के बाद वह अपने टेस्ट करियर पर विराम लगाने की घोषणा कर चुके हैं। उनके संन्यास लेने के बाद कंगारू टीम के लिए यह भूमिका कौन निभाएगा इस पर चर्चा जोरों पर है। इस बीच मिचेल मार्श ने इस स्थान पर बल्लेबाजी करने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिशेल मार्श ने कहा कि डेविड वार्नर के संन्यास लेने के बाद उनका टेस्ट क्रिकेट में पारी का आगाज करने का इरादा नहीं है। मार्श सीमित ओवरों की क्रिकेट में अमूमन शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करते हैं लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबी अवधि के प्रारूप में वह छठे नंबर पर ही बल्लेबाजी करना चाहते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि मौजूदा समय में युवाओं में टी-20 क्रिकेट का क्रेज है और वे सबसे लंबे प्रारूप की जगह फटाफट क्रिकेट को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा- मैं आने वाले समय में क्रिकेटरों को रेड-बॉल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखना पसंद करूंगा, क्योंकि यही वह विरासत है, जिसे आपको पीछे छोड़ना चाहिए। बहुत कम लोग हैं, जो ऐसा करने में सक्षम हैं और उनका लंबा करियर बिना टेस्ट क्रिकेट के बीत जाता है। इस समय सभी लीग क्रिकेट की ओर देखते हैं। खिलाड़ी सिर्फ लीग क्रिकेट के जरिए पैसा कमा रहे हैं और नाम कमा रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियाई टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस का मानना है कि मौजूदा समय में क्रिकेट के व्यस्त कार्यक्रम की वजह से खिलाड़ियों के लिए तीनों प्रारूपों में खेलना मुश्किल होता जा रहा है। यह एक खिलाड़ी के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कठिन होने वाला है। उन खिलाड़ियों को सलाम, जो इस समय तीनों फार्मेट खेल रहे हैं। यह खेल के लिए एक प्रतिबद्धता है, लेकिन यह बहुत कठिन है और मैं समझता हूं कि यह बदल रहा है। गौरतलब है कि जब से टी-20 क्रिकेट की शुरुआत हुई है, तभी से इसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर साफ पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में खिलाड़ी अपने कार्यभार को लेकर भी ज्यादा चिंतित हो गए हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने सिर्फ एक या दो फार्मेट में खेलने का निर्णय लिया है लेकिन कई तीनों प्रारूपों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को लेकर खेल पंडितों का कहना है कि क्रिकेट के शास्त्रीय प्रारूप माने जाने वाले टेस्ट को अगर बचाना है तो इसके लिए सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आप पर्याप्त संख्या में टेस्ट खेलें तो इसे कोई खतरा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि टी-20 प्रारूप ने क्रिकेट के कैलेंडर को एक तरह से दबाव में ला दिया है, लेकिन टेस्ट को इसमें फिट बैठाने के लिए प्रशासकों को उपाय करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना होगा कि हर टीम साल में पर्याप्त टेस्ट खेले।

● **आशीष नेमा**

आईफोन एक्स, कोरोना और आम आदमी

खुदा झूठ न बुलवाए, इस एक्स ने हमेशा से ही मुझे बड़ा परेशान किया है, बचपन एक्स फॉर एक्समस रटते-रटते निकल गया, अभी तक समझ नहीं आया क्रिसमस बोलूं कि एक्समस...। थोड़ी बड़ी क्लास में आए तो मैथ्स में एक्स ने भेजा घुमा कर रख दिया, बिना एक्स कोई सवाल ही नहीं, ये भी आज तक समझ नहीं आया कि मैथ्स में एक्स का क्या काम, सीधे-सीधे जोड़, घटा, गुणा, भाग से मैथ्स नहीं पढ़ा जा सकता क्या? फिर थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक मिस्टर एक्स साथ चिपक गए, जिसको भी मेरी बुराई करनी होती वो मिस्टर एक्स का नाम लेकर कर देता, ये कहते हुए कि, अरे वो जो कोई भी हो एक्स, वाय, जेड तुम तो इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हारे बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं... देखो आ गया न एक्स, आज तक पता नहीं चला मिस्टर एक्स हैं कौन जो मुझ में इतनी रूचि लेते हैं, बुराई करने वाला भी मजे में, बुराई की बुराई कर दो और पता भी न चलने दो किसने की... और अब ये...कल ही बेटा दनदनाता हुआ कमरे में आया, पापा, अब इस टन्डीरे से परेशान हो गया हूं मैं, मुझे भी अब एप्पल चाहिए।

मुझे समझा ही नहीं, फोन टन्डीरा है तो उसके लिए एप्पल क्यों चाहिए? मैंने कहा, उसमें क्या मुश्किल है तो, कल ही ले आऊंगा आते हुए बाजार से एप्पल...इसमें इतना भिनक क्यों रहा है?

उसे विश्वास नहीं हुआ आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोला,

सच्ची! आप सही कह रहे हैं?

मैंने कहा, लो इसमें सच-झूठ वाली क्या बात है...पहले कहता तो आज ही ले आता किलो दो किलो एप्पल... कोरोना है तो क्या हुआ एप्पल तो खरीद भी सकते खा भी सकते...

उसने सर पीटा, अरे मैं उस एप्पल की बात नहीं कर रहा, एप्पल आईफोन की बात कर रहा हूं...अब मुझे आईफोन चाहिए, मेरे सब दोस्तों के पास आईफोन है, एक मैं ही हूं जो इस टन्डीरे को साथ लेकर घूमता है...आपको पता भी है, कितनी शर्म आती है मुझे उन सबके सामने अपना ये फोन निकालते, और वो कितनी शान से निकालते हैं मेरे सामने अपना फोन जैसे वो राजा भोज, मैं गंगू तैली...।

मैंने कहा, ये क्या बात हुई आईफोन लेने से वो राजा भोज कैसे हो गए, फोन तो फोन है चाहे एप्पल हो या संतरा, स्मार्ट तो है ना, तू अपने आपको गंगू तैली समझता ही क्यों है?

उसने मुंह बनाया, कैसे न समझूं, उनका फोन 60, 70, 80 हजार का, मेरा फोन 9200 का, पता नहीं चलता क्या उनको भी कि मैं राजा भोज नहीं गंगू तैली हूं, जो सस्ता सा फोन लेकर घूम रहा है।

मैंने कहा, पहले मुझे तू ये बता कि कोरोना में तू बाहर गया कब, फ्रेंड्स से मिला कब, तुझे पता कैसे चला कि उनके पास आईफोन है?

वो बोला, पापा, आपको पता नहीं है क्या आजकल ऑनलाईन क्लासेस चल रही हैं ऑनलाईन वेबिनार हो रहे हैं, जूम पर, गूगल मीट पर सब प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें सब पता चलता है...जिसके पास आईफोन है न उसका नाम नहीं आता उसके फोन का नाम आता है... फिर कोरोना में बाहर निकलना बंद हुआ है, फोन से बात करना नहीं...ओह्ह, मैंने कहा, कोरोना में भी लोगों के पास पैसे बचे हैं, आईफोन लेने के कमाल है...! चल ठीक है एक काम कर तू भी ले ले एक सेकंड हैंड आईफोन...आ जाएगा तेरे भी फोन का नाम तेरे जूम पर...।

उसने अपनी एक हथेली पर अपनी ही दूसरी हथेली मारी, वही तो कह रहा हूं, आज है कल क्या पता हो न हो तो आज तो ढंग से जी ले, थोड़े अरमान पूरे कर लें, आईफोन से अपनी हैसियत बढ़ा लें... मैंने कहा, वाह बेटा, क्या कहने, अरे कल हो न हो तो कुछ ऐसा कर कि लोग याद रखें, तेरे आईफोन लेने से लोग तुझे याद नहीं रखने वाले...।

उसने भी धमकी दी, ठीक है, जब तक मुझे आईफोन नहीं मिलेगा मैं ऑनलाईन क्लासेस अटेंड नहीं करूंगा, न पढ़ाई पे ध्यान दूंगा...।

मैंने कहा, वाह मेरे नवाब साहब, ये धमकी देने के बजाय पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने पैरों पर खड़ा हो और खुद काबिल बन आईफोन लेने के... समझा!

उसने पलटवार किया, वही तो मै आपसे कह रहा हूं, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया पढ़ाई पे...जरा उस समय ढंग से पढ़ लिख लेते तो आज अपने बेटे को आईफोन दिलाने की हैसियत होती कि नहीं...।

मैंने कहा, मेरी छोड़ तू अपनी सोच, अपने कैरियर पे ध्यान दे फिर जितने चाहे आईफोन खरीद और रौब जमा...।

उसने कहा, आप आज मुझे आईफोन दिलाओ मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, कैरियर बनाऊंगा, तब तक कंपनी और नए फोन लॉन्च करेगी, वो मैं मेरे बच्चों को दिलाऊंग...।

वाह रे मेरे शेखचिल्ली... मैंने हाथ खड़े कर दिये...पर मैं क्या करूं, मेरे पास तो मेरे बच्चों की ये फालतू फरमाइशें पूरी करने के न पैसे हैं न इच्छा...।

उसने ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया...ठीक है, अब मैं घर पर रहने के बजाय बाहर जाऊंगा, न हाथ सैनेटाइज करूंगा, न मास्क लगाऊंगा, कोरोना हो गया और मैं मर गया तो लेकर बैठे रहना आप अपने पैसे और हैसियत दोनों...।

और हम जैसे लोअर मिडिल क्लास लोगों के तो दिल जिगर, गुर्दा, किडनी सभी खराब रहते हैं... कौन लेगा? न हमारा ऐसा कलेजा है जो इतने महंगे एप्पल का बोझ ले सके...पर इस बेटे का क्या करूं जो अपने आम बाप को अंबानी समझ एप्पल की जिद पकड़े बैठा है... जहां व्यक्ति की 10 एप्पल खरीदने की ताकत नहीं, वहां कंपनी ने एप्पल एक्स लॉन्च कर दिया है...कोरोना से पहले इस समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए कल ही एक ऑनलाईन सभा का आयोजन करूंगा... फिलहाल तो ये विचार कर रहा हूं कि ये एप्पल एक्स यानि 10 खरीदने के लिए किसे गिरवी रखू किडनी, दिल, जिगर या पूरा का पूरा मैं...चाहे कंपनी आईफोन एक्स लॉन्च करे या सरकार बजट या कोरोना एंट्री मार दे, आम आदमी को तो मूर्ख बनना ही है...चाहे कैसे बने... है न...।

● **डॉ. ममता मेहता 'पिंकी'**

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प

इस संकल्प ने हमारे मन-मानस
में गहरी जड़ पकड़ ली है

कोल इण्डिया लिमिटेड
विश्व की बृहत्तम कोयला उत्पादक संस्था
A Maharatna Company

प्रकृति के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है